ISSN-0971-8397

योजना

जुलाई 2015 | विकास को समर्पित मासिक | ₹ 10

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नये आयाम

भारत और पड़ोसः नयी आशाएं, नयी दिशाएं
अचल मल्होत्रा

भारत-अमेरिका संबंधः उभरती साझेदारियां
के सी सिंह

आर्थिक विकास के लिए राजनय
राम उपेन्द्र दास

सुशासनः सिद्धांत व व्यवहार
ए सूर्य प्रकाश

विदेशी धरती पर भारतीय सशस्त्र बलों का सबसे बड़ा राहत एवं बचाव अभियान

नेपाल में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की सेना एवं अन्य सशस्त्र बलों की ओर से चलाए गए 'ऑपरेशन मैत्री' में कुल 11,200 (780 मृतक भी शामिल) लोगों को निकाला या बचाया गया। सेना एवं वायुसेना ने बचाव अभियान के दौरान कुल 2,223 उड़ानें भरीं। शवों को निकालने और पीड़ितों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के साथ ही भारतीय सुरक्षा बलों की ओर से 17 हज़ार टन राहत सामग्री भी वितरित की गई। भारतीय सेना के रैपिड एक्शन मेडिकल टीमों ने 4762 लोगों को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई। मेडिकल टीमों ने 300 लोगों की कठिन सर्जरी भी की। इसके अलावा 216 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने और 4174 ओपीडी के मामलों का भी समाधान किया गया।

मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन के इस व्यापक मिशन की शुरुआत भारतीय सेना और वायुसेना ने भूकंप आने के दिन 25 अप्रैल से ही की थी, जबकि चार जून को यह अभियान पूरा हुआ। नेपाल में भूकंप से हुई भीषण तबाही के चार घंटों के भीतर ही भारतीय वायुसेना ने अपना मैराथन अभियान शुरू कर दिया था। वायुसेना ने इस अभियान में एक सी-130जे एयरक्राट, दो सी-17, एक आईएल-76 जैसे विमानों को लगाया था। इसके अलावा पीड़ितों को एयरलिफ्ट करने के लिए 295 एनडीआरएफ के जवानों को भी तैनात किया गया था। वहीं, मलबे में दबे लोगों की खोजबीन के लिए पांच खोजी कुत्ते भी लगाए गए थे।

एक महीने से अधिक समय तक चले 'ऑपरेशन मैत्री' के तहत भारतीय बलों ने बड़े पैमाने पर राहत सामग्री पहुंचाने का काम भी किया। सेना की ओर से पानी, कंबल, फील्ड हॉस्पिटल, टेंट, स्ट्रेचर, दवाइयां, पैकेट बंद खाना, दूध, बर्तन, सब्जियां, आरओ प्लांट, ऑक्सीजन जनरेटर, मरीजों के लिए बेड, एक्स-रे एवं लैबोरेटरी जैसी बेहद महत्वपूर्ण चीज़ें उपलब्ध कराईं। इसके अलावा मेडिकल टीमें भी अपने मोबाइल ऑपरेशन थियेटर के साथ पूरी मुस्तैदी से तैनात थीं।

वायुसेना ने इस मैराथन अभियान में हेवी लिफ्टर विमानों सी-130जे सुपर हरक्युलिस, सी-17 ग्लोबमास्टर, आईएल-76, गजराज और मीडियम लिफ्टर एएन-32 को भी लगाया था। इन एयरक्राट विमानों के अलावा वायुसेना ने एमआई-17वी5 औरएमआई-17 समेत आठ मीडियम लिफ्टर हेलीकॉप्टरों को भी इस ऑपरेशन में लगाया था।

एमआई-17वी5 और एमआई-17 हेलीकॉप्टरों की मदद से वायुसेना ने पोखरा और काठमांडू ज़िले में बड़े पैमाने पर राहत एवं बचाव कार्य को अंजाम दिया। इनमें से अधिकतर ऑपरेशन दोनों ज़िलों के सुदूरवर्ती गांवों में चलाए गए, जहां राहत सामग्री पहुंचाने और राहत कार्यों को अंजाम देने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। भारतीय बलों ने भूकंप प्रभावित सुदूर गांवों जैसे लुकला, ढाडिंग, मिलांची, गोरखा, चौतारा, चारीकोट, मेलम, अरोघाट, धुंचे, त्रिशूली, रामेछाप, बारपक, नारायण चौर, नामची बाज़ार, तातोपानी, लामाबगर आदि में बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया।

भारतीय सेना की इंजीनियर टास्क फोर्स ने भूकंप से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के निर्माण और उन्हें दुरुस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। टास्क फोर्स ने खासतौर पर बारपक, गोरखा और काठमांडू ज़िले के सुदूर इलाकों में रोड नेटवर्क को दुरुस्त करने का काम किया। जिसकी वजह से इन इलाकों में राहत एवं बचाव की सामग्री पहुंचाना आसान हो सका। भारतीय इंजीनियरों ने 16 किमी सड़क को दुरुस्त करने का काम किया। इसके अलावा 55 घरों और आश्रयस्थलों का भी निर्माण किया। यही नहीं मलबे में दबे शवों को भी निकालने का काम किया। राहत कार्यों में जुटे भारतीय सेना के पायलट घायलों और असहाय लोगों को निकालने के लिए लगातार उड़ान भरते रहे। यही नहीं दूर के इलाकों में बचाव अभियान चलाने के लिए वायुसेना ने 567 नेपाली सैनिकों को भी गांवों तक पहुंचाने में मदद की। सेना ने बचाव अभियान के दौरान 10 हज़ार कंबल, 1000 टेंट और 1000 तिरपाल भी मुहैया कराई।

इसके अलावा सेना की हिमालय रक्षा टीम ने भी भूकंप आने के तत्काल बाद बचाव अभियान शुरू कर दिया। टीम ने भूकंप के बाद हुए हिमस्खलन में फंसे तमाम पर्वतारोहियों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यही नहीं हिमस्खलन में दबे 18 शवों को भी कड़ी मशक्कत के बाद निकाला। इसके अलावा टीम के डॉक्टरों ने हिमस्खलन में फंसे लोगों को तत्काल इलाज भी मुहैया कराया। ❑

योजना

वर्ष:59 • अंक 7 • जुलाई 2015 • ज्येष्ठ-आषाढ़, शक संवत 1937 • कुल पृष्ठ:60

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित

प्रधान संपादक: दीपिका कच्छल
संपादक: ऋतेश पाठक
उपसंपादक: भुवनेश
संपादकीय कार्यालय
648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003
दूरभाष: 24365920,
ई-मेल: yojanahindi@gmail.com
वेबसाइट: www.yojana.gov.in
www.publicationsdivision.nic.in
http://www.facebook.com/yojanahindi
संयुक्त निदेशक (उत्पादन): वीके मीणा
व्यापार व्यवस्थापक: सूर्यकांत शर्मा
(प्रसार एवं विज्ञापन)
ईमेल: pdjucir@gmail.com
आवरण: जी. पी. धोपे

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 (दूरभाष: 24367260, 5610)
हाल सं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 (दूरभाष: 23890205)
701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर, नवी मुंबई-400614 (दूरभाष: 27570686)
8, एसप्लानेड ईस्ट, कोलकाता-700069 (दूरभाष: 22488030)
'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर, चेन्नई-600090 (दूरभाष: 24917673)
प्रेस रोड नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट, तिरुअनंतपुरम-695001 (दूरभाष: 2330650)
ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकल्प, एमजी रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001 (दूरभाष: 24605383)
फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलुरु-560034 (दूरभाष: 25537244)
बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना-800004 (दूरभाष: 2683407)
हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024 (दूरभाष: 2225455)
अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, अहमदाबाद-380007 (दूरभाष: 26588669)
के. के. बी. रोड, नयी कॉलोनी, कमान संख्या-7, चेनीकुटी, गुवाहाटी-781003 (दूरभाष: 2665090)

इस अंक में

संपादकीय 7

भारत और पड़ोस: नई आशाएं, नई दिशाएं
अचल मल्होत्रा 9

भारत-अमेरिका संबंध: उभरती साझेदारियां
के सी सिंह 15

भारत और चीन संबंध– बदलते रिश्ते
मनीष चंद 19

आर्थिक विकास के लिए राजनय
राम उपेंद्र दास 23

रक्षा समझौते: अंतर्राष्ट्रीय संबंध के वाहक
आलोक बंसल 27

क्या आप जानते हैं? 31

बहुपक्षीयता और क्षेत्रीय सहयोग: कुछ प्रश्न
दिलीप सिन्हा 33

तकनीकी युग में नए राजनयिक आयाम
पश्यंती शुक्ला 37

संभावनाओं से भरपूर 'एक्ट ईस्ट'
रहीस सिंह 41

मध्य-पूर्व की ओर संतुलित कदम
संजय राय 45

सुशासन: सिद्धांत व व्यवहार
ए सूर्य प्रकाश 49

महिला एवं बाल विकास: प्रगति की आस
पवन रेखा कुमारी 53

योग: दिलो-दिमाग को जोड़ने का मंत्र 58

पत्रिका मंगवाने हेतु, नयी सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें:

व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन), प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 48-53, भूतल, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिए हमारे विक्रय केंद्रों पर भी संपर्क किया जा सकता है।

- योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।
- योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।
- पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

दरें : वार्षिक: ₹ 100 द्विवार्षिक: ₹ 180, त्रिवार्षिक: ₹ 250, विदेशों में वार्षिक दरें: पड़ोसी देश: ₹ 530, यूरोपीय एवं अन्य देश: ₹ 730

आपकी राय

पर्यटन की शादार प्रस्तुति

पत्रिका 'योजना' के मई 2015 अंक में प्रकाशित आलेख 'पर्यटक ई-वीजा: आसान हुई पर्यटकों की राह', 'भारत में पर्यटन विकास: चुनौतियां व संभावनाएं', ज्ञानवर्धक लगा। वर्तमान समय में पर्यटन उद्योग की चर्चा प्राय: सभी प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में बराबर की जा रही है। बदलते सूचना प्रौद्योगिक के विकास से पर्यटन के क्षेत्र में नये-नये क्षेत्र विषय जुड़ते चले जा रहे हैं। नयी पीढ़ी का झुकाव पर्यटन की तरफ बढ़ रहा है। आव्रजन विभाग ने पर्यटक ई-वीजा पर आने वाले यात्रियों की सहायता के नौ हवाई अड्डों– दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोच्चि, तिरूवनंतपुरम और गोवा में 72 समर्पित काउंटर स्थापित किए हैं, लेकिन रांची (झारखंड), पटना (बिहार) और गया (बिहार) को नजरअंदाज कर दिया गया है। ई-पर्यटक वीजा से भारत में विदेशी पर्यटकों का आकर्षण बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा भारत में अधिक आएगी और रोजगार में वृद्धि होगी।

इस अंक में प्रकाशित आलेख 'ग्राम्य पर्यटन के खुलते दरवाजे' ने मुझे विशेष आकर्षित किया। भारत में करीब 15-20 वर्षों से कैरियर में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जब कम्प्यूटर आया तो चारों तरफ कम्प्यूटर की ही चर्चा होती रही है और भविष्य में भी होती रहेगी। अब समय आ गया है कि परिवार में मानसिकता का बदलाव भी जरूरी है। आज सूचना तंत्र बहुत विकसित हो चुका है। विदेशी पर्यटक पूर्णिया जिले के गांव में पहुंच रहे हैं। अमेरिका, आस्ट्रेलिया के अलावा देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं। बिहार के गांवों के नाम पर्यटन के बहाने अमर हो रहे हैं। पर्यटन के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। पर्यटन आने वाले दिनों में भारत का नक्शा बदल देगा।

अशोक कुमार ठाकुर
ग्राम-मालीटोल, पोस्ट- अदलपुर,
जिला-दरभंगा (बिहार)

सफलता का मंत्र

मैं ''योजना'' का 15 वर्षों से नियमित पाठक हूं और इसी पत्रिका के कारण मैंने कई क्षेत्रों में सफलता हासिल की। जैसे– विश्वविद्यालय स्तर की कई निबंध प्रतियोगिताओं में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। तत्पश्चात यूजीसी द्वारा कराए गए सेमिनार में मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए आलेख भी सराहे गए है। साथ ही साथ इसी पत्रिका के कारण भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, नई दिल्ली से सन 1992 में राष्ट्रपति स्काउट की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ और उस समय के राष्ट्रपति से राष्ट्रपति रोवर पुरस्कार प्राप्त किया। इसके साथ ही 2003 ई. में राष्ट्रीय मुख्यालय भारत स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता में सीनियर सेक्शन में द्वितीय स्थान प्राप्त किया और 2005 ई. में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह सारे पुरस्कार मैंने 'योजना' पत्रिका का अध्ययन कर ही प्राप्त किए है। इसलिए मैं इस पत्रिका का बेसब्री से इंतजार करता रहता हूं।

मई 2015 में विकास को समर्पित मासिक पत्रिका *योजना* में संपादक महोदय द्वारा लिखित संपादकीय 'सैर कर दुनिया की गाफिल' काबिलेतारिफ है।

इसी प्रकार से मनोज दीक्षित जी द्वारा *अवसंरचना और पर्यटन विकास* में *पर्यटक स्थल अनुभव* एवं तालिका 1 में भारत में विदेशी पर्यटकों का आवागमन, भारत में घरेलू और विदेशी पर्यटक, (2012-13) विकास दर शीर्ष 15 देशों से विदेशी पर्यटकों का आवागमन (2013), पर्यटन प्राप्तियां, भारत में रेल यातायात, भारतीय जल परिवहन, भारत में एयरपोर्ट को क्षेत्र या राज्य एवं नगरीय सार्वजनिक सुविधाओं का वर्णन किया है। वह वास्तव में पर्यटन करने वाले व्यक्तियों को लाभ मिलेगा एवं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र/छात्राओं को भी लाभ प्राप्त होगा।

इसी प्रकार, नानू भसीन एवं नवनीत कौर जी द्वारा लिखित आलेख ''पर्यटक ई-वीजा: आसान हुई पर्यटकों की राह'' में पर्यटक ई-वीजा को समझाने का कार्य किया है उसने वास्तव में गागर में सागर का कार्य किया है। कंचन शर्मा द्वारा भारत में पर्यटन विकास: चुनौतियां व संभावनाएं में पर्यटन क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रमुख प्रयासों के बारे में पाठकों को जो समझाने का कार्य किया गया है वह काबिलेतारीफ है।

जी. अंजनेय स्वामी द्वारा पर्यटन उद्यमिता: संभावित क्षेत्र एवं धीप्रज्ञ द्विवेदी द्वारा पर्यावरण, परिस्थितिकी और पर्यटन में

जिस प्रकार से उद्यमिता और पर्यावरण का समझाने का कार्य किया वह भी शानदार है।

क्या आप जानते हैं? शीर्षक में तरह-तरह के वीजा के बारे में जो जानकारी देने का जो कार्य किया गया है वह वास्तव में हम सभी पाठकों के लिए नयी जानकारी है। मैं इसके लिए संपादकीय मंडल का आभार प्रकट करता हूं। उमेश चतुर्वेदी द्वारा ''बौद्ध सर्किट बदल सकता है यूपी, बिहार की तस्वीर'' एवं विकास दिव्यकीर्ति जी द्वारा 'पर्यटन क्षेत्र से जुड़े सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दे' और 'यात्राएं जिन्होंने भारत को बदला' में लेखक संजय श्रीवास्तव जी द्वारा वर्णन किया गया है वह वास्तव में ज्ञान का भंडार बढ़ाने में सहयोगी है। अर्चना कुमारी एवं दिव्यांशु कुमार द्वारा भारत में शैक्षिक पर्यटन: अतीत, वर्तमान और भविष्य का वर्णन अच्छा है।

गिरीन्द्र नाथ झा जी द्वारा लिखा आलेख ''ग्राम्य पर्यटन के खुलते दरवाजे'' में पर्यावरण जागरूकता हेतु साईकिल यात्रा एवं ग्रामीण पर्यटन योजना का वर्णन किया है वह भी काबिलेतारीफ है। रत्ना श्रीवास्तव जी द्वारा 'लगातार बढ़ता धार्मिक पर्यटन', विकास पथ के माध्यम से डिजिटल इंडिया पहल, एवं प्रगति: बहुप्रयोजी, नियमोन्मुख बहुविध प्लेटफार्म तथा समयबद्ध क्रियान्वयन और पर्यटन विकास में भावी योजनाओं का जो वर्णन संपादक महोदय द्वारा किया गया है उसने वास्तविक रूप से धरातल पर रहकर समझाने का कार्य किया है।

सुजीत कुमार
''शांति निकेतन'' आर.एम.एस. कॉलोनी,
उर्दू बाजार, भागलपुर (बिहार)

उपयोगी जानकारियां

पत्रिका योजना का मई 2015 अंक मैंने पढ़ा जिसमें पर्यटन के बारे में बताया गया है। यह अंक मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस अंक में पर्यटन के साथ-साथ बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। जैसे–भारत में शैक्षिक पर्यटन, पर्यटन के सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दे, स्वास्थ्य पर्यटन आदि सभी आलेख में विभिन्न तरह की जानकारियां हैं। भारत में शैक्षिक पर्यटन का आधार तक्षशिला विश्वविद्यालय तथा नालंदा विश्वविद्यालय आदि रहे। यहां पर विदेश से छात्र-छात्राएं पढ़ने आते रहे हैं। इस अंक में ग्राम्य पर्यटन के बारे में लिखा गया जो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अभी लोग काम करने या अन्य दूसरे वजह से गांव से शहर की ओर आ जाते हैं। इस आलेख को पढ़ने के बाद लगा कि ग्राम्य पर्यटन एक अच्छा पर्यटन विकल्प है।

अधिकांश लोग जो शहर में रहते हैं वे अब पर्यटन के लिए गांव जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर शहर से ज्यादा आनंद मिलता है। ग्राम्य पर्यटन का आनंद गांव जाकर पक्की सड़क पर घूमने, पीली सरसों के खेत में घूमने, ट्रैक्टर पर घूमने आदि में है। भारत शैक्षिक पर्यटन के साथ-साथ धार्मिक पर्यटन स्थान भी हैं। इसी कारण यहां देश-विदेश के लोग घूमने आते हैं। इसीलिए भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा धार्मिक स्थानों का देश कहा जाता है। मई 2015 के अंक में एक आलेख स्वास्थ्य पर्यटन के ऊपर भी लिखा गया है। कई देशों के लोग भारत में स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं। भारत एक पर्यटन स्थल होने के कारण यहां पर विदेशी पर्यटकों का ईलाज भी होता है। विदेशी पर्यटक 30 प्रतिशत हृदय रोग के उपचार के लिए भारतीय चिकित्सा पर विश्वास करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि भारत की स्वास्थ राजधानी चेन्नई को कहा जाता है क्योंकि वहां पर अधिक मात्रा में विदेशी पर्यटकों का ईलाज होता है। अर्थात् स्वास्थ्य पर्यटन के क्षेत्र में भारत तरक्की की ओर बढ़ रहा है।

रिम्पी कुमारी
कालिंदी महाविद्यालय दिल्ली
विश्वविद्यालय, दिल्ली

मेक इन इंडिया: एक दूरदर्शी निर्णय

योजना के अप्रैल अंक में विनिर्माण क्षेत्र में विकास और चुनौतियों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के विविध पहलुओं से अवगत कराने के लिए धन्यवाद।

विनिर्माण आज के किसी भी अर्थव्यवस्था की वह बुनियाद है जिस पर किसी राष्ट्र के सुखद सपनों का महल खड़ा किया जाता है। विनिर्माण के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है, वह है- श्रम, पूंजी, जमीन और नवीन प्रौद्योगिकी परंतु दुर्भाग्यवश 125 करोड़ के युवा प्रधान वाले देश के पास न तो अपनी पूंजी है और न ही प्रौद्योगिकी। जिनके पास पर्याप्त पूंजी, प्रौद्योगिकी है उसे हम अपनी जमीन देना नहीं चाहते। ऐसे में 65 प्रतिशत युवाओं के नवीन महत्वकांक्षाओं को कैसे पूरा किया जाए, यह एक गंभीर चिंतन का विषय है और अपने देश में संकीर्ण मानसिकता के शिकार होते हैं।

इसी सवाल के प्रत्युत्तर में हमारे प्रधानमंत्री ने *मेक इन इंडिया* का नारा दिया लेकिन अफसोस कि बात ये है कि भूमि अधिग्रहण बिल पर देश के कुछ सियासतदानों ने संसद और संसद के बाहर जो हंगामा किया वह काफी दुखद रहा। अब देश के युवाओं को तय करना है कि उन्हें शिथिल नेतृत्व चाहिए या फिर दोनों आंखों से दूर तक देख सकने वाला कुशल नेतृत्व जिसमें 21वीं सदी के उभरते-उभरते भारत के सपनों को साकार की समता हो। इसलिए देश के युवाओं से अपील है कि–

राहों पे नजर रखो,
होठों पर दुआ रखो
आ जाए कोई निवेशक
इसलिए दरवाजा खुला रखो।

विभाकर झा, डी-311,
वेस्ट विनोद नगर, नई दिल्ली-92

निवेदन

योजना हमेशा द्विपक्षीय संचार में विश्वास रखती है। पाठकों से निवेदन है कि वह अपने राय व विचारों से हमें अवगत कराते रहें। साथ ही, पत्रिका में प्रकाशनार्थ आलेख भी हमें भेजे जा सकते हैं। पाठक हमें डाक द्वारा पत्र भेज सकते हैं। साथ ही आप अपनी सामग्री yojanahindi@gmail.com पर ईमेल के द्वारा हमें प्रेषित कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज योजना हिंदी पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी राय, सुझाव व सहयोग का इंतजार रहेगा।

–संपादक

दृष्टि The Vision

Most trusted & renowned institute among IAS aspirants

सामान्य अध्ययन

(फाउंडेशन कोर्स– 2016)

संध्याकालीन सत्र
निःशुल्क कार्यशाला

19 जुलाई, सायं 6:30 बजे

Not feeling confident in Current Affairs for UPSC??

Remove information overloading, Read genuine content in Drishti's "Current Affairs Today".

Monthly Magazine

Book your copy at the nearest book shop

For distribution/business enquiries- 8130392355

For preview & subscription visit: drishtiias.com

CSAT
120 days Programme

Test Series
(Mains/PT) For IAS-2015
General Studies & CSAT
Online Test Series also available

इतिहास
द्वारा
अखिल मूर्ति

भूगोल
द्वारा
कुमार गौरव

दिल्ली के अतिरिक्त हमारी कहीं कोई शाखा नहीं है। कुछ विद्यार्थियों ने हमें बताया है कि इंदौर आदि शहरों में कुछ संस्थाएँ हमारे नाम का अवैध प्रयोग कर रही हैं। विद्यार्थियों से निवेदन है कि उनके झाँसे में न आएँ।

641, Ist Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9 Ph.: 011-47532596, (+91)8130392354,56,57,58,59
E-mail:info@drishtiias.com, drishtiacademy@gmail.com * Website: www.drishtiias.com

YH-74/2015

संपादकीय

उदीयमान भारत

अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ कहते हैं कि किसी राष्ट्र के कद और भाग्य को सैन्य शक्ति से भी अधिक राजनयिक मोर्चे पर उसकी सफलता तैयार करती है। भारत के संबंध में यह बयान और भी अधिक सत्य है। एक ओर राष्ट्र के रूप में हमारी देशभक्ति की भावना की सभी सराहना करते हैं, दूसरी ओर शांतिप्रिय देश के रूप में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी बहुत निखरी है। साथ ही हमने सीमाओं की रक्षा करने वाले अपने जवानों का हमेशा अभिनंदन किया है, लेकिन राजनयिक मोर्चों पर भारत की उपलब्धियों की ओर हाल तक उतना ध्यान नहीं दिया गया, जितना दिया जाना चाहिए था। अब एक स्वागत योग्य परिवर्तन हो रहा है। मुख्यधारा का मीडिया तो पर्याप्त कवरेज दे ही रहा है, आम आदमी ने भी भारतीय राजनय की सफलता की गाथा पर ध्यान देना आरंभ कर दिया है। हालांकि वे कूटनीतिक शब्दों और वाक्यों की जटिलता नहीं समझते, लेकिन वे कूटनीतिक प्रयासों तथा राष्ट्र निर्माण में इसमें निहित लाभों को महसूस करते हैं और सराहना करते हैं।

उदारीकरण एवं विश्व व्यापार में तेजी से बदलते रुझानों ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत परिवर्तन किया है। स्वयं पर बहुत अधिक केंद्रित रहने वाली अर्थव्यवस्था से इसे वैश्विक रूप से एकीकृत अर्थव्यवस्था में बदलने के सफल प्रयासों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। पिछला एक वर्ष हमारे राजनयिक प्रयासों को वैश्विक सराहना मिलने का साक्षी रहा है। भारतीय राजनय ने बेहद सतर्कता अथवा संभले कदमों से सशक्त एवं सक्रिय कदमों तक की बड़ी छलांग लगाई है। यह सब तब आरंभ हुआ, जब प्रधानमंत्री ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में दक्षेस राष्ट्रों के प्रमुखों को आमंत्रित किया। विशेषज्ञों ने उसे कूटनीतिक तख्तापलट बताया। एक वर्ष की छोटी सी अवधि में ही प्रधानमंत्री की उन्नीस विकसित एवं विकासशील देशों की यात्रा ने हमारे विदेश संबंधों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए। यह वर्ष भारत द्वारा अपने पड़ोसी और उनके पड़ोसियों को प्राथमिकता दिए जाने का साक्षी बना। हमने विश्व की सभी प्रमुख शक्तियों के साथ अपने रणनीतिक संबंध और मजबूत किए हैं। भूकंप से तबाह नेपाल में फौरन बचाव तथा राहत कार्य सुनिश्चित करने में भारत की सक्रियता पर दुनिया भर का ध्यान गया। कई वर्षों से संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियान में हमने दुनिया में सबसे अधिक योगदान किया है।

दुनिया में दूसरे सबसे बड़े समुदाय के रूप में भारतीयों की उपस्थिति ने अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों को वांछित रूप से प्रोत्साहन दिया है। हाल के रुझान बताते हैं कि अब तक निष्क्रिय रहे देशों ने भी भारत के साथ संबंध मजबूत करने में बहुत रुचि प्रदर्शित की है। दुनिया में भारतीयों का सबसे बड़ा उच्च कौशल युक्त समूह होने के कारण कोई भी देश भारत को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और चीन को भी पछाड़ते हुए सबसे तेज विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है।

आर्थिक क्षेत्र, मानव संसाधन विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत की प्रगति ने दुनिया को उस बात पर ध्यान देने के लिए विवश कर दिया है, जो हम एक राष्ट्र के रूप में कहते हैं। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया। इसके साथ ही इसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से चुनौतीपूर्ण मांगों को और भी बढ़ा दिया है। किंतु भारत सतत प्रयासों और नीतिगत पहलों से इन चुनौतियों को पूरा करने में सफल रहा है। 1947 से 2015 तक, लगातार सशक्त होते हुए भारत ने अपना भाग्य रचा है और राष्ट्रमंडल में न्यायोचित स्थान प्राप्त किया है। हम आशा रखें कि वह दिन दूर नहीं, जब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाएगा, जो उसे बहुत पहले बन जाना चाहिए था। ❑

Career Launcher

सिविल सेवा अभ्यर्थी

सिविल सेवा परीक्षा 2016 के लिए सामान्य अध्ययन का इंटिग्रेटेड फाउंडेशन बैच

फाउंडेशन बैच में पंजीकरण कराने के लिए निकटतम् CL केंद्र पर संपर्क करें

सिविल सेवा परीक्षा 2016 में सफलता हेतु प्रत्येक शुक्रवार सामान्य अध्ययन की निःशुल्क कार्यशाला में भाग लें

मुखर्जी नगर	ओल्ड राजेन्द्र नगर
04:00 pm	10:00 am

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की अखिल भारतीय टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन एवं पेपर-पेन दोनों ही माध्यमों में उपलब्ध। तुरंत पंजीकरण करायें @ ₹5000

सिविल सेवा परीक्षा '13 के टॉप 10 में से 6 CL विद्यार्थी हैं

रैंक 1
गौरव अग्रवाल
CL पंजीकरण संख्या: 3540934

रैंक 3
रचित राज
CL पंजीकरण संख्या: 1035692

रैंक 6
साक्षी साहनी
CL पंजीकरण संख्या: 5293711

रैंक 8
जॉनी टी वर्गीज
CL पंजीकरण संख्या: 5293820

रैंक 9
दिव्यांशु झा
CL पंजीकरण संख्या: 4088566

रैंक 10
मेघा रूपम
CL पंजीकरण संख्या: 10017630

and many more...

CL | Civil Services Test Prep

www.careerlauncher.com/civils

/CLRocks

समसामयिकी घटनाओं की अद्यतन सूचना प्राप्त करने के लिए www.careerlauncher.com/civils/blog देखें।

दिल्ली CL सिविल सेवा के अध्ययन केंद्र

मुखर्जी नगरः 204/216, द्वितीय तल, विराट भवन/एमटीएनएल बिल्डिंग, पोस्ट ऑफिस के सामने, फोन – 41415241/46

ओल्ड राजेन्द्र नगरः 18/1, प्रथम तल, अग्रवाल स्वीट्स के सामने, फोन – 42375128/29

इलाहाबादः 19 बी/49, भूतल, कमला नेहरू मार्ग, यूनिवर्सिटी स्टेडियम गेट के सामने, मनमोहन पार्क चौराहा, फोन – (0)9956130010

YH-80/2015

भारत और पड़ोसः नई आशाएं, नई दिशाएं

अचल मल्होत्रा

किसी ने ठीक ही कहा है कि दुनिया की शुरुआत घर से होती है। व्यक्ति से परिवार, परिवार से पास-पड़ोस, पास-पड़ोस से समाज, समाज से राष्ट्र और राष्ट्र से विश्व की ओर संबंधों का विस्तार होता है। भारत की विदेश नीति भी इसी आधार पर काम करती दिख रही है। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में दक्षेस देशों के शासनाध्यक्षों को आमंत्रण, सत्ता संभालने के तुरंत बाद भूटान से विदेश यात्राओं की शुरुआत, आगे चलकर नेपाल व बांग्लादेश के साथ ऐतिहासिक समझौते आदि संकेत देते हैं कि भारत अपनी दुनिया की शुरुआत अपने पड़ोस से करना चाहता है और यह वक्त की मांग भी है

2014 के संसदीय चुनावों के बाद नई दिल्ली में सशक्त और स्थिर सरकार के उदय ने पड़ोसी देशों सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह संकेत दिया कि भारत को गंभीरता से लेने का वक्त अब आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रति अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने पिछले एक साल में दिल्ली में कई महत्वपूर्ण नेताओं की मेजबानी करने के अलावा, करीब डेढ़ दर्जन देशों की यात्राएं भी कीं। इस प्रक्रिया में, उन्होंने द्विपक्षीय या क्षेत्रीय अथवा बहुपक्षीय प्रारूप में दुनिया भर के सभी महत्वपूर्ण नेताओं से मुलाकात की और उनके साथ विचार-विमर्श किया।

सरकार के राजनयिक प्रयासों से यह अब तक बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि वर्तमान सरकार की विदेश नीति संबंधी प्राथमिकताओं में 'सबसे पहले पड़ोस' को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। पड़ोसी देशों तक पहुंच बनाने की दिशा में पहला कदम तो प्रधानमंत्री के औपचारिक तौर पर पदासीन होने से पहले ही उठा लिया गया था। पिछले साल 26 मई को प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए दक्षेस के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों को आमंत्रित किया गया। इस निमंत्रण को उपयुक्त रूप से मास्टरस्ट्रोक और साहसी कदम करार दिया गया और इससे एक स्पष्ट संकेत गया कि भारत की नई सरकार दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों एवं क्षेत्र की अखंडता को बेहद महत्व देती है। शपथ ग्रहण समारोह में क्षेत्र के सभी राष्ट्राध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों की उपस्थिति ने इस बात की पुष्टि की कि वे भी भारत की भावना का उसी के अंदाज में प्रत्युत्तर देने की मंशा रखते हैं। इस अवसर ने शुरुआती संपर्क स्थापित करने का बेहतरीन मौका दिया, इसके बाद यात्राओं के आदान प्रदान अथवा क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से इतर बैठकों का दौर प्रारंभ हो गया। कार्यकाल के प्रथम वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं में सात सदस्यीय दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (दक्षेस) के चार देशों (भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश) और चीन की यात्रा शामिल रही। राजनीतिक, सुरक्षा और सामरिक परिस्थितियों की वजह से दक्षेस के शेष तीन सदस्य देशों (अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव) की यात्राओं का कार्यक्रम बनाने में कुछ वक्त लग सकता है। इस बीच, अफगान राष्ट्रपति इस साल अप्रैल में भारत की यात्रा पर आए थे और भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नई दिल्ली में पाकिस्तान और मालदीव के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात की थी। संक्षेप में कहें, तो एक वर्ष के दौरान, प्रधानमंत्री ने पास-पड़ोस के समस्त नेताओं के साथ कम से कम एक बार मुलाकात की और कुछ के साथ तो एक से ज्यादा बार भी मुलाकात की।

क्षेत्र के कुछ विशिष्ट देशों के साथ भारत के रिश्ते क्या आकार ले रहे हैं, इस पर चर्चा से पहले दक्षिण एशिया पर एक क्षेत्र के रूप में नजर डालना उचित होगा। कम से कम यह तो कहा ही जा सकता है कि दक्षिण एशिया एक जटिल क्षेत्र है। इस क्षेत्र के देशों की साझा विरासत और ऐतिहासिक रिश्ते हैं। इसके साथ ही इन देशों के धार्मिक, जातीय, भाषायी एवं राजनीतिक ताने-बाने में विविधताएं भी

लेखक अमेरिका और जॉर्जिया में भारत के राजदूत रहे हैं। वह संयुक्त राष्ट्र तथा विएना स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारत के सहायक स्थायी प्रतिनिधि भी रहे हैं। संप्रति वह विदेश नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों के स्वतंत्र विश्लेषक हैं। वह समय-समय पर भारतीय विश्वविद्यालयों तथा विदेश मंत्रालय की विशिष्ट व्याख्यान मालाओं में विदेश नीति के मसलों पर व्याख्यान भी देते हैं। ईमेलः achal_malhotra@hotmail.com

परिलक्षित होती हैं। दक्षिण एशिया रक्तरंजित अंतर्राज्यीय युद्धों और गृह युद्धों का रणक्षेत्र रहा है, यह मुक्ति आंदोलनों, परमाणु प्रतिद्वंद्विता, सैन्य तानाशाहियों का साक्षी रहा है और मादक पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी से जुड़ी गंभीर समस्याओं के अलावा उग्रवाद, धार्मिक कट्टरपंथ एवं आतंकवाद से ग्रसित रहा है। धार्मिक सहिष्णुता के मापदंड पर, घटक देशों का दायरा लचीली धर्मनिरपेक्ष मानसिकता और कठोर रूढ़िवाद के बीच रहा है। दक्षिण एशिया को दुनिया का सबसे कम समानताओं वाला क्षेत्र माना जाता है। तीस वर्ष के अस्तित्व के बावजूद, दक्षेस ने बहुत ही धीमी और सुस्त प्रगति दर्ज की है। क्षेत्र में बहुत अर्से बाद सरकारों के लोकतांत्रिक स्वरूप ने कुछ जमीन हासिल करना शुरू किया है और कुछ देशों की आर्थिक वृद्धि दर में भविष्य के लिए कुछ सकारात्मक संकेत दिखाई दिए हैं।

दक्षिण एशिया को दुनिया का सबसे कम समानताओं वाला क्षेत्र माना जाता है। तीस वर्ष के अस्तित्व के बावजूद, दक्षेस ने बहुत ही धीमी और सुस्त प्रगति दर्ज की है। क्षेत्र में बहुत अर्से बाद सरकारों के लोकतांत्रिक स्वरूप ने कुछ जमीन हासिल करना शुरू किया है और कुछ देशों की आर्थिक वृद्धि दर में भविष्य के लिए कुछ सकारात्मक संकेत दिखाई दिए हैं।

इस क्षेत्र में भारत की स्थिति क्या है? भारत आकार और आबादी में सबसे विशाल है, प्रभावशाली लोकतंत्र के रूप में इसका रिकॉर्ड कमोबेश स्वच्छ रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत सुदृढ़ है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि में व्यापक सुधार हुआ है और इसे एक ऐसे देश के रूप में देखा जाने लगा है, जिसका वैश्विक रंगमंच पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाना निश्चित है। परिणामस्वरूप, दक्षिण एशिया के सभी अन्य देश भारत के सामने बौना महसूस करने लगे हैं। दुर्भाग्यवश, भारत की इसी बढ़ते कद की बदौलत, ऐसे हालात भी उत्पन्न हुए हैं, जिनमें छोटे पड़ोसी देश उसे गलत नजरिए से ''बड़े भाई'' जैसा व्यवहार करने वाले देश के रूप में देखने लगे हैं। कभी-कभी तो कुछ पड़ोसियों को लगने लगा है कि भारत से रियायतें प्राप्त करने के लिए तथाकथित ''चीन कॉर्ड'' खेलना मुनासिब होगा।

क्षेत्र के लिए भारत का विज़न काठमांडु में (26 नवंबर, 2014 को) दक्षेस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त किया गया। उन्होंने कहा, ''भारत के लिए, क्षेत्र के लिए हमारा विज़न पांच स्तंभों: व्यापार, निवेश, सहायता, प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग, हमारी जनता के बीच सुव्यवस्थित संपर्क के माध्यम से मेल-जोल पर टिका है।'' प्रगति की राह में रोड़ा अटकाने वालों का अप्रत्यक्ष रूप से हवाला देते हुए उन्होंने कहा, ''नई चेतना'' का प्रादुर्भाव हो चुका है और दक्षेस सदस्य देशों के बीच रिश्तों का परवान चढ़ना निश्चित है, उन्होंने आगे कहा, ''यह दक्षेस के माध्यम से या उसके बाहर हो सकता है, दक्षेस के सभी सदस्यों के बीच, या उनमें से कुछ के बीच हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं कि पड़ोस के कुछ प्रमुख देशों के साथ हमारे रिश्ते कैसा आकार ले रहे हैं।

भूटान

हिमालयी राज्य, भूटान के साथ हमारे रिश्ते सावधानीपूर्वक विकसित हुए हैं और उन्हें अनुकरणीय कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री अपनी पहली विदेश यात्रा (15-16 जून, 2014) के दौरान भूटान गए थे। इस यात्रा ने अपने आप में सब कुछ बयान कर दिया। इसका उद्देश्य भारत द्वारा भूटान को भरोसेमंद और विश्वसनीय मित्र के रूप में प्रदत्त महत्व को दोहराना था। इस यात्रा के दौरान सहयोग और आर्थिक संबंधों के विकास को बल मिलने की संभावना थी। भूटान, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान खुद को प्राप्त होने वाली सहायता की बेहद सराहना करता आया है, जिनका सिलसिला 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुआ था।

पनबिजली क्षेत्र में भूटान को मिला भारत का सहयोग, दोनों देशों के लिए लाभकारी रहा है और यह अन्य देशों विशेषकर नेपाल के लिए तो अनुकरणीय मॉडल की तरह है। भारत ने भूटान की प्रचुर हाइड्रो अथवा जलीय संभावनाओं को इस्तेमाल में लाने के लिए उसे विद्युत संयंत्र लगाने में सहायता दी है, इससे जहां एक ओर, भारत अपनी ऊर्जा की बढ़ती जरूरतें पूरी करने के लिए बिजली खरीद पा रहा है, वहीं दूसरी ओर भूटान पर्याप्त राजस्व अर्जित कर रहा है। अतीत में, भूटान ने वर्ष 2003 में भारत विरोधी गतिविधियां चलाने वाले उग्रवादियों को अपने भूभाग से खदेड़ दिया था और भारत को आश्वासन दिया था कि वह अपनी जमीन का इस्तेमाल ऐसी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा, जो भारत के राष्ट्रीय हितों के हानिकारक हैं, इस बार भी प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान यह आश्वासन दोहराया गया।

बांग्लादेश

बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान भारत द्वारा निभाई गई भूमिका की व्यापक स्वीकृति और सराहना के बावजूद बांग्लादेश के साथ संबंधों ने कई उतार-चढ़ावों के दौर देखे हैं। शेख हसीना की अगुवाई वाली अवामी लीग पार्टी को जहां भारत के प्रति नरम रवैया रखने वाली समझा जाता है, वहीं बेगम खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनल पार्टी (बीएनपी) और बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी का प्रतिनिधित्व

भारत आकार और आबादी में सबसे विशाल है, प्रभावशाली लोकतंत्र के रूप में इसका रिकॉर्ड कमोबेश स्वच्छ रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत सुदृढ़ है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि में व्यापक सुधार हुआ है और इसे एक ऐसे देश के रूप में देखा जाने लगा है, जिसका वैश्विक रंगमंच पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाना निश्चित है। परिणामस्वरूप, दक्षिण एशिया के सभी अन्य देश भारत के सामने बौना महसूस करने लगे हैं।

करने वाली राजनीतिक ताकतें भारत के प्रति कड़ा रुख अख्तियार करने वाली समझी जाती हैं। हाल के वर्षों में, बांग्लादेश में बीएनपी अथवा अवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकारें रही हैं, जिनके प्रभाव से संबंधों में प्रगति हुई है अथवा ठहराव आया है।

बांग्लादेश की धरती से भारत विरोधी गतिविधियां चलाने वाले भारतीय उग्रवादियों, बांग्लादेश से भारत में होने वाला अवैध प्रवसन, पूर्वोत्तर में सामाजिक तनाव, अनसुलझी सीमाओं के पार होने वाली तस्करी, साझा नदियों विशेषकर तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे आदि की वजह से समय-समय पर, बांग्लादेश के साथ हमारे संबंधों में विघ्न उत्पन्न होते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, शेख हसीना की सरकार ने भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का उपयुक्त रूप से निवारण किया

है, बांग्लादेश में यह धारणा रही है कि बदले में उसे पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल सका है।

इस संक्षिप्त पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने के ऐन बाद बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा (6-7 जून, 2015) पर गए। उनकी यात्रा के दौरान भूमि सीमा समझौता चर्चा का केंद्र बना रहा, जिस पर हस्ताक्षर तो 1974 में हो गए थे, लेकिन भारत में बाद की सरकारें, राज्य सरकारों विशेषकर पश्चिम बंगाल और असम की आपत्तियों सहित विविध कारणों से संसद में इसका अनुमोदन नहीं करा सकीं थीं। प्रधानमंत्री ने जिस अंदाज से केंद्र और राज्यों के अभिमत को संघटित कर सर्वसम्मति से 100वां संविधान संशोधन पारित कराना सुगम बनाया और संसद के दोनों सदनों में 1974 के इस समझौते और इससे संबंधित 2011 के प्रोटोकॉल के अनुमोदन का मार्ग प्रशस्त किया, वह प्रशंसनीय है। भूमि सीमा समझौते से न सिर्फ दोनों देशों के बीच 4096 किलोमीटर सीमा का मामला हल हुआ और भारत/बांग्लादेश की बस्तियों में रहने वाले 50000 से अधिक लोगों को नई पहचान मिली, बल्कि इसके कई अन्य सकारात्मक परिणाम भी हुए, जिनमें उग्रवादियों की गतिविधियों, मानव तस्करी, अवैध प्रवसन और तस्करी आदि पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी सीमा प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण हैं।

भूमि सीमा समझौते से न सिर्फ दोनों देशों के बीच 4096 किलोमीटर सीमा का मामला हल हुआ और भारत/बांग्लादेश की बस्तियों में रहने वाले 50000 से अधिक लोगों को नई पहचान मिली, बल्कि इसके कई अन्य सकारात्मक परिणाम भी हुए, जिनमें उग्रवादियों की गतिविधियों, मानव तस्करी, अवैध प्रवसन और तस्करी आदि पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी सीमा प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण हैं।

प्रधानमंत्री की इस यात्रा का सही मायनों में सबसे महत्वपूर्ण परिणाम, भारत को व्यापार और यात्रा के लिए, बांग्लादेश की ओर से अपनी जमीन से पारगमन की सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी समझौता है, इससे पूर्वोत्तर और भारत के अन्य भागों के बीच संपर्क में उल्लेखनीय सुधार होगा, जो अब तक संकरे और असुरक्षित सिलीगुड़ी गलियारे पर निर्भर था, जो 'चिकन नैक' के नाम से जाना जाता है। ढाका-शिलांग-गुवाहाटी तथा कोलकाता-ढाका-अगरतला बस सेवाएं क्षेत्र के भीतर भू-संपर्क के क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत है। इसी तरह तटीय जहाजरानी (शिपिंग) समझौते से समस्त अपरिहार्य फायदों के साथ जहाज पर माल की ढुलाई पर लगने वाले समय में महत्वपूर्ण कमी आएगी। बांग्लादेश के चटगांव और मोंगला बंदरगाहों के भारत द्वारा इस्तेमाल संबंधी समझौता ज्ञापन भी इतना ही महत्वपूर्ण है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार में बांग्लादेश ने 'पारगमन' को 'तीस्ता' से नहीं जोड़ा।

बांग्लादेश में विशेष भारतीय आर्थिक क्षेत्रों से, भारतीय निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, बदले में रोजगार सृजन के अलावा व्यापार घाटे से जुड़ी बांग्लादेश की चिंताएं दूर होंगी। दो बिलियन डॉलर जितनी दूसरी ऋण सहायता से बांग्लादेश को विशेषकर सार्वजनिक परिवहन, सड़क, रेलवे, अंतर्देशीय जलमार्गों, बंदरगाहों, आईसीटी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में विभिन्न विकास योजनाएं चलाने में मदद मिलेगी, जबकि भारत से वस्तुओं, परियोजनाओं और सेवाओं के निर्यात में योगदान भी दिया जाएगा।

भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध अब तर्कसाध्य रूप से नए गुणात्मक दौर में प्रवेश कर चुके हैं। संबंधों में स्थायित्व पुख्ता हो चुका है। प्रधानमंत्री की यात्रा ने भी जल संसाधन के बंटवारे, बिजली क्षेत्र, (असैन्य परमाणु ऊर्जा सहित), अंतरिक्ष, द्विपक्षीय व्यापार की बांधाएं समाप्त करने और बांग्लादेश में भारत के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संचालन सहित व्यापार एवं निवेश, उचित मल्टी-मॉडल संपर्क और प्रभावी सीमा प्रबंधन आदि सहित भविष्य के द्विपक्षीय और उप-क्षेत्रीय सहयोग के लिए व्यापक एजेंडा तय कर दिया है। सबसे बढ़कर, इस यात्रा ने बांग्लादेश में भारत की कार्य को पूरा कर दिखाने की योग्यता के प्रति पुख्ता भरोसा कायम किया है।

अफगानिस्तान

पिछले कई वर्षों से, अफगानिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि यह उसके सुरक्षा हितों से टकरा रही है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नेटो) सेनाएं वहां से हटना प्रारंभ कर चुकी हैं। अफगानिस्तान में हाल का राजनीतिक बदलाव भी ज्यादा सरल नहीं रहा है। भारत, तालिबान की वापसी जैसी स्थिति के लिए तैयार नहीं है। अफगानिस्तान में इस प्रकार के शासन का उदय भारत के हित में नहीं होगा, जो पाकिस्तान का प्रतिनिधि हो और जिसमें कट्टरपंथियों का वर्चस्व हो।

पिछले साल सितंबर में कार्यभार संभालने के फौरन बाद, अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ घानी ने ऐसी धारणा बनाने के पर्याप्त कारण दिए कि उनकी विदेश नीति की प्राथमिकताओं की सूची में भारत का स्थान काफी नीचे है। उन्होंने कार्यभार संभालने के कई महीने बाद (28-29 अप्रैल 2015) भारत की यात्रा की, इससे पहले उन्होंने ब्रिटेन और सऊदी अरब के अलावा क्षेत्र के दो देशों- चीन और पाकिस्तान का दौरा किया। इस कदम से भारत में चिंता हुई और ये सवाल पूछा गया कि क्या इस कदम से यह जाहिर होता है कि अफगानिस्तान की नीति में पाकिस्तान के पक्ष में बदलाव आया है, और वह भी भारत की कीमत पर।

भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध अब तर्कसाध्य रूप से नए गुणात्मक दौर में प्रवेश कर चुके हैं। संबंधों में स्थायित्व पुख्ता हो चुका है। प्रधानमंत्री की यात्रा ने भी जल संसाधन के बंटवारे, बिजली क्षेत्र, (असैन्य परमाणु ऊर्जा सहित), अंतरिक्ष, द्विपक्षीय व्यापार की बांधाएं समाप्त करने और बांग्लादेश में भारत के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संचालन सहित व्यापार एवं निवेश, उचित मल्टी-मॉडल संपर्क और प्रभावी सीमा प्रबंधन आदि सहित भविष्य के द्विपक्षीय और उप-क्षेत्रीय सहयोग के लिए व्यापक एजेंडा तय कर दिया है।

नई दिल्ली प्रवास के दौरान अफगान राष्ट्रपति ने सजगता से ऐसे आकलनों का महत्व कम करके बताने की कोशिशें कीं। भारत के एक टीवी चैनल, द्वारा यह पूछने पर कि क्या उनकी विदेश यात्राओं का क्रम उनकी प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करता है, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने दिलचस्प रूप से लोकप्रिय कहावत 'देर आयद, दुरुस्त

आयद' का इस्तेमाल किया। इस संबंध में आशंकाओं को दूर करने के लिए ही मानो 28 अप्रैल, 2015 के संयुक्त वक्तव्य में एक अतर्निहित संदर्भ शामिल किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया कि क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सुरक्षा अविभाज्य है और उनके परस्पर सम्मानपूर्ण संबंध अन्य राष्ट्रों या राष्ट्रों के समूह की कीमत पर नहीं हैं। इसी वक्तव्य में अफगान राष्ट्रपति ने भारत के साथ अफगानिस्तान के संबंधों की बुनियादी प्रकृति पर अफगानिस्तान का दृष्टिकोण दोहराया और कहा कि भारत अफगानिस्तान की विदेश नीति की प्राथमिकताओं के पांच 'चक्रों' में से चौथे स्थान पर है।''

आश्वस्त करने वाले इन वक्तव्यों के बावजूद, भारतीय नेतृत्व इस बात से अवगत है कि अफगानिस्तान के भीतर और उसके आसपास हो रही घटनाओं को लेकर सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि अफगानिस्तान के स्थायित्व और मैत्री में भारत के गंभीर हित हैं। द्विपक्षीय रूप से भारत, अफगानिस्तान के साथ सामरिक भागीदारी समझौता कर चुका है और अफगानिस्तान के स्थायित्व में योगदान के अंश के रूप में, उसके बुनियादी ढांचे के विकास, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने, अफगान सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण सहित क्षमता निर्माण के लिए दो अरब डॉलर की सहायता देने की प्रतिबद्धता व्यक्त कर चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान में स्थायित्व भारत की प्राथमिकताओं वाली सूची में प्रमुख स्थान रखता है।

पिछले कई वर्षों से, अफगानिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि यह उसके सुरक्षा हितों से टकरा रही है। भारतीय नेतृत्व इस बात से अवगत है कि अफगानिस्तान के भीतर और उसके आसपास हो रही घटनाओं को लेकर सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि अफगानिस्तान के स्थायित्व और मैत्री में भारत के गंभीर हित हैं।

पाकिस्तान

भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते 1947 में देश के विभाजन के बाद से ही सामान्य नहीं रहे हैं। दोनों देशों ने 1948, 1965, 1971 में युद्ध लड़े हैं और 1999 में यहां करगिल घटित हो चुका है। भारत के खिलाफ आतंक का युद्ध सरहद पार से बदस्तूर जारी है। दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने की छिटपुट कोशिशें होती रही हैं, लेकिन हर बार नतीजा ढाक के तीन पात वाला रहा है।

जिस समय नई सरकार ने कार्यभार संभाला, तब पाकिस्तान के साथ संबंध बेहद नाजुक दौर में थे। पाकिस्तान सहित दक्षेस के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों/राष्ट्राध्यक्षों को पिछले साल मई में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के निमंत्रण ने तनाव मिटाने का अवसर प्रदान किया, शुरुआती हिचकिचाहट के बाद, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ इस मौके पर आए और दोनों पक्षों ने विदेश सचिव स्तरीय वार्ता बहाल करने पर सहमति व्यक्त की। गत वर्ष अगस्त में इस्लामाबाद में होने वाली सचिव स्तरीय वार्ता की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली में कश्मीरी अलगाववादियों से मिलने और बातचीत करने पाकिस्तानी उच्चायुक्त के फैसले ने भारत सरकार को यह यात्रा रद्द करने, यह संदेश भेजने के लिए उकसाया कि पाकिस्तानी उच्चायुक्त द्वारा कश्मीरी अलगाववादियों से मिलना असामान्य बात न होने के बावजूद, सरकार इस पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करती है। भारत सरकार की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया, ''पाकिस्तान के उच्चायुक्त द्वारा हुर्रियत के तथाकथित नेताओं को आमंत्रण ने सचमुच पाकिस्तान की नेकनीयती पर सवालिया निशान लगा दिया है और यह दर्शाता है कि नकारात्मक दृष्टिकोण और भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोशिशें बदस्तूर जारी हैं..... मौजूदा हालात में, यह महसूस किया गया है कि भारतीय विदेश सचिव के अगले सप्ताह इस्लामाबाद जाने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा।'' उसके बाद पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में एक बार फिर से कश्मीर मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया, जिससे माहौल और ज्यादा बिगड़ गया। यहां इस बात का उल्लेख करना उचित है कि 1972 के शिमला समझौते के अंतर्गत पाकिस्तान ने कश्मीर मामले को, द्विपक्षीय मामला समझने पर सहमति व्यक्त की थी।

सरकार का दक्षेस यात्रा (3 मार्च 2015) के अंग के तहत विदेश सचिव को पाकिस्तान भेजने का फैसला और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के रिश्ते बहाल करने की संभावनाओं पर मीडिया में आई कुछ रिपोर्ट्स के कारण आलोचकों ने भारत की पाकिस्तान नीति पर सवाल उठाए। इस संदर्भ में, 31 मई 2015 को नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्री का एक बयान ध्यान देने योग्य है। उन्होंने भारत की पाकिस्तान नीति में किसी तरह के बदलाव से इंकार करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने शुरुआत से बातचीत के तीन मापदंड तय किए हैं, जिनसे पाकिस्तान को बार-बार अवगत कराया गया है और भारत बिना किसी तरह का बदलाव लाए उनका निष्ठापूर्वक पालन कर रहा है। पहला सिद्धांत यह है कि सभी मामले शांतिपूर्ण वार्ता के जरिए सुलझाए जाने चाहिए, दूसरा, वार्ता भारत और पाकिस्तान के बीच होनी चाहिए और किसी तीसरे देश को शामिल नहीं किया जाना चाहिए तथा आखिरी, चर्चा या संवाद शांतिपूर्ण माहौल में और शिमला समझौते तथा लाहौर घोषणा के अनुरूप होना चाहिए।

पाकिस्तान के साथ समस्या की जड़ कश्मीर में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के भीतर मौजूद विविध शक्ति केंद्रों में हैं: ताकतवर सेना, प्रभावशाली आईएसआई, कट्टरपंथी ताकतें और गुट तथा पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित लेकिन कमजोर सरकार। जब तक इन शक्ति केंद्रों के बीच भारत से रिश्ते सुधारने पर सर्वसम्मति नहीं बनेगी, इस बारे में कोई भी ठोस प्रगति महज़ ख्याली पुलाव ही रहेगी।

वैसे, भविष्य में क्या होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि पाकिस्तान के साथ समस्या की जड़ कश्मीर में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के भीतर मौजूद विविध शक्ति केंद्रों में हैं: ताकतवर सेना, प्रभावशाली आईएसआई, कट्टरपंथी ताकतें और गुट तथा पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित लेकिन कमजोर सरकार। जब तक इन शक्ति केंद्रों के बीच भारत से रिश्ते सुधारने पर सर्वसम्मति नहीं बनेगी, इस बारे में कोई भी ठोस प्रगति महज़ ख्याली पुलाव ही रहेगी।

श्रीलंका

सन् 2009 में एलटीटीई के सफाए के बाद, भारत ने श्रीलंका के प्रति बहुआयामी नीति अपनाई। इस नीति के कई संघटक रहे हैं : 1) श्रीलंका सरकार को श्रीलंकाई तमिलों से किए वायदे, विशेषकर शक्तियों के सार्थक हस्तांतरण और 13वें संशोधन के समयबद्ध कार्यान्वयन का वायदा पूरा करने के लिए समझाना। 2) श्रीलंकाई तमिलों को समय-समय पर यह भरोसा दिलाना कि 13वें संशोधन को कमजोर बनाने से रोकने और भविष्य में समुदाय के लिए समानता, न्याय और आत्मसम्मान सुनिश्चित लिए वह हरसंभव कदम उठाएगा। 3) लंबे अर्से तक चले गृह युद्ध से बुरी तरह प्रभावित उत्तरी श्रीलंका के पुनर्निर्माण के लिए निवेश करना, 4) जहां तक संभव हो भारत के तमिल नेताओं की मांगों को पूरा करना, लेकिन अंत में, संकुचित क्षेत्रीय पार्टियों के दबाव में न आकर, व्यापक राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति के निरूपण में केंद्र का विशेषाधिकार का उपयोग करना 5) श्रीलंका में चीन की बढ़ती उपस्थिति पर सावधानी से नजर रखना और श्रीलंका के चीन की ओर झुकाव पर नियंत्रण रखना। 6) मछुआरों का मसला हल करना।

भारत और श्रीलंका दोनों जगह नई सरकार हैं। श्रीलंका में इस साल जनवरी में नेतृत्व परिवर्तन की अल्पावधि के भीतर और बहुत कम अंतराल पर चार उच्च स्तरीय यात्राएं (श्रीलंका के विदेश मंत्री की भारत यात्रा, विदेश मंत्री की श्रीलंका यात्रा, श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा और भारत के प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा) की गई हैं, इससे जाहिर होता है कि दोनों देशों के नेतृत्व अपने संबंधों को दोबारा दुरुस्त करने की मंशा रखते हैं।

दुर्भाग्यवश, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे, ने बार बार भरोसा दिलाने के बाद भी श्रीलंकाई तमिल अल्पसंख्यकों से किया शक्तियों के हस्तांतरण का वादा नहीं निभाया और साथ ही साथ चीन कॉर्ड भी खेला। उनकी निश्चित चीन समर्थक नीति ने, चीन को श्रीलंका में महत्वपूर्ण सामरिक जगह पर नियंत्रण करने का अनुमति दे दी। एलटीटीई से युद्ध के दौरान, श्रीलंका सरकार द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव पर सन् 2012 और 2013 में भारत द्वारा श्रीलंका के खिलाफ मत देना भी जाहिर तौर पर श्रीलंकाइयों को पसंद नहीं आया: वर्ष 2014 में मतदान में भाग न लेने के फैसले को महज सांत्वना के रूप में देखा गया।

अब भारत और श्रीलंका दोनों जगह नई सरकार हैं। श्रीलंका में इस साल जनवरी में नेतृत्व परिवर्तन की अल्पावधि के भीतर और बहुत कम अंतराल पर चार उच्च स्तरीय यात्राएं (श्रीलंका के विदेश मंत्री की भारत यात्रा, विदेश मंत्री की श्रीलंका यात्रा, श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा और भारत के प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा) की गई हैं, इससे जाहिर होता है कि दोनों देशों के नेतृत्व अपने संबंधों को दोबारा दुरुस्त करने की मंशा रखते हैं। श्रीलंकाई संविधान के 13वें संशोधन के पूर्ण कार्यान्वयन के जरिए श्रीलंकाई तमिलों को शक्तियों के हस्तांतरण के अलावा, श्रीलंका में सार्थक सामंजस्य, मछुआरों की रक्षा एवं सुरक्षा, भारत की सुरक्षा चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता, व्यापार और वाणिज्य, समुद्रीय सुरक्षा और महासागरीय अर्थव्यवस्था आदि को बढ़ावा देने पर नए सिरे से बल दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि नई शुरुआत करने और अपने संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए दोनों पक्षों में राजनीतिक इच्छाशक्ति विद्यमान है। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि श्रीलंका में नया नेतृत्व व्यवहारिक रुख अपनाएगा तथा भारत और चीन के साथ संबंधों में संतुलन लाएगा।

नेपाल

कहा जा सकता है कि पिछले कुछ वर्षों से कई कारणों से नेपाल के साथ संबंधों में कुछ हद तक ठहराव आ गया था। नेपाल में राष्ट्रवादी तत्व 1950 की भारत-नेपाल शांति एवं मैत्री संधि के पुनरीक्षण की मांग कर रहे हैं, जो भारत और नेपाल के विशिष्ट रिश्तों का आधार रही है। इस संधि के प्रावधानों के अंतर्गत, नेपाली नागरिकों ने भारतीय नागरिकों के समकक्ष सुविधाओं और अवसरों को प्राप्त करते हुए भारत में अपूर्व लाभ उठाए हैं। इस संधि ने नेपाल को बंदरगाह विहीन देश होने के नुकसान से उबारा है। नेपाल में निहित स्वार्थों वाले लोग भारत-भूटान मॉडल की तर्ज पर भारत-नेपाल पनबिजली सहयोग को अवरुद्ध करने में सफल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप नेपाल प्रचुर पन-बिजली संसाधनों से सम्पन्न होने के बावजूद बिजली का शुद्ध आयातक बना हुआ है और भारत के सीमावर्ती राज्य नेपाल में आने वाली बाढ़ की विभीषिका झेलते आ रहे हैं। साथ ही, नेपाल को शिकायत है कि भारत ने जिन परियोजनाओं को वायदा किया था, उनके कार्यान्वयन में अत्यंत देरी हो रही है। इतना ही नहीं, दशक भर तक, नेपाल राजनीतिक बदलाव के कठिन दौर से गुजरता रहा है, वह राजशाही के अंत, माओवादी आतंकवाद के उत्थान एवं पतन, माओवादियों के मुख्य धारा में लौटने, लोकतंत्र के जन्म का गवाह बना और अब वह देश के लिए नया संविधान लिखने की प्रक्रिया से गुजर रहा है।

प्रधानमंत्री की पिछले साल अगस्त की नेपाल यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक थी। यह 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की प्रथम नेपाल यात्रा थी। प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभालने के तीन महीनों से भी कम अर्से में यह यात्रा की। इस यात्रा से पहले भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक हुई। बीस वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ, जब इसकी अध्यक्षता दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने की। श्री नरेन्द्र मोदी अकेले ऐसे विदेशी हैं, जिन्हें नेपाल की संविधान सभा और संसद को संबोधित करने का सौभाग्य प्रदान किया गया।

प्रधानमंत्री की पिछले साल अगस्त की नेपाल यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक थी। यह 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की प्रथम नेपाल यात्रा थी। प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभालने के तीन महीनों से भी कम अर्से में यह यात्रा की। इस यात्रा से पहले भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक हुई। बीस वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ, जब इसकी अध्यक्षता दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने की।

नेपाल के लोगों की संवेदनाओं को देखते हुए, ''1950 की भारत-नेपाल शांति एवं मैत्री संधि का पुनरीक्षण, उसे समायोजित एवं अद्यतन बनाने पर सहमति व्यक्त की गई'' ताकि ''संशोधित संधि मौजूदा वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से जाहिर कर सके तथा बहुआयामी एवं गहरे संबंधों को और मजबूत और व्यापक बनाने के लक्ष्य को प्रगतिशील ढंग से पूर्ण करे।'' (4 अगस्त 2014

(शेषांश पृष्ठ 18 पर)

IAS GSI / GS World PCS

सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों के साथ.....

Ashok Singh
(Meridian Cources)

Manikant Singh
(The Study)

Prof. Pushpesh Pant
(JNU)

Prof. Majid Hussain
(Pragati IAS)

R. Kumar
(Aastha IAS)

Abhay Kumar
(Synergy)

Deepak Kumar
(GS World)

Rajesh Mishra
(Saraswati IAS)

V. K. Trivedi
(GS World)

Pankaj Mishra
(Aastha IAS)

Subodh Mishra
(Aastha IAS)

छात्रावास सुविधा उपलब्ध,
जीवंत पत्राचार पाठ्यक्रम
शुल्क : 12000/-

Under the organised management of...

Niraj Singh
Managing Director

Divyasen Singh
Co-ordinator

Target IAS 2016

Delhi Centre

सामान्य अध्ययन
Foundation
13 July

Allahabad Centre

GS GATEWAY BATCH
15 July

GS World House, Stainly Road, Near Traffic Choraha
PH. 0532-2266079, 8726027579

Lucknow Centre

Grand Seminar
1st July, 4.00 PM

A-7, Sector-J, Near Puraniya Chauraha, Aliganj
Contact : Mahesh Vishwakarma # 9696214120

Head Office : 705, 2nd Floor, Main Road, Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
PH. 011-27658013, 7042772062/63, 9868365322

YH-81/2015

भारत-अमेरिका संबंधः उभरती साझेदारियां

के सी सिंह

भारत और अमेरिका के लिए चुनौती होगी कि वे अतीत में गंवा दिए गए मौकों की भरपाई आने वाले दशक में कर लें। हालांकि सभी देश अपने हितों की रक्षा करते हैं, चीन के लिए यदि अमेरीकी बाज़ार के दरवाजे नहीं खुलते हैं तो चीन का आगे बढ़ पाना कठिन होगा। भारत पर तकनीकी प्रतिबंध के काल में ऐसा ही हुआ था। भारत की सरकारों ने निरंतर उस स्थिति को समाप्त कर दिया है। अब भारत को केवल भारत ही रोक सकता है

वर्ष 1947 में भारत को स्वाधीनता मिलने के बाद से ही भारत-अमेरिका संबंध को दोनों देशों और दोनों प्रजातंत्रों के मिलन और सभ्यतागत समानता ढूंढने के निरंतर प्रयास के रूप में देखा जा सकता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों के हित अक्सर टकराते रहे हैं। दोनों के बीच वास्तविक संबंधों की संभावना वर्ष 1989 में सोवियत संघ के विघटन और तथाकथित शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद ही पनप पाई।

उसके बाद पी वी नरसिम्हा राव से लेकर आज तक के सभी प्रधानमंत्री इस प्रक्रिया में अपना योगदान देते आए हैं। इसमें कई गंभीर बाधाएं भी आती रही हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 1998 में वाजपेयी सरकार के दौरान भारत द्वारा नाभिकीय परीक्षण किए जाने के बाद अमेरिका ने ग्लेन सुधार के तहत भारत पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। फिर जब जसवंत सिंह तथा स्ट्रोब टॉलबोट की वार्ता के बाद जब नई बाधाओं को सुलझा लिया गया, तब जाकर ही वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की भूमिका को ईमानदारी से स्थान दिया गया और दोनों देशों के बीच सही संबंधों के रास्ते खुल पाए।

अमेरिका को यह बात समझ में आ गई थी कि चूंकि भारत अब एक उभरती हुई ताकत है, इसलिए उसे अब नाभिकीय तकनीक व शस्त्र संपन्न देशों की सूची से बाहर रखना संभव नहीं है और भारत को अब वैश्विक आर्थिक व सुरक्षा व्यवस्था में शामिल करना ही होगा चाहे इसके लिए स्थापित सत्ता समीकरणों को झटका ही क्यों न देना पड़े। शीत युद्ध के दौरान निर्गुटवादी भारत को सामान्यतः दोस्त के रूप में तो देखा जाता था, परंतु विश्वसनीय नहीं माना जाता था। इससे भी बुरी बात यह थी कि 1971-72 में बांग्लादेश की मुक्ति के समय जब अमेरिका चीन से आगे निकल रहा था, भारत को अघोषित रूप से सोवियत संघ का साथी समझा जाता था। बदलते वैश्विक परिदृश्य में अधिक परिपक्व होती भारतीय अर्थव्यवस्था के कारण भारत को एक साथी बनाने का आकर्षण स्पष्ट परिलक्षित होता है।

राष्ट्रपति क्लिंटन के कार्यकाल में जब अमेरिका रणनीतिक सहयोग के लिए आर्थिक संबंधों को बढ़ा रहा था, भारतीय बाज़ार की विशालता और क्षमता ने उसका ध्यान आकर्षित किया। इससे प्रेरित होकर ही वर्ष 1995 में वाणिज्य सचिव रॉन ब्राउन द्वारा राष्ट्रपति व्यापार विकास मिशन की शुरुआत की गई। वर्ष 1999 से भारत-अमेरिका संबंधों की गति और दिशा में काफी परिवर्तन आया। 9/11 के हमले के बाद वर्ष 2000 में राष्ट्रपति क्लिंटन की भारत यात्रा और उसके तुरंत बाद वर्ष 2001 में प्रधानमंत्री वाजपेयी की अमेरिका यात्रा के बाद नई वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में अमेरिका भारत को एक आवश्यक साथी के रूप में देखने लगा। इसमें राष्ट्रपति बुश की वह अवधारणा भी काम कर रही थी जिसके अनुसार एशिया में चीन के उभार को रोकने में एक मजबूत भारत की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती थी। इन दो महत्वपूर्ण घटनाओं ने अमेरिकी नीति को नई दिशा दी।

तत्पश्चात् भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त कार्य-समूहों की रचना और उच्चस्तरीय

लेखक पूर्व विदेश सचिव हैं। वह ईरान तथा संयुक्त अरब अमीरात में राजदूत रह चुके हैं। संप्रति वह सामरिक विषयों पर केंद्रित एक थिंक-टैक के संचालक मंडल के सदस्य हैं। विभिन्न अग्रणी सामचार-पत्रों, पत्रिकाओं व समाचार चैनलों में वह राजनयिक मामलों पर टिप्पणीकार के रूप में उपस्थित होते हैं। ईमेलः ambkesingh@gmail.com

आदान-प्रदान का विस्तार होना शुरू हो गया। इस पृष्ठभूमि में वर्तमान सरकार के अमेरिका के साथ संबंधों को देखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत-अमेरिका नागरिक नाभिकीय समझौता केवल नाभिकीय ऊर्जा की बात नहीं है, बल्कि यह 1974 में भारत द्वारा किए गए शांतिपूर्ण नाभिकीय विस्फोट के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा भारत पर उच्च तकनीक हस्तांतरण पर लगाई गई रोक के रूप में देखा जाना चाहिए। चार अंतर्राष्ट्रीय समूह जिसमें नाभिकीय आपूर्ति समूह, मिसाइल तकनीक नियंत्रण समूह, वासेनार समझौता और आस्ट्रेलिया समूह शामिल हैं, दुनिया की आधुनिकतम और दोहरे उपयोग वाली तकनीकों का नियंत्रण करते हैं। अमेरिका ने यह महसूस कर लिया है कि यदि भारत को चीन जैसे विकसित देशों के साथ खड़ा होना है तो शीत युद्ध के दौरान उस पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना होगा।

पिछले एक वर्ष में भारत-अमेरिका संबंध में काफी सुधार आया है। सितंबर, 2014 में वाशिंगटन वार्ता में सभी मुद्दों पर ध्यान दिया गया था। व्यापार के मुद्दे पर सुनिश्चित किया गया कि वस्तु और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार को पांच गुना बढ़ाकर 100 अरब डालर किया जाएगा। इसके लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास की भी संस्तुति की गई।

बहरहाल, भारत अमेरिका संबंधों में सुधार की गति धीमी रही क्योंकि अमेरिका अपने वित्तीय और बैंकिंग समस्याओं और यूरो क्षेत्र की समस्याओं से जूझ रहा था और भारत भी आर्थिक मामलों में निर्णयहीनता की अपनी समस्याओं से दो-चार हो रहा था।

मौजूदा प्रधानमंत्री ने जब अपना कार्यकाल शुरू किया तो उस समय भारत-अमेरिका संबंध एक प्रकार से ठहराव की अवस्था में थे। दोनों ही देशों में एक बड़े परिदृश्य को सामने रखने की बजाय व्यक्तिगत हितों के प्रभाव में निर्णय लिए जा रहे थे। भारत ने दोहा व्यापार वार्ता में अपने खाद्य-सुरक्षा के मुद्दों को तरजीह नहीं दिए जाने के कारण विरोध प्रकट किया था। भारत द्वारा कड़े परमाणु मुआवजा कानून बनाए जाने से अमेरिका अपमानित महसूस कर रहा था। अमेरिका इसे उपकरण आपूर्तिकर्ताओं पर अतिरिक्त शर्त के रूप में देख रहा था जिसे वे पूरा नहीं कर सकते थे या करना नहीं चाहते थे। अमेरीकी संसद भारत में हो रहे तथाकथित बौद्धिक अधिकारों के उल्लंघन पर सक्रियता दिखा रही थी। भारत की चिंता थी कि अमेरिका के वीसा प्रतिकूल रवैये से भारत के आईटी कर्मचारी पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। टकराव के ऐसे अनेक मुद्दे पैदा हो रहे थे। यह वह समय था जब दोनों देशों के नेताओं द्वारा व्यवस्थाओं को फिर से बहाल करने के लिए ऊपर से नीचे तक हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो गया था।

सितंबर, 2014 में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा और राष्ट्रपति बराक ओबामा की जनवरी, 2015 में भारत यात्रा ने परस्पर संबंधों में गति प्रदान की। ओबामा अपने कार्यकाल में दो बार भारत आने वाले और साथ ही भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं।

डब्ल्यूटीओ मामले को सुलझाने के लिए अमेरिका भारत के खाद्य भंडारों के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए सहमत हो गया। परंतु नाभिकीय मामले को राष्ट्रपति ओबामा की भारत यात्रा का इंतजार करना पड़ा जब अमेरीकी सरकार ने भारत को मौका दिया कि वह अमेरिकी आपूर्तिकर्ताओं को परमाणु मुआवजा कानून की आवश्यकता समझाने का प्रयास करे। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा और अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों नेताओं द्वारा जारी संयुक्त व्यक्तव्य से यह साफ दिख रहा था कि दोनों के बीच परस्पर विश्वास और सहयोग के विषय बढ़े हैं।

पिछले एक वर्ष में भारत-अमेरिका संबंध में काफी सुधार आया है। सितंबर, 2014 में वाशिंगटन वार्ता में सभी मुद्दों पर ध्यान दिया गया था। व्यापार के मुद्दे पर सुनिश्चित किया गया कि वस्तु और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार को पांच गुना बढ़ाकर 100 अरब डॉलर किया जाएगा। इसके लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास की भी संस्तुति की गई।

इस संबंध में भावी रणनीति बनाने के लिए एक उच्चस्तरीय बौद्धिक संपदा समूह की स्थापना की गई। विनिर्माण में नवाचार और कौशल विकास में नई सहभागिता के लिए संवाद बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया।

एक ओर ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे थे जिसमें स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जा को समाधान के रूप में रखा गया था। पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी (पेस) के रूप में इस क्षेत्र में एक रणनीतिक साझेदारी की गई। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस 2015 में हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के प्रति भी एक घोषणा की गई। इसके अनुसार क्योटो प्रोटोकोल के बाद कार्बन उत्सर्जन पर एक कार्ययोजना बनाना था। अमेरिका ने आश्वासन दिया कि भारत में कार्बन उत्सर्जन नियंत्रित अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए वह एक अरब डॉलर की एक्जिम बैंक सुविधा प्रदान करेगा। रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के मामलों पर भी पूरा ध्यान दिया गया। रक्षा-सहयोग, रक्षा तकनीक प्रदान करने और मालाबार सामुद्रिक अभ्यास को जारी रखने जैसे पुराने समझौतों को फिर से जारी रखने की घोषणा की गई।

आतंकवाद का सामना करने के मुद्दे पर दोनों देशों ने अपने संकल्प को दोहराया और कहा कि, 'सम्मिलित और ठोस उपाय जिसमें आतंकियों के सुरक्षित ठिकानों को नष्ट करना शामिल है, किए जाने अत्यंत आवश्यक है।' पाकिस्तान को केंद्र बनाकर कार्यरत सभी आतंकी समूहों के नाम लिए गए जिसमें भारत में काम करने वाले लश्कर-ए-तौएबा और दाऊद समूह भी शामिल है। मुंबई पर हुए 26/11 के हमले के अपराधियों का पाकिस्तान द्वारा प्रत्यर्पण कराए जाने का भी उल्लेख किया गया। सामूहिक प्रयास और पाकिस्तान को निशाना बनाने वाली भाषा पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी थी।

उच्च तकनीक, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहयोग के मुद्दो पर उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है जो भारत को विनिर्माण में 21वीं सदी के स्तर का विशेषज्ञता दिला सकता है। हालांकि ऊर्जा लागतों में आई कमी के कारण विनिर्माण क्षेत्र के कई रोजगार वापस अमेरिका जा रहे हैं, फिर भी कई चुनिंदा क्षेत्रों में सरकार की मेक इन इंडिया नए सहयोगियों को आकर्षित कर सकती है।

उच्च तकनीक, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहयोग के मुद्दों पर उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है जो भारत को विनिर्माण में 21वीं सदी के स्तर का विशेषज्ञता दिला सकता

है। हालांकि ऊर्जा लागतों में आई कमी के कारण विनिर्माण क्षेत्र के कई रोजगार वापस अमेरिका जा रहे हैं, फिर भी कई चुनिंदा क्षेत्रों में सरकार की मेक इन इंडिया नए सहयोगियों को आकर्षित कर सकती है। सरकार ने एक नई पहल की है 'ज्ञान' अर्थात् ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडेमिक नेटवर्क (जीआईएएन) के नाम से। इसके तहत प्रत्येक वर्ष 1000 अमेरिकी शिक्षाविद् पढ़ाने के लिए भारत आया करेंगे। आज भारत का कोई भी विश्वविद्यालय एशिया के टॉप रैंकिंग में नहीं है। ऐसे में यह पहल उच्च शिक्षा संस्थानों के स्तर ऊपर उठाने का त्वरित उपाय है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई और पुरानी महामारियों से लड़ने और वैक्सीन तैयार करने में सहयोग के संकेत दिए गए हैं। भारत को मध्यम स्तर पर आम आदमी तक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में जो कमी है, उसे दूर करने की आवश्यकता है। निजी अस्पतालों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दो प्रकार के भारत का निर्माण कर रही हैं। एक अत्यंत दयनीय स्वास्थ्य सेवाओं वाला गरीब भारत और दूसरा धनी भारत।

रणनीतिक मोर्चे पर साझा बयान सरकार के एक्ट ईस्ट नीति और ओबामा के एशिया में समन्वय नीति के बीच संतुलन साधता दिखा। मध्य, दक्षिण और पूर्वी एशिया में संपर्क की भारत-अमेरिका की नीति चीन के 'वन बेल्ट, वन रोड, हब एंड स्पोक' का उत्तर है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर जोर दिया गया और समुद्री आवागमन विशेषकर दक्षिण चीन सागर में की स्वतंत्रता पर विशेष जोर दिया गया।

जनवरी, 2015 में राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा में तीन दस्तावेज साझा रूप से जारी किए गए। उनमें 2014 में जारी दस्तावेजों के अनेक विषयों का विस्तार किया गया था और रणनीतिक धारणाओं के संरूपण का प्रयास भी था। एक ऐसा ही विशेष दस्तावेज है मैत्री घोषणापत्र। यह घोषणापत्र अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, स्थिरता व समृद्धि के लिए साझा रणनीतिक दृष्टि की व्याख्या करता है। ये बड़े ही उदात्त लक्ष्य हैं जिसको पाने के लिए कि अतीत में भी भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इसके बाद यह घोषणापत्र साझा मूल्यों जैसे कि लोकतंत्र, मानवाधिकार आदि की चर्चा करता है, यह जलवायु परिवर्तन से सामना करने, स्थिर विकास करने जैसे कर्तव्यों की बात करता है और नियमबद्ध तथा पारदर्शी बाज़ार का भरोसा दिलाता है। यह वर्तमान रणनीतिक संवाद को रणनीतिक व वाणिज्यिक संवाद में बदलता है और दोनों देशों के प्रमुखों और सुरक्षा सलाहकारों के बीच हॉटलाइन स्थापित किए जाने पर जोर देता है।

एक दूसरा दस्तावेज एशिया पैसिफिक के लिए साझा रणनीतिक दृष्टि की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। एक बार फिर समान लोकतंत्र होने के कारण भारत और अमेरिका के मिल कर काम करने पर जोर दिया जा रहा है ताकि पूरे क्षेत्र में एक कानून आधारित व्यवस्था का निर्माण हो सके। दोनों ही दस्तावेजों में चीन की भूमिका का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि भारत सिंगापुर में होने वाले शांग री ला संवाद में अपना रक्षा मंत्री भेजना टाल गया, अमेरिका के साथ उसका तालमेल इन दस्तावेजों से साफ जाहिर होता है। इस प्रकार भारत अपनी पिछली छह दशक पुरानी निर्गुट की नीति से बहुगुट की नीति की ओर अग्रसर हो गया है।

जनवरी, 2015 में राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा में तीन दस्तावेज साझा रूप से जारी किए गए। उनमें 2014 में जारी दस्तावेजों के अनेक विषयों का विस्तार किया गया था और रणनीतिक धारणाओं के संरूपण का प्रयास भी था। एक ऐसा ही विशेष दस्तावेज है मैत्री घोषणापत्र। यह घोषणापत्र अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, स्थिरता व समृद्धि के लिए साझा रणनीतिक दृष्टि की व्याख्या करता है।

रक्षा के क्षेत्र में त्वरित कार्रवाई करते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर 2-3 जून, 2015 को भारत आए। नई दस वर्षीय रक्षा फ्रेमवर्क समझौते के अनुसार अमेरीकी तकनीक को भारतीय मेक इन इंडिया के साथ मिलाना है। एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन और जेट इंजन पर वार्ता होनी है। एयरक्राफ्ट कैरियर से विमानों को लांच करने की कैटापुल्ट तकनीक जो अभी केवल अमेरिका के पास ही है से भारत और अधिक भारवाही और टोही विमानों को भेज सकेगा।

अमेरिका के साथ नजदीकी संबंधों के

भारत-अमेरिका के बीच अहम समझौते

- अवसंरचना के क्षेत्र में सहयोग को लेकर बनी सहमति।
- 25 जनवरी, 2015 को अमेरिका की व्यापार एवं विकास एजेंसी और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों के बीच विशाखापत्तनम, इलाहाबाद और अजमेर को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने को लेकर समझौता हुआ। इससे संबंधित एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए गए।
- यूएसएआईडी और भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के बीच 500 शहरों के विकास और स्वच्छ भारत अभियान जैसी प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं को साकार करने के लिए एएमओयू पर हस्ताक्षर किए।
- डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के क्रियान्वयन में सहयोग की संयुक्त घोषणा।
- यूएसएआईडी ने आईआईटी गांधीनगर के साथ नॉलेज पार्टनरशिप पर जताई सहमति।
- अमेरिका ने अकादमिक विकास की दिशा में भारत के वैश्विक अकादमिक नेटवर्क (ज्ञान) स्थापित करने के प्रयासों का किया समर्थन। भारत में शॉर्ट टर्म अध्यापन और रिसर्च प्रोग्राम के लिए 1000 अमेरिकी शिक्षक भारत के विश्वविद्यालयों से जुड़ेंगे।
- वाशिंगटन में भारत-अमेरिका निवेश उपक्रम की स्थापना को लेकर बनी सहमति।
- व्यापार नीति फोरम की मंत्री स्तरीय बैठक पर बनी सहमति।
- भारत में स्वच्छ ऊर्जा की परियोजनाओं के लिए अमेरिका का एक्जिम बैंक देगा एक अरब डॉलर। अमेरिकी निजी कंपनियों ने भी इस सेक्टर में निवेश पर जताई सहमति।
- नवंबर, 2015 में इंडो-यूएस तकनीकी समिट के आयोजन पर सहमति। अमेरिका पहली बार होगा साझीदार देश।
- उच्च तकनीकी उत्पादों के विकास के लिए सहयोग को दोनों देशों में सहमति।

वादों को पूरा करने के लिए ढेर सारे क्षेत्रों में काफी अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है विशेषकर तब जबकि चीनी सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। चीन दक्षिण चीन सागर में अपना लगातार नियंत्रण बढ़ा रहा है। इस बीच भारत ने ब्रिक्स समूह के माध्यम से चीन और रूस के लिए भी अपने दरवाजे खोल दिए हैं। संभावना है कि भारत को शंघाई सहयोगी संगठन में भी शामिल कर लिया जाए। भारत के लिए इस प्रकार के समानांतर और प्रतिस्पर्धी सूत्रों को संभालना एक बड़ी चुनौती होगी। यह संतुलन साधना साउथ ब्लाक में बैठे राजनयिकों के लिए खासा मशक्कत भरा होगा क्योंकि निर्गुट आंदोलन के समय से ही उनका अभ्यास सभी प्रमुख ताकतों से एक हाथ की दूरी रख कर काम करने का रहा है।

भारत और अमेरिका के लिए चुनौती होगी कि वे अतीत में गंवा दिए गए मौकों की भरपाई आने वाले दशक में कर लें। हालांकि सभी देश अपने हितों की रक्षा करते हैं, चीन के लिए यदि अमेरीकी बाज़ार के दरवाजे नहीं खुलते हैं तो चीन का आगे बढ़ पाना कठिन होगा। भारत पर तकनीकी प्रतिबंध के काल में ऐसा ही हुआ था। भारत की सरकारों ने निरंतर उस स्थिति को समाप्त कर दिया है। अब भारत को केवल भारत ही रोक सकता है। ❑

(पृष्ठ 13 का शेषांश)

को प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा के दौरान संयुक्त प्रेस वक्तव्य) नेपाल में भरोसे की कमी को मिटाने के लिए प्रधानमंत्री ने नेपाल की जनता को भरोसा दिलाया कि भारत की, नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोई मंशा नहीं है और वह द्विपक्षीय एवं उप-क्षेत्रीय प्रारूपों में नेपाल के साथ सहयोग करने का इच्छुक है। कई परियोजनाओं मसलन- पंचेश्वर विकास परियोजना और अपर करनैली पनबिजली परियोजना के लिए परियोजना विकास समझौते के लिए समय सीमा निर्धारित है और संभावित सहयोग के कई नए क्षेत्रों की पहचान की गई है। कुल मिलाकर भारत-नेपाल संबंधों को जीवंतता प्रदान करने पर विशेष बल दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कि कोई भी आसानी से समझ सकता है कि भारत, सचमुच संबंधों को सही दिशा में लाने का इच्छुक है और नेपाल की जनता को भारत की वायदा निभाने की योग्यता पर काफी भरोसा है।

अंत में कहा जा सकता है कि दक्षिण एशिया में एक साल की व्यापक एवं ऊर्जा से भरपूर कूटनीति कई मायनों में फलदायी रही है: इसने विश्वास की कमी काफी हद तक दूर की है, वायदे पूरे करने की भारत की क्षमता के प्रति भरोसा बढ़ाया है, मौजूदा रिश्तों को और ज्यादा प्रगाढ़ बनाया है, कुछ मामलों में रिश्तों को नए सिरे से निर्धारित किया है, वर्तमान चुनौतियों को दूर किया है और दीर्घकालिक संबंध के लिए एजेंडा निर्धारित किया है, विकास एवं समृद्धि तथा जमीनी, सामुद्रिक एवं हवाई संपर्क के जरिए आर्थिक एकीकरण सहित, क्षेत्र के एकीकरण की पहली शर्त के रूप में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की जरूरत सशक्त ढंग से दोहराई है। इससे सब तरफ एक गूढ़ संदेश गया है कि जिन क्षेत्रों में सभी सदस्यों के मिलकर काम करने में कठिनाइयां हैं, वहां द्विपक्षीय अथवा उप-क्षेत्रीय प्रारूपों को अपनाया जाए, ताकि इच्छुक सदस्य साथ आ सकें और आगे बढ़ सकें। वक्त आ चुका है कि अब तक हासिल सम्मिलित लाभों पर समयबद्ध रूप से आगे की कार्यवाही की जाए, वायदे और आश्वासन कर्मठता से पूरे किए जाएं और अनसुलझे मामले प्रभावशाली ढंग से सुलझाए जाएं। ❑

ENGLISH

by

Muntosh Mishra "भारत"

Complete Grammar + Writing Skills

* 7 DAYS' CLASSES FREE
* Vocabulary के लिए आधे घंटे हर दिन
* Practice sets + Previous years' के Questions का solution
* मात्र 3-4 महीने में English की किसी भी Competition के लिए पूर्ण तैयारी
* Printed, updated study materials
* UPSC, PO और SSC के लिए Separate Batches
* English में लिखना सिखाने पर विशेष ध्यान

अगर आपको लगता है कि आपकी English बहुत कमजोर है तो Free trial classes जरूर लें।

Satisfaction नहीं होने पर Fees 45 दिनों में कभी भी वापस

THE WELL™

SANCTUM OF SUCCESS

308, Top Floor, Jyoti Bhawan
In Front of Post Office
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9

09811141396, 09899324319

YH-77/2015

भारत और चीन संबंध– बदलते रिश्ते

मनीष चंद

साझी लोकप्रिय संस्कृति एशिया की दो उभरती हुई शक्तियों के बीच में एक शक्तिशाली सूत्र और सेतु निर्माता के रूप में स्थापित हुई है जो आपस में एक उदार मूल्य प्रणाली, पारिवारिक परंपराओं के प्रति आदर और शिक्षा पर बल व मानसिक विकास द्वारा एक दूसरे से जुडी हुई हैं। अब इस तार को और मजबूत करने की कोशिश हो रही है। इसके लिए ना केवल रणनीति या व्यवसायिक बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक विनिमय पर भी जोर दिया जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में हिमालय के आर-पार फैले दोनों देश अधिक सुखद व सहज संबंधों के साक्षी होंगे

भारत और चीन संबंधों में इस समय एक परिवर्तनकारी आंदोलन हमें देखने को मिल रहा है और यह उस नई ऊर्जा, उत्साह और रचनात्मक तरीके से परिलक्षित हो रहा है जिस ऊर्जा और उत्साह से ये दोनों देश संलग्न हो रहे हैं। जिस तरीके से यह पहली बार हो रहा है कि एशिया की इन दो महाशक्तियों के नेताओं ने पिछले 9 महीनों में एक दूसरे के देशों की यात्राएं की हैं, यह इस बात का संकेत है कि दोनों ही देश आपसी सहयोग से इस सदी को एशिया की सदी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री का चीन में 14 से 16 जून तक का जियान, बीजिंग और शंघाई का दौरा कई मामलों में महत्वपूर्ण रहा है और उसने दो एशियाई महाशक्तियों के बीच में विविध संबंधों के बहुमुखी रेशों को बांधा है, जहां विश्व की एक तिहाई जनता निवास करती है और जहां का कुल सकल घरेलू उत्पाद 12 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स से भी ज्यादा है।

प्रधानमंत्री की चीन की यात्रा ने उस उत्साह में वर्धन किया है जो सितंबर 2014 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा की गई भारत की यात्रा के साथ आरंभ हुआ था। अगर दोनों यात्राओं को और दिल्ली में पिछली सरकार के दौरान जो कदम उठाए गए थे, उन्हें एक साथ रखा जाए तो यह भारत और चीन की उभरती वर्णमाला को बतलाता है। A से एशिया, B से बिजनेस, C से कल्चर, और D से डिप्लोमेसी और डेवलपमेंट। ये नया शब्दकोष और सिद्धांत दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग के नए आयाम खोलते नजर आ रहे है जिन्हें अक्सर विश्व एशिया के चिर प्रतिद्वंदियों और दुश्मनों के रूप में जानता है पर जो अब विविध क्षेत्रों में एक महत्वाकांक्षी सहभागिता का निर्माण कर रहे हैं।

गृहनगर कूटनीति

संयुक्त कूटनीति, संस्कृति, व्यापार और भू-राजनीति, प्रधानमंत्री के यात्रा प्रतीकवाद और प्रभावी परिणामों दोनों को ही बतलाती है जो इस महत्वपूर्ण संबंध में नए रुझानों और सूचनाओं को बतलाती है। अपने प्रकार की प्रथम भावभंगिमा के रूप में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री का स्वागत अपने गृहनगर जियान के सरकारी अतिथि ग्रह में किया था। शुरुआती बैठक में राष्ट्रपति शी ने भारत और चीन के रिश्तों की एक खूबसूरत तस्वीर पेश करने की कोशिश की। चीनी राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री को बताया कि चीन और भारत के रिश्ते ''स्थाई विकास को महसूस कर रहे हैं और उदार संभावनाओं के समक्ष खड़े हैं''। प्रधानमंत्री का टेरिकोटा लड़ाकों के संग्रहालय और प्राचीन बुद्ध मंदिर (जहां संस्कृत वक्तव्यों के चीनी अनुवाद रखे गए हैं) में जाना भारत और चीन के सदियों पुराने सभ्यतागत रिश्तों की याद दिला गया। ऐसा पहली बार था कि राष्ट्रपति शी ने किसी

लेखक मनीष चंद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, उभरती शक्तियों और चीन पर आधारित एक ऑनलाइन पत्रिका इंडिया राइट्स नेटवर्क www| indiawrites| वतह के संस्थापक-सीईओ और प्रमुख संपादक है। उन्होंने चीन की कई बार यात्रा की है और भारत और चीन के मीडिया फोरम में भाग लिया है जो दो देशों के मीडिया पेशेवरों के बीच में सूचना अंतर को कम करने के लिए और एक बेहतर संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया एक कदम है। विदेशी मामलों के विश्लेषक के रूप में उनके मुख्य शोध क्षेत्रों में भारत और चीन संबंध, भारत और अफ्रीका संबंध और उभरती शक्तियां रही हैं। उन्होंने कई थिंक टैंक (विचारक समूहों) के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों पर पेपर प्रस्तुत किए हैं। ईमेल: manish.mcchand@gmail.com

विदेशी राजनेता की आगवानी और स्वागात सत्कार अपने गृहनगर में किया हो, जो भारत चीन के रिश्ते को मजबूत करने के प्रयासों में उनकी निजी प्रतिबद्धता दर्शाता है। राष्ट्रपति शी द्वारा जो गरमाहट और व्यक्तिगत मेहमाननवाजी प्रधानमंत्री को दी गई उसे हम प्रधानमंत्री के द्वारा अहमदाबाद में शी के भव्य स्वागत और मेहमाननवाजी के प्रतिफल के रूप में देख सकते हैं। ऐसा पहली बार हुआ था कि भारत और चीन के नेताओं ने एक दूसरे के देशों में अपनी यात्राएं राष्ट्रीय राजधानी से शुरू न करते हुए राज्यों की राजधानी से की और उस प्रकार उभरते चीन और भारत संबंधों में गृहनगर कूटनीति की एक नई रूपरेखा का निर्माण किया। इसने द्विपक्षीय संबंधों को नियमित कूटनीति से इतर संबंधों की गर्माहट पर जोर दिया है और दिल और दिमाग के तार भी व्यक्तिगत तौर पर जोड़े हैं। प्रधानमंत्री ने जियान में हुए अपने भव्य स्वागत के बाद ट्वीट करके कहा, "चीन के लोगों का उत्साह देखकर खुशी हुई। लोगों-से-लोगों का जुड़ाव हमेशा खास होता है।"

कूटनीति में प्रतीकवाद का अहम स्थान है पर ये ठोस कदमों की जगह नहीं ले सकते। भारत और चीन के रिश्तों की नई कहानी में इस प्रकार हमें प्रतीकवाद और ठोस कदम इस महत्वपूर्ण संबंध के दीर्घकालीन संस्करण के साथ सम्मिलित रूप से मिलते हैं जो दो देशों के 2 अरब 6 करोड़ लोगों की जिंदगियों और किस्मत पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल सकता है।

नई शक्तियों की कहानी: एशियाई सदी

कूटनीति में प्रतीकवाद का अहम स्थान है पर ये ठोस कदमों की जगह नहीं ले सकते। भारत और चीन के रिश्तों की नई कहानी में इस प्रकार हमें प्रतीकवाद और ठोस कदम इस महत्वपूर्ण संबंध के दीर्घकालीन संस्करण के साथ सम्मिलित रूप से मिलते हैं जो दो देशों के 2 अरब 6 करोड़ लोगों की जिंदगियों और किस्मत पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल सकता है। एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक वक्तव्य में, 15 मई को दिया गया संयुक्त वक्तव्य भारत और चीन को "क्षेत्र की दो प्रमुख महाशक्तियों" के रूप में बताता है जो एशियाई सदी और इक्कीसवीं शताब्दी के भू-राजनीतिक-आर्थिक परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ेंगी। वक्तव्य के अनुसार "नेतृत्व भारत और चीन के क्षेत्र की दो महाशक्तियों के उदय को मानता है और विश्व इस बात को मान रहा है कि यह सदी एशिया की होने वाली है।" "उनके बताया है कि भारत चीन द्विपक्षीय संबंध एशिया और पूरे विश्व में निश्चित ही इक्कीसवीं शताब्दी में एक निर्धारक भूमिका का निर्वाह करने जा रहे हैं।" संबंधों को एक वृहद वैश्विक परिदृश्य में देखते हुए संयुक्त वक्तव्य का कहना है कि "दो विशाल उभरते विकासशील देशों, दो सबसे तेज उभरती अर्थव्यवस्थाओं और वैश्विक वास्तु में दो मुख्य ध्रुवों के बीच संबंधों का संरचनात्मक मॉडल अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्य-से राज्य संबंधों के लिए एक नया आधार प्रस्तुत करता है"

चुनौतियों की लाल रेखाएं

सबसे सृजनात्मक योगदान हालांकि सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी के साथ आया कि भारत और चीन के रिश्तों के सामर्थ्य का सही फलन और शांतिपूर्ण एशिया की सदी का वादा तब ही संभव हैं जब दोनों देश "एक दूसरे की चिंताओं, हितों और आकांक्षाओं को आपसी सम्मान और संवेदनशीलता" से ख्याल रखें। ये वे महत्वपूर्ण लाल रेखाएं/चेतावनियां हैं जिनका ध्यान दोनों ही देशों को रखना होगा अगर वे एक दूसरे को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सामरिक अविश्वास और प्रतिद्वंद्विता की धारणाओं को दरकिनार करते हुए उद्दयमान होते देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने चीन की अपनी मई यात्रा में इन रेखाओं को अपने चीनी मेजबान को याद दिलाया जब उन्होंने उनसे उन मुद्दों पर उनकी बात स्पष्ट करने के लिए कहा जो दोनों ही देशों को इन संबंधों को पूरी तरह से प्रभावी नहीं होने दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने चीनी प्रीमियर ली के साथ अपने संयुक्त मीडिया वक्तव्य में कहा "मैंने चीन से कुछ मुद्दों पर अपना मत बदलने पर जोर दिया जो भारत और चीन के रिश्तों के मजबूत होने में रुकावट पैदा करते हैं", चीनी राष्ट्रपति के साथ बीजिंग में प्रेस वार्ता में कहे गए उनके इस कथन ने भारत द्वारा बीजिंग द्वारा उठाए गए उन कदमों पर अपने विरोध को बताया है जो भारत अनुचित समझता है, और उसे अस्वीकार करता है। इनमें अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के नागरिकों को अलग वीजा देना, भारतीय भूभाग में चीनी सेना का आ जाना और कश्मीर के विवादित क्षेत्र में चीन-पाकिस्तान का विशिष्ट आर्थिक कॉरीडोर उनमें से प्रमुख मुद्दे हैं। ये मुद्दे भारत और चीन के बीच काफी समय से चले आ रहे हैं और भारतीय जनमानस के मन में चीन की एक नकारात्मक छवि स्थापित कर चुके हैं, और बीजिंग की मंशा और कदमों के बारे में ये बीजिंग और नई दिल्ली के बीच महत्वपूर्ण अविश्वास का भी प्रमुख कारण हैं।

चीनी राष्ट्रपति के साथ बीजिंग में प्रेस वार्ता में कहे गए उनके इस कथन ने भारत द्वारा बीजिंग द्वारा उठाए गए उन कदमों पर अपने विरोध को बताया है जो भारत अनुचित समझता है, और उसे अस्वीकार करता है। इनमें अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के नागरिकों को अलग वीजा देना, भारतीय भूभाग में चीनी सेना का आ जाना और कश्मीर के विवादित क्षेत्र में चीन-पाकिस्तान का विशिष्ट आर्थिक कॉरीडोर उनमें से प्रमुख मुद्दे हैं।

अर्थव्यवस्था अहम दृष्टिकोण

इन मुद्दों पर खुलकर आपस के मतभेद जाहिर करने से जोखिम हो सकता है और रिश्तों में खटास आ सकती है। पर यह चीन और भारत के बीच नई परिपक्वता का ही संकेत था कि असंतोष होते हुए भी इन दोनों देशों ने सकारात्मक होना उचित समझा और दोनों ही देशों के लिए उचित प्रतिभागिता के फलक को चौड़ा करते हुए आर्थिक अवसरों पर ध्यान देना उचित समझा। यह भारत और चीन के बीच विविध क्षेत्रों में हुए 24 समझौतों में परिलक्षित होता है जिनमें आधारभूत संरचना, स्मार्ट सिटीज, रेलवेज, स्किल डेवलपमेंट, स्पेस और पर्यावरण परिवर्तन जैसे क्षेत्र हैं। दोनों पक्षों ने कूटनीतिक वार्तालाप बढ़ाने हेतु चीन के चेंगडु और भारत के चेन्नई नगरों में एक एक कांसुलेट खोले जाने का निर्णय लिया है। एक

निर्धारक कदम के रूप में दोनों ही देशों ने अपनी तरह के प्रथम राज्य/आंचलिक लीडर्स फोरम की स्थापना की जिससे भारत और चीन के राज्यों में वार्तालाप को मदद मिलेगी। मंच की पहली बैठक 15 मई को आयोजित की गई जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शिरकत की। इन सबके अतिरिक्त भारत और चीन के बीच मई 2015 की सम्मलेन बैठक ने संबंधों में अर्थव्यवस्था को ही प्रमुखता दी जो नई दिल्ली और बीजिंग में सरकारों की प्रमुखता है। सभी मामलों में भू-राजनीति और भू-अर्थव्यवस्था आने वाले महीनों और दशकों में भारत और चीन के संबंधों के नए आयाम तय करेगी पर अभी आर्थिक परिदृश्य ही है जो गहन निवेश और व्याप्त के माध्यम से साझी-समृद्धि के क्षेत्र में एशिया की दो महा-शक्तियों को नजदीक ला रहा है। और यहां संभावनाएं विशाल हैं, और आसमान ही सीमा है बशर्ते एक दूसरे के प्रमुख मुद्दों की ओर आदर और संवेदनशीलता प्रदर्शित की जाए तो।

मेक इन इंडिया

प्रधानमंत्री ने बीजिंग में कहा था: "हमनें अपनी आर्थिक साझेदारी को उच्च दर्जे की महत्वकांक्षा स्तर पर निर्धारित किया है। हम बहुत बड़े द्विपक्षीय अवसरों और कई चुनौतियों, जैसे शहरीकरण, को देखते हैं।" राष्ट्रपति शी और प्रीमियर ली के साथ अपनी वार्ता में उन्होंने ने कहा: "दोनों नेता हमारे मेक इन इंडिया मिशन और इंफ्रास्टक्चर सेक्टर में चीन के भागीदारी का समर्थन करते हैं।"

आर्थिक परिदृश्य में नतीजे महत्वपूर्ण रहे हैं और कार्य प्रगति में है। राष्ट्रपति शी जिंगपिंग के 2014 में भारत की यात्रा के दौरान भारत में चीन द्वारा अगले पांच सालों में भारत में 20 बिलियन डॉलर्स के निवेश के वादे के आधार पर शंघाई में दोनों देशो के बीच 22 बिलियन डॉलर्स के व्यापारिक समझौते हुए। भारत-चीन सीईओ फोरम में प्रधानमंत्री ने व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर बल दिया। भारत चीन के सीईओ फोरम में अपने संबोधन में, पीएम ने दोनों ही देशों के बीच बढ़ते व्यापार और निवेश पर जोर दिया है और चीन की तरफ से इसपर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। चीन के एम्बेसडर ले युचेंग ने मेक इन चीन और मेक इन इंडिया के बीच गजब की समानता का निर्धारण करते हुए इसे सम्मिलित करके मेक इन चिंह्या बना दिया, जो कि एशिया की दो महाशक्तियों के बीच विनिर्माण और व्यापार को साझा करने की तरफ एक कदम है।

भारत-चीन: अहम समझौते

- लगभग 22 अरब डॉलर के व्यापारिक समझौते।
- आगामी पांच वर्षों के दौरान भारत में 20 अरब डॉलर निवेश करने का चीन का वादा।
- भारतीय आईटी और दवा कंपनियों के लिए चीन का बाज़ार अधिक खोलने पर चीन ने वादा दोहराया।
- वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान सामरिक तथा आर्थिक संवाद आयोजित करने का निर्णय। इसकी अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष तथा चीन स्थित एनडीआरसी के चेयरमैन संयुक्त रूप से करेंगे।
- दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रालयों के बीच आगामी 5 वर्षों के लिए व्यापार तथा विकास कार्यक्रम तैयार।
- मुंबई और शंघाई, अहदाबाद तथा ग्वांगझू, हैदराबाद एवं क्विंगडाओ, चेन्नई और चोंगक्विंग के बीच *सिस्टर सिटि* तथा गुजरात एवं ग्वांगडोंग और कर्नाटक तथा सिचुआन के बीच *सिस्टर स्टेट* का संबंध स्थापित करना।
- संघाई में फुडान विश्वविद्यालय के अंतर्गत गांधी तथा भारतीय अध्ययन केंद्र और क्यूनमिंग में योग महाविद्यालय स्थापित करना।
- वार्षिक मानसरोवर यात्रा के लिए सिक्किम के नाथूला दर्रे के रास्ते अतिरिक्त मार्ग तैयार करने पर समझौता। यह उत्तराखंड के लिप्पुलेख दर्रे से होकर जाने वाले रास्ते के अलावा होगा। नाथूला के रास्ते मार्ग खुलने पर ज्यादा लोग यात्रा कर सकेंगे और परेशानी तथा समय दोनों में कमी आएगी।
- चीन में *भारत-भ्रमण* वर्ष की घोषणा। भारत में 2016 चीन *भ्रमण-वर्ष* होगा।

10 जून को FICCI द्वारा आयोजित चीन-भारत इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन सेमिनार में ले ने कहा चीन ने हाल ही में मेड इन चीन 2025 अभियान की शुरुआत की है जिसमें अन्य के साथ अभिनव और उच्च विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा, जो उन्होंने कहा कि कई मायनों में भारत के प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया रणनीति के समकक्ष व समकालीन है। चीन के राजदूत ने जोर देकर कहा कि चीन का व्यापारिक समुदाय समुदाय भारत की नई सरकार के द्वारा व्यापार को आसान बनाने के उपायों की प्रशंसा करता है और साथ ही उन्होंने कहा कि चीन की कंपनियां भारत में कई क्षेत्रों में निवेश करना चाहती हैं जैसे विनिर्माण, मानव संसाधन, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी परियोजनाएं और रेलवे।

जहां एक ओर व्यापार इस बात की गारंटी नहीं देता की भारत और चीन के रिश्ते हमेशा सौहार्दपूर्ण ही रहेंगें, और विवादास्पद मुद्दे संबंधों को प्रभावित नहीं करेंगे, जैसा जापान और चीन के रिश्तों से देखा जा सकता है, कि आर्थिक अभियान से विवाद की आशंका में कमी आती है और दोनों ही देश साझे लाभों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो गहरे होते आर्थिक संबंधों से हासिल किए जा सकते हैं। तभी भारत और चीन के बीच बदलते संबंधों की कहानी को आर्थिक कदमों से सही किया जा सकता है और इस पूरे परिदृश्य में एक बेहतर आर्थिक संबंधों के लिए दीर्घ सूत्रीय संरचना का निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में, नवीनतम निर्णय है 2015 की दूसरी छमाही में एक रणनीतिक आर्थिक संवाद आयोजित कराने का निर्णय जिसकी सह अध्यक्षता भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष और चीन के एनडीआरसी के अध्यक्ष करेंगे व दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रालयों के बीच पंच वर्षीय व्यापार और विकास योजनाओं का विकास करना।

विकास में साझेदारी

विकास में निकटतम साझेदारी का विकास एक और ऐसा कदम है जिससे दोनों एशियाई देशों के बीच सहयोग के नए मार्ग खोले गए हैं। इस संदर्भ में सरकार ने पिछली सरकार के द्वारा किए गए कुछ अच्छे कार्यों पर अच्छा काम किया है। मई के सम्मलेन में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इनमें सम्मिलित

हैं: 1) चीन का गुजरात और महाराष्ट्र में औद्योगिक पार्क की स्थापना करना 2) रेलवे प्रोजेक्ट जैसे चेन्नई-बेंगलुरु-मैसूर लाइन की गति बढ़ाना, दिल्ली-नागपुर सेक्शन में हाई-स्पीड लिंक बनाना , रेलवे यूनिवर्सिटी बनाना आदि में चीन की सहभागिता 4) भारत में गिट शहर और चीन में शेनजेन के बीच महत्वपूर्ण स्मार्ट सिटी परियोजना 5) मुंबई-शंघाई, अहमदाबाद-गुआंगघेउ, हैदराबाद-किंगडाओ, औरंगाबाद-दुनहुआंग के बीच सिस्टर सिटी संबंध की स्थापना करना और चेन्नई-चोंगकिंग और गुजरात-ग्वान्दोंग और कर्नाटक-सिचुआन के बीच सिस्टर राज्य/आंचलिक संबंध स्थापित करना

लंबा परिदृश्य: वैश्विक सहयोग

अपने रिश्तों को वैश्विक आयाम देते हुए, भारत और चीन ने अपनी संलग्नता का विस्तार किया है और कई वैश्विक व ताजे मुद्दों को आपनी वार्ता में सम्मिलित किया है जैसे: आतंकवाद, बहुदेशीय व्यापारिक वार्ता और अफगानिस्तान में क्षेत्रीय सहयोग को सघन करने के लिए बहुमुखी व्यापार बातचीत व और पश्चिमी एशिया में संकट। कम्प्रेहेंसिव कन्वेशन ओन इंटरनेशनल टेररिज्म पर वार्ता को जल्दी खत्म करने की भारत द्वारा एक लंबे दबाव पर चीन की सहमति के साथ आतंकवाद पर लगाम लगाने का बढ़ता दबाव महत्वपूर्ण हैं। अफगानिस्तान पर सहयोग, जो पूर्व प्रधानमंत्री की सरकार की पहल का परिणाम था, पर विश्व और क्षेत्र द्वारा गहरी निगाह रखी जाएगी। दोनों एशियाई देश अंतर्राष्ट्रीय बहुदेशीय व बहुसंबंधीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, जी-20 और सुरक्षा परिषद में भी एक दूसरे के सहयोग और समर्थन में तेजी लाएंगे।

चीन में प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौती पर एक अतिरिक्त संयुक्त वक्तव्य यह प्रदर्शित करता है कि कैसे ये दो देश दिसंबर 2015 में पेरिस में सीओपी 21 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन में एक वैश्विक समझौते के लिए जारी प्रयासों को आकार देने के लिए अपने द्विपक्षीय संबंधों का प्रबंधन कर सकते हैं।

चीन में प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौती पर एक अतिरिक्त संयुक्त वक्तव्य यह प्रदर्शित करता है कि कैसे ये दो देश दिसंबर 2015 में पेरिस में सीओपी 21 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन में एक वैश्विक समझौते के लिए जारी प्रयासों को आकार देने के लिए अपने द्विपक्षीय संबंधों का प्रबंधन कर सकते हैं। स्थाई विकास में सहभागिता पर यह ध्यान अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एमओयू पर हस्ताक्षर करने में परिलक्षित होता है। संयुक्त वक्तव्य के अनुसार वे पेरिस में होने वाले यूएनएफसीसीसी के लिए आगामी सीओपी 21 में एक महत्वाकांक्षी, विस्तृत, वैश्विक, संतुलित और समान जलवायु अनुबंध का निर्माण करने के लिए एक साथ और दूसरे अन्य देशों के साथ काम करने महत्ता को समझते हैं, जो वास्तविक तकनीक हस्तांतरण, अनुकूलन के लिए सहयोग और इस वैश्विक चुनौती का सामना करने के लिए वित्तीय सहयोग को प्रोत्साहित करेगा।

2015-2020 अंतरिक्ष सहयोग कार्यक्रम पर सहमति बनने से दोनों एशियाई देशों के बीच में आपसी सहयोग के नए रास्ते खुले हैं। एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में चीन ने पहली बार भारत के नाभिकीय आपूर्ति समूह में सम्मिलित होने की आकांक्षा को गंभीरता से लिया है। चीन ने भारत की वैश्विक आकांक्षाओं के लिए अपने समर्थन को दोहराया है पर वह अभी भी भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता पर अपना सुस्पष्ट समर्थन नहीं दे पाया है। चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता में भारत के समर्थन से भारत-चीन के बदलते रिश्तों में बड़ा बदलाव आ सकता है और दोनों देशों के बीच अविश्वास के उस अंतर को भर सकता है जो दोनों देशों के बीच संवाद में रुकवाट बना हुआ है।

आगे की ओर देखें तो कोई भी दो एशियाई देशों से इन द्विपक्षीय आयामों में परिवर्तन की अपेक्षा कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय शान्ति, सुरक्षा और विकास को प्रभावित करने वाले विकास पर सक्रिय सलाहों के द्वारा क्षेत्रीय एवं वैश्विक एजेंडे को आकार देने के लिए वृहद आयामों की भी अपेक्षा कर सकता है। प्रधानमंत्री के चीन दौरे के दौरान जिस प्रकार से दो प्रमुख शक्तियों का मिलन हुआ है वह इस महत्वपूर्ण प्रतिभागिता का निर्माण करेगा क्योंकि एशिया के ये दो शेर इस सदी को एशियाई सदी बनाने के अपने वादे को पूरा करने के लिए पूरे क्षेत्र के साथ अपने बढ़ते आर्थिक मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय छवि का विस्तार करेंगे। हालांकि कुछ खतरे भी हैं जिनसे दोनों देशों को सावधान रहना होगा, असुलझा सीमा विवाद दोनों में तनाव और अविश्वास का कारण बना हुआ है, जिसे इस महत्वपूर्ण संबंधों के लंबे परिदृश्य का विस्तार कर सुलझाने की जरूरत है। अगर यह अविश्वास जारी रहता है तो यह आर्थिक संबंधों को पटरी से उतार सकता है। चीन को भारतीय कंपनियों तक अपने बाज़ार को पहुंचाने के अपने वादे पर खरे उतरने की जरूरत है, खास तौर पर आईटी, फार्मा और फूड सेक्टर में। इस उभरते हुए आर्थिक संबंधों की दीर्घ अवधि शक्ति के लिए चीन के दीर्घ अवधि निवेश के लिए योजनाएं और औद्योगिक पार्क की स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों ही देशों को तीसरे देशों के साथ अपने संबंधों के बारे में अपनी चिंताओं के बारे में भी समाधान करने की जरूरत है। भारत और चीन संबंधों के निरंतर परिवर्तन ने अब रचनात्मक मोड़ लिया है और वे अब इन समस्याओं का समाधान करने के लिए इच्छुक हैं। जैसे एक चीनी कहावत है कि हजारों मील का सफर एक छोटे से कदम के साथ शुरू होता है, कई छोटे छोटे कदम लिए जा चुके हैं और अब इन दोनों ही देशों के लिए जरूरी है कि वे अपनी सीमाओं का विस्तार करें, भारत और चीन के संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए लचीलापन और कल्पना दिखाएं और उसे प्रतिस्पर्धात्मक महत्वाकांक्षा और भू-राजनीति के दबाव से अलग निकाल कर देख सके।

चीन को भारतीय कंपनियों तक अपने बाज़ार को पहुंचाने के अपने वादे पर खरे उतरने की जरूरत है, खास तौर पर आईटी, फार्मा और फूड सेक्टर में। इस उभरते हुए आर्थिक संबंधों की दीर्घ अवधि शक्ति के लिए चीन के दीर्घ अवधि निवेश के लिए योजनाएं और औद्योगिक पार्क की स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों ही देशों को तीसरे देशों के साथ अपने संबंधों के बारे में अपनी चिंताओं के बारे में भी समाधान करने की जरूरत है।

(शेषांश पृष्ठ 40 पर)

आर्थिक विकास के लिए राजनय

राम उपेंद्र दास

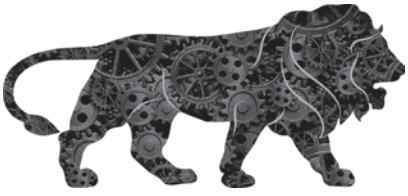

'मेक इन इंडिया' ऐसा कार्यक्रम है, जो घरेलू माना जाता है, लेकिन निश्चित रूप से जिसके बाहरी आयाम हैं। विनिर्माण क्षेत्र के विकास की गति बढ़ाने एवं रोजगार के अवसर तैयार करने के लक्ष्य से आरंभ इस कार्यक्रम पर विदेशों में बहुत ध्यान दिया गया है। यह देखते हुए कि भारत इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक आकर्षक ठिकाना है, 'मेक इन इंडिया' जैसा प्रयास आर्थिक विकास के और ऊंचे स्तर प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। किंतु इसके लिए विनिर्माण क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों से जोड़ने वाली एकीकृत नीति अपनाने की आवश्यकता होगी और इससे जुड़े बाहरी आयामों की स्पष्ट समझ भी रखनी होगी

भारत की आर्थिक वैश्विक गतिविधियां नए रास्ते पर पहुंच गई हैं और भविष्य में इनमें प्रगति होने की संभावना है। इन्हें स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में जटिल एवं विविध प्रकार के संपर्क शामिल होते हैं। नीति निर्माण की प्रक्रिया तथा बाज़ार से प्रेरित होने वाली घटनाओं पर इनका महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। कूटनीति एवं आर्थिक कूटनीति को इस संदर्भ में नए अर्थ मिल जाते हैं।

आर्थिक कूटनीति का नया संदर्भ

एक परिभाषा के अनुसार स्वतंत्र देशों की सरकारों के मध्य आधिकारिक संबंधों को निभाते समय खुफिया जानकारी एवं तरकीबों का प्रयोग कूटनीति माना जाता है। (सैटो, 1961) किंतु समय के साथ अब कूटनीति के दायरे में नए पहलू शामिल हो गए हैं। पहली बात, देशों के बीच संपर्क केवल सरकारों के बीच के आधिकारिक संपर्क तक सीमित नहीं रह गया है। उसके बजाय लोगों के बीच संपर्क भी बढ़ा है, जिसमें संचार प्रौद्योगिकियों तथा यात्रा सुविधाओं के नए साधनों ने सहायता की है। दूसरी बात, देशों के बीच संपर्क की जो प्राथमिक संभावना राजनीतिक, सैन्य एवं रणनीतिक सहयोग के क्षेत्र में होती थी, आर्थिक वैश्वीकरण और उदारीकरण के दौर में या तो आर्थिक संपर्क उनकी जगह लेता जा रहा है अथवा उनमें शामिल होता जा रहा है। भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की ये दो विशेषताएं आर्थिक कूटनीति को अग्रणी मंच पर ले आई हैं।

बहुस्तरीय, क्षेत्रीय एवं द्विपक्षीय स्तरों पर संस्थागत घटनाक्रमों से भी आर्थिक कूटनीति को अधिक महत्ता मिल गई है। इनमें ब्रेटन वुड्स संस्थानों से मोहभंग होना, संयुक्त राष्ट्र संघ के छाते तले किसी सार्थक आर्थिक सहयोग के लिए कम गुंजाइश होना और दोहा दौर समेत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की वार्ता में पर्याप्त प्रगति नहीं होना शामिल हैं। दूसरी ओर द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय आर्थिक संपर्क अभूतपूर्व गति से बढ़े हैं। वस्तुओं के व्यापार के साथ-साथ सेवाओं में व्यापार एवं निवेश के लिए आर्थिक सहयोग समझौतों को शामिल करने से उनकी प्रकृति और भी समग्र हो गई है। वे बातचीत में तेज हैं और स्वत: स्फूर्त शक्ति बनकर उभरे हैं। (दास एवं अन्य, 2012) इनसे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आर्थिक कूटनीति की विभिन्न रणनीतियां विकसित करने के अधिक कारण मिले हैं और भारत भी अपवाद नहीं है।

परिवर्तन की अनिवार्यता: शांति लाने वाली संपन्नता की ओर

यह बताना महत्वपूर्ण है कि यदि आर्थिक कूटनीति को अधिक प्रभावी बनाना है तो दूसरे देशों के साथ हमारे संपर्कों में बदलाव की आवश्यकता है। इसका अर्थ है आर्थिक कूटनीति को द्विपक्षीय स्तर पर अथवा किसी विशेष क्षेत्र में शांति बहाल करने में सहायता के लिए इस्तेमाल करना और ऐसा करने के

लेखक नई दिल्ली स्थित संस्था रिसर्च ऐंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज में प्रोफेसर हैं। वह वर्ल्ड वाच संस्था के मानद फेलो भी हैं। न्यू देल्ही मैनेजमेंट के सदस्य हैं एवं बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के अकादमिक सलाहकार परिषद से भी जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा विकाय योजनाओं के क्षेत्र में उन्हें बेहद अनुभव हासिल है। उन्होंने एडीबी, राष्ट्रमंडल सचिवालय, आईएलओ, एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया, दक्षेस सचिवालय, यूएनडीपी, यूनेस्को और वर्ल्ड बैंक जैसे कार्यक्रमों का निरीक्षण और आयोजन भी करवाया। प्रस्तुत लेख में उनके निजी विचार हैं। ईमेल: upendra@ris.org.in, ट्विटर: @upendra900

लिए आर्थिक कूटनीति को 'शांति स्थापित करने वाली संपन्नता' पर केंद्रित करना होगा। इसका अर्थ है कि पहले अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने और आर्थिक संबंधों के ऊंचे स्तरों तक ले जाने का प्रयास करने के बजाय इस संदर्भ में भी प्रयास होने चाहिए जहां द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय संबंधों के माध्यम से आर्थिक संपन्नता को शांति स्थापित करने पर केंद्रित किया जा सकता है, जो बदले में वैश्विक शांति स्थापित करने की दिशा में कारक का कार्य कर सकती है। इस संदर्भ में प्रासंगिक साहित्य देखना महत्वपूर्ण है, जो इस बदलाव को अधिक मुखर एवं आर्थिक कूटनीति के लिए प्रासंगिक बनाता है।

फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्तेस्क्यू (1748) के अनुसार शांति "वाणिज्य का प्राकृतिक प्रभाव" है। इतालवी अर्थशास्त्री परेतो (1889) का तर्क था कि सीमा-शुल्कों का संघ बनने से देशों के बीच शांति स्थापित करने में सहायता

किसी देश का अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ संघर्ष होने की आशंका कम होती है क्योंकि देशों के बीच समझौतों से होने वाला व्यापारिक लाभ खोना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, राज्यों के बीच संघर्ष पर व्यापारिक एकीकरण का प्रभाव दोनों राज्यों की विशेषताओं के आधार पर अलग-अलग हो सकता है।

हो सकती है। ये कथन दिखाते हैं कि यह बात बहुत पहले अनुभव कर ली गई थी कि क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण सदस्य देशों के बीच शांति स्थापित कर सकता है। (जैसा शिफ और विंटर्स 2003 में लिखा है, पृष्ठ 189)

ब्राउन एवं अन्य (2005) के अनुसार कई तथ्य हैं, जो बताते हैं कि क्षेत्रीय व्यापार एकीकरण शांतिपूर्ण परिणाम ला सकता है। उनमें से कुछ हैं: (क) आर्थिक एकीकरण के बाद किसी भी देश के लिए संघर्ष महंगा पड़ता है क्योंकि व्यापार से होने वाले उसके लाभ प्रभावित होते हैं, (ख) क्षेत्रीय सहयोग मजदूरों के शोषण से निकाले जाने वाले हीरों (ब्लड डायमंड) और अवैध लकड़ी जैसे व्यापार में टकराव वाले संसाधनों को कम करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए 1998 में इकनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीका स्टेट्स (इकोवास) ने अन्य सदस्य देशों से मंजूरी के बगैर नए हथियारों का आयात प्रतिबंधित करते हुए छोटे हथियारों पर दुनिया की पहली क्षेत्रीय रोक लगाई। (ग) क्षेत्रीय व्यापार समझौते विवादों के समाधान के असैन्य तरीके उपलब्ध कराते हैं और देशों के बीच समझ एवं बातचीत को बढ़ावा देते हैं।

ली एवं प्युन (2009) के अनुसार मॉन्तेस्क्यू, कांत, एंजल और शुम्पीटर समेत राजनीति विज्ञान में "उदार शांति" का विचार इस बात पर जोर देता है कि पारस्परिक आर्थिक स्वतंत्रता शांति का मार्ग हो सकती है। इससे पता चलता है कि द्विपक्षीय आर्थिक अंतरनिर्भरता राज्यों के बीच संबंधों में सैन्य शक्ति के प्रयोग को कम करता है। किसी देश का अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ संघर्ष होने की आशंका कम होती है क्योंकि देशों के बीच समझौतों से होने वाला व्यापारिक लाभ खोना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, राज्यों के बीच संघर्ष पर व्यापारिक एकीकरण का प्रभाव दोनों राज्यों की विशेषताओं के आधार पर अलग-अलग हो सकता है। शिफ और विंटर्स (1998) के अनुसार पड़ोसी देशों के बीच व्यापार देशों के बीच विश्वास एवं संपर्क बढ़ाकर सुरक्षा को मजबूत करता है। क्षेत्रीय व्यापार समझौते (आरटीए) पर हस्ताक्षर करने हैं या नहीं, यह फैसला करने के लिए विभिन्न प्रणालियों का चित्रण करने हेतु मार्टिन एवं अन्य (2010) एक सामान्य सैद्धांतिक ढांचा प्रयोग करते हैं। सामान्य व्यापारिक लाभों के अतिरिक्त राजनेता शांति को बढ़ावा देने वाली सुरक्षा के दो प्रकार के लाभों पर विचार करते हैं: (क) राजनीतिक मंच के रूप में काम करने वाले आरटीए, जो विवाद निपटारे में सहायता करते हैं और (ख) व्यापार कम करने वाले संभावित युद्ध से होने वाली हानि को बढ़ाने वाले आरटीए।

सदस्य देशों के बीच शांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई व्यापारिक समझौते तैयार किए गए हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ (आसियान) और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (दक्षेस) जैसे क्षेत्रीय समूहों का आरंभ गैर आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग के साथ हुआ और औपचारिक व्यापारिक समझौतों के रूप में आर्थिक एजेंडा उनकी बातचीत में बहुत बाद में आया। इसी प्रकार मर्कोसर की स्थापना वास्तव में अर्जेंटीना एवं ब्राजील के बीच तनाव कम करने के लिए की गई थी। युद्ध से बर्बाद बाल्कन क्षेत्र में आर्थिक बहाली एवं एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2000 में दक्षिण-पूर्वी यूरोप में मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के प्रयास हुए। 2004 में मिस्र और इजरायल ने अमेरिका के साथ व्यापार प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में पांच विशेष क्षेत्र स्थापित करने की बात भी थी, जहां मिस्र के उत्पादों की अमेरिकी बाज़ार में तब तक बेरोकटोक आवाजाही होती रहेगी, जब तक उनमें 35 फीसदी वस्तुएं इजरायल एवं मिस्र के साझे प्रयासों से बनी हों। (ब्राउन एवं अन्य, 2005) यह माना और कहा जाता है कि अफ्रीका में हिंसक संघर्षों को देखते हुए क्षेत्रीय व्यापार समझौते टकराव के स्रोत को कम से कम संघर्ष खत्म कर सकते हैं। इससे पड़ोसी देशों के मध्य शंका कम होगी। क्षेत्रीय समझौतों में शामिल होने से मिलने वाले लाभ देशों के मध्य टकराव खत्म कर

मर्कोसर की स्थापना वास्तव में अर्जेंटीना एवं ब्राजील के बीच तनाव कम करने के लिए की गई थी। युद्ध से बर्बाद बाल्कन क्षेत्र में आर्थिक बहाली एवं एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2000 में दक्षिण-पूर्वी यूरोप में मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के प्रयास हुए। 2004 में मिस्र और इजरायल ने अमेरिका के साथ व्यापार प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।

सकते हैं। (अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, 2000)

यह आलेख बताता है कि क्षेत्रीय व्यापारिक समझौते से सदस्य देशों के मध्य सैन्य संघर्ष कम होते हैं और शांति को बढ़ावा मिलता है।

अन्योनाश्रय आंतरिक व बाह्य संबंध

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में देखा जाना चाहिए और जो आर्थिक कूटनीति के पक्ष में तर्क देने के लिए बहुत प्रासंगिक है और वह है घरेलू आर्थिक अनिवार्यताओं एवं विदेशी आर्थिक वातावरण के बीच संबंध।

यह संबंध दोनों दिशाओं में चलता है और उससे घरेलू तथा बाहरी आर्थिक मानदंडों में घालमेल हो जाता है। आर्थिक कूटनीति विदेशी आर्थिक मसलों से संबंधित है। सिद्धांत रूप में इससे विश्लेषण सरल हो जाना चाहिए। लेकिन क्या 'घरेलू' है और क्या 'अंतर्राष्ट्रीय',

इसके बीच स्पष्ट रेखा खींचना लगातार कठिन होता जा रहा है। 1950 के दशक से आर्थिक अंतरनिर्भरता में वृद्धि, जो हाल के वर्षों में तेज हुई है, का अर्थ है कि जिसे पहले घरेलू (अथवा यूरोपीय) माना जाता था, वह अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं से संचालित होता है। (बेन एवं वूलकॉक, 2003) इसे देखते हुए भारत के घरेलू आर्थिक विकास के कुछ प्रयासों को विदेशी संदर्भ में रखना महत्वपूर्ण होगा ताकि आर्थिक कूटनीति को और तटस्थ तरीके से समझा जा सके।

'मेक इन इंडिया' के विदेशी आयाम

भारतीय प्रधानमंत्री का 'मेक इन इंडिया' प्रयास भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत समय से अनुभव की जा रही आवश्यकता को पूरा करता है। किंतु जब यह विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि एवं रोजगार सृजन पर जोर देता है तो गलती से अक्सर इसे केवल केवल 'घरेलू अर्थव्यवस्था' की ओर लक्षित मान लिया जाता है। ऐसा हो सकता है किंतु इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण विदेशी आयाम हैं और विनिर्माण क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों से अलग नहीं माना जा सकता। अनुमान कम से कम रखा जाए तो भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवाजाही के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार प्रवाह इस समय भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधे से भी अधिक है। बाहरी क्षेत्र का प्रभुत्व विभिन्न प्रकार के कारकों से होता है, जैसे विनिर्माण एवं सेवाओं में तुलनात्मक एवं प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभों, विदेशी पूंजी, प्रौद्योगिकी, कौशल एवं प्रबंधकीय विशेषज्ञता, क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला आदि पर विचार। विशेषकर आर्थिक कूटनीति एवं इसके आयाम तैयार करने के लिए 'मेक इन इंडिया' में निहित घरेलू एवं विदेशी आयामों के अर्थशास्त्र एवं उनके बीच सबंधों को अच्छी तरह समझना अनिवार्य है।

बाहरी क्षेत्र का प्रभुत्व विभिन्न प्रकार के कारकों से होता है, जैसे विनिर्माण एवं सेवाओं में तुलनात्मक एवं प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभों, विदेशी पूंजी, प्रौद्योगिकी, कौशल एवं प्रबंधकीय विशेषज्ञता, क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला आदि पर विचार। विशेषकर आर्थिक कूटनीति एवं इसके आयाम तैयार करने के लिए 'मेक इन इंडिया' में निहित घरेलू एवं विदेशी आयामों के अर्थशास्त्र एवं उनके बीच सबंधों को अच्छी तरह समझना अनिवार्य है।

यह समझना आसान है कि 'वृद्धि के वाहक' के रूप में विनिर्माण विशाल पैमाने के कारण उत्पादकता एवं रोजगार पर प्रभाव डालते हुए आपूर्ति एवं मांग पक्षों की वृद्धि में में योगदान करता है। अध्ययनों से पता चला है कि विनिर्माण में उत्पादन में विशेषज्ञता, नए प्रयोगों तथा रोजगार सृजन के जरिए वृद्धि को बढ़ावा देने वाली विशेषताएं होती हैं। चूंकि बाज़ार का आकार छोटा होने अर्थात् मांग कम होने से बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव नहीं होने तथा उत्पादकता एवं प्रौद्योगिकी संबंधी बाधाओं अर्थात् आपूर्ति पक्ष सीमित होने से विशेषज्ञता की समिति संभावना होने के कारण किसी भी देश में विनिर्माण सदैव वृद्धि का कारण नहीं बन सकता, इसलिए व्यापार एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के बीच क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण व्यावहारिक विकल्प बन जाता है।

ऐसा इसलिए है चूंकि विनिर्मित वस्तुओं के संबंध में शुल्क एवं गैर शुल्क उदारीकरण तथा संवाओं में नियमों के उदारीकरण से साझेदार देशों में बाज़ार तक पहुंच बढ़ती है और मांग के पक्ष की बाधाएं दूर हो जाती हैं। दूसरी ओर आपूर्ति पक्ष की बाधाएं क्षेत्रीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सहयोग के माध्यम से खत्म की जा सकती हैं, जिससे न केवल वित्तीय संसाधन आ सकते हैं बल्कि क्षेत्रीय स्थितियों के अनुरूप प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधकीय तथा तकनीकी कौशल भी प्राप्त हो सकता है लेकिन यह स्पष्ट है कि विनिर्माण को विकास का संवाहक बनाने के लिए क्षेत्रीय व्यापार एवं निवेश एकीकरण के प्रति एकीकृत प्रयास आवश्यक हो सकता है। बदले में ये आर्थिक विकास में योगदान करेंगे, जिसके लिए आर्थिक कूटनीति को क्षेत्रीय एकीकरण के अर्थशास्त्र को ध्यान में रखना होगा।

इस विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए विनिर्मित वस्तुओं में व्यापार को तब तक बढ़ाया नहीं जा सकता, जब तक सेवाओं में एक दूसरे से जुड़े हुए व्यापार में सहयोग की संस्थागत प्रणाली मौजूद नहीं होगी। उदाहरण के लिए वस्तुओं में व्यापार माल की लदाई के बाद के क्रेडिट, माल के बीमा, बैंक गारंटी, परिवहन सेवाओं आदि जैसी सेवाओं पर निर्भर करता है, जो न केवल व्यापार को सुविधाजनक बनाती हैं बल्कि निर्यात की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में भी योगदान करती हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में सेवाओं में व्यापार इस सेवा क्षेत्र से संबंधित वस्तुओं जैसे चिकित्सा उपकरण एवं दवाओं, जिन पर स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को विश्वास है, पर निर्भर रहता है। इस प्रकार किसी भी क्षेत्रीय व्यापार समझौते वस्तुओं एवं सेवाओं में व्यापार के बीच दोतरफा संबंधों को पहचानने की आवश्यकता होती है। किंतु वास्तव में इसका उलटा भी देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए रियल्टी क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र में मूर्त एवं अमूर्त के बीच लगातार बढ़ते अलगाव के कारण वस्तुओं में व्यापार तथा सेवाओं में व्यापार वृद्धि के अलग-अलग रास्तों पर चलता है। किसी भी स्थिति में वस्तुओं तथा सेवाओं में व्यापार के स्वायत्त प्रवाह का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस तर्क को इस तथ्य से बल मिलता है कि ढांचागत सेवाओं के उन्नयन में सहयोग से सौदों की लागत में कमी होती है और क्षेत्रीय संदर्भ में उत्पाद सस्ते हो जाते हैं।

इस प्रकार किसी भी क्षेत्रीय व्यापार समझौते वस्तुओं एवं सेवाओं में व्यापार के बीच दोतरफा संबंधों को पहचानने की आवश्यकता होती है। किंतु वास्तव में इसका उलटा भी देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए रियल्टी क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र में मूर्त एवं अमूर्त के बीच लगातार बढ़ते अलगाव के कारण वस्तुओं में व्यापार तथा सेवाओं में व्यापार वृद्धि के अलग-अलग रास्तों पर चलता है।

यह भी मानने की आवश्यकता है कि क्षेत्रीय व्यापार का उच्च स्तर प्राप्त करने और विकास पर उसके प्रभाव को महसूस करने के लिए व्यापार-निवेश संपर्कों को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। ऐसे संपर्क किसी क्षेत्रीय समूह में देशों की निर्यात आपूर्ति संबंधी क्षमताओं को सुधारने में मदद करते हैं। क्षेत्रीय दायरे में व्यापारिक उदारीकरण का लाभ उठाने के लिए निवेश करने से उनके कारण रोजगार का अधिक सृजन भी होता है। मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) क्षमता बढ़ाने वाले क्षेत्रीय पुनर्गठन के मामले में निवेश का प्रवाह बढ़ा

सकता है, लेकिन क्षेत्रीय व्यापार प्रवाह पर निर्णायक प्रभाव व्यापार सृजन करने वाले साझे उपक्रमों का ही होता है। व्यापार सृजन करने वाले साझे उपक्रम क्षेत्रीय एफटीए का लाभ उठाने की स्थिति में होते हैं। विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि की गति पर इनका सीधा प्रभाव होता है।

इस संदर्भ में यदि देशों के बीच व्यापार निवेश संपर्कों को मजबूत बनाने वाले निवेश के प्रवाह की मदद से लंबवत एकीकरण तथा क्षैतिज विशेषज्ञता पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो अधिक व्यापार एवं निवेश प्रवाह का लाभ मिलेगा, जिससे रोजगार का अधिक सृजन संभव हो सकेगा। इसका अर्थ किसी विशेष उद्योग में उत्पादन के विभिन्न चरणो को एकीकृत तरीके अर्थात् लंबवत तरीके से क्षेत्र विशेष में वितरित करना और उत्पादन के उसी चरण में विशेषज्ञता को क्षेत्र भर में उत्पादों की विविधता के अनुसार अर्थात् क्षैतिज तरीके से वितरित करना हो सकता है। क्षेत्रीय स्तर पर संयोति ऐसे विनिर्माण, जो रोजगार सृजन के सकारात्मक परिणामों के साथ विकास का संवाहक बन सके, का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय संदर्भ में क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला बनाने हेतु ऊपर दिए गए विचार महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

उद्भव के नियम का प्राथमिक कार्य एफटीए में व्यापार का विचलन उस समय रोकना है, जिस समय उत्पाद का उद्भव सुनिश्चित करने वाले विभिन्न तरीकों का लक्ष्य सामग्री अर्थात् इनपुट में बड़ा परिवर्तन करना होता है। किंतु इस बात पर ध्यान नहीं जाता है कि उद्भव के ये नियम और उनके तरीके एक साथ मिलकर विनिर्माण करने वाले देश में मूल्य वर्द्धन में सहायता करते हैं और रोजगार सृजन करते हुए विकास में भूमिका अदा करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि विनिर्माण की प्रक्रिया में मूल्य वर्द्धन से कंपनियों में कामगारों को मजदूरी और वेतन, पूंजी पर ब्याज, भूमि का किराया तथा उद्यमियों को लाभ प्राप्त होता है। इसका अर्थ यही है कि विनिर्माण में जितना अधिक मूल्य वर्द्धन होगा, विनिर्माण में केवल श्रमिकों नहीं बल्कि सभी कारकों को शामिल करने की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। अधिक मूल्य वर्द्धन ही उद्यमियों को अधिक लाभ प्रदान करने का रास्ता है। संक्षेप में, एफटीए के अंतर्गत उद्भव के नियम विनिर्माण को बढ़ावा देकर तथा रोजगार सृजन कर विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं।

इस प्रकार यदि विनिर्माण को अन्य क्षेत्रों के साथ एकीकृत रूप में देखा जाए और उद्भव के नियमों जैसे बाहरी आयामों को ठीक से समझा जाए तो 'मेक इन इंडिया' अभियान अचूक बाण हो सकता है। यह दर्शाना कठिन नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों का अर्थशास्त्र ही आर्थिक कूटनीति का आधार होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार का प्रयास अंत में आर्थिक कूटनीति को रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन एवं लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने जैसे आर्थिक विकास के उद्देश्य प्राप्त करने में मदद का माध्यम बनाने के लिए ही होता है।

निष्कर्ष

ऊपर की बातों से स्पष्ट है कि आर्थिक कूटनीति का आशय बहुत बदल गया है और सरकारों के स्तर की पारंपरिक वार्ता एवं राजनीतिक तथा सैन्य संपर्क के अलावा लोगों के बीच संपर्क एवं देशों के मध्य आर्थिक संपर्क इसमें शामिल हो गया है। इस प्रकार आर्थिक कूटनीति को बेहतर आर्थिक संपर्क के माध्यम से द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय स्तरों पर शांति बहाल करने के उपकरण के रूप में प्रयोग करना अधिक सार्थक होगा, जैसा इस लेख में भी बताया गया है। यह भी देखा गया कि देसी एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच स्पष्ट विभेद करना कठिन है क्योंकि कारण दोनों ही दिशाओं में चलते हैं। 'मेक इन इंडिया' ऐसा ही कार्यक्रम है, जो घरेलू माना जाता है, लेकिन निश्चित रूप से जिसके बाहरी आयाम हैं। विनिर्माण क्षेत्र के विकास की गति बढ़ाने एवं रोजगार के अवसर तैयार करने के लक्ष्य से आरंभ इस कार्यक्रम पर विदेशों में बहुत ध्यान दिया गया है। यह देखते हुए कि भारत इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक आकर्षक ठिकाना है, 'मेक इन इंडिया' जैसा प्रयास आर्थिक विकास के और ऊंचे स्तर प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। किंतु इसके लिए विनिर्माण क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों से जोड़ने वाली एकीकृत नीति अपनाने की आवश्यकता होगी और इससे जुड़े बाहरी आयामों की स्पष्ट समझ भी रखनी होगी।

यदि विनिर्माण अन्य क्षेत्रों के साथ एकीकृत रूप में देखा जाए और उद्भव के नियमों जैसे बाहरी आयामों को ठीक से समझा जाए तो 'मेक इन इंडिया' अभियान अचूक बाण हो सकता है। यह दर्शाना कठिन नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों का अर्थशास्त्र ही आर्थिक कूटनीति का आधार होना चाहिए।

इसलिए अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं एवं विदेश नीति के लक्ष्यों में आर्थिक बिंदुओं को आर्थिक कूटनीति के अंग के रूप में शामिल करना महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में भारत की विदेश नीति को देसी आर्थिक प्राथमिकताओं से जोड़ने के लिए एवं आर्थिक विकास तथा विश्व में बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की संभावना को महसूस करने के लिए आर्थिक आर्थिक कूटनीति को माध्यम के रूप में प्रयोग करना अपरिहार्य हो जाता है। ❑

संदर्भ

1. **अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक (2000):** अफ्रीकन डेवलपमेंट रिपोर्ट, न्यूयॉर्क: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
2. **बेन, एन और वूलकॉक, एस (2003):** दि न्यू इकनॉमिक डिप्लोमैसी, हैंपशर, ऐशगेट
3. **ब्राउन, ओ, शाहीन, एफ एच, खान, एस आर और यूसुफ, एम (2005):** रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स: प्रमोटिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑर बिल्डिंग पीस? अक्टूबर, कनाडा: आईआईएसडी
4. **दास, राम उपेंद्र (2013):** व्यासदेव दासगुप्त द्वारा संपादित एक्सटर्नल डाइमेंशन्स ऑफ एन इमर्जिंग इकॉनॉमी, इंडिया, लंदन एवं न्यूयॉर्क: रूटलेजमें 'रीजनल इकनॉमिक इंटीग्रेशन: न्यू कॉन्टेक्स्ट एंड एनालिटिकल कंस्ट्रक्ट्स'
5. **दास, राम उपेंद्र, एदिसूर्य, पी और स्वरूप, ए (2012):** रीजनल ट्रेड एंड इकनॉमिक इंटीग्रेशन: एनालिटिकल इनसाइट्स एंड पॉलिसी ऑप्शन्स, सिंगापुर और न्यूयॉर्क: वर्ल्ड साइंटिफिक
6. **ली, जे-डब्ल्यू और प्युन, जे एच (2009):** डज ट्रेड इंटीग्रेशन कंट्रिब्यूट टु पीस? एडीबी वर्किंग पेपर सीरीज ऑन रीजनल इकनॉमिक इंटीग्रेशन नंबर 24
7. **मार्टिन, पी, मेयर, टी और थोनिग, एम (2010):** द जियोग्राफी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स: इफ यू वांट पीस, प्रिपेयर फॉर ट्रेड। इंस्टीट्यूट डी फ्रांस और एएनआर की शोध परियोजना के अंग के रूप में तैयार किया गया पत्र (http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/gtdw_e/wkshop09_e/thoenig_e.pdf)
8. **मॉन्तस्क्यू (1748):** मॉन्तस्क्यूज पैराडॉक्सिकल इकनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्दियू 3
9. आरआईएस, साउथ एशिया डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन रिपोर्ट 2015, नई दिल्ली
10. **साटो, ई (1961):** अ गाइड टु डिप्लोमैटिक प्रैक्टिस, लंदन: लॉन्गमैन्स
11. **शिफ, एम और एल ए विंटर्स (1998):** डायनमिक एंड पॉलिटिक्स इन रीजनल इंटीग्रेशन अरेंजमेंट्स: एन इंट्रोडक्शन, द वर्ल्ड बैंक इकनॉमिक रिव्यू 12(2): 177-95
12. **शिफ, एम और एल ए विंटर्स (2003):** रीजनल इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट, वॉशिंगटन डीसी: द वर्ल्ड बैंक

रक्षा समझौते: अंतर्राष्ट्रीय संबंध के वाहक

आलोक बंसल

दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भारत के रक्षा सहयोग में काफी विस्तार हुआ है। यह उज्जवल भविष्य से जुड़ा हुआ है, जो भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की परिकल्पना है, साथ ही भारत के रक्षा बलों में बढ़ रही आस्था से भी जुड़ा है। ज्यादा से ज्यादा देश अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत के साथ होना चाहते हैं। आने वाले दिनों में इस सहयोग में और बढ़ोतरी होगी तथा 'यह मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को एक सुदृढ़ आधार प्रदान करेगा, जिसमें भारत को रूपांतरित करने की असीम संभावना है

अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में भारत ने पिछले एक साल में नई ऊंचाइयां तय की हैं। हालांकि इस समयांतराल में सभी क्षेत्रों में भारत का प्रदर्शन चौतरफा विकास वाला रहा है लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में रही है। यह अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस एक वर्ष के दौरान विश्व समुदाय में भारत की हैसियत बढ़ी है। सुरक्षा और विदेश नीति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा परिणामस्वरूप किसी राष्ट्र राज्य की सुरक्षा चिंताएं उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को तय करती हैं। रक्षा तैयारी सुरक्षा के प्रमुख घटकों में से एक है। यह आलेख इस बात पर प्रकाश डालता है कि किस तरह राजग सरकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसकी सुरक्षा चिंताओं से प्रभावित है, विशेष रूप से देश की रक्षा तैयारी को बढ़ाने की आवश्यकता पर किस हद तक जोर है।

यह वास्तविकता ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत रक्षा क्षेत्र में सहयोग करने वाला सैन्य साज-ओ-सामान का सबसे बड़ा आयातक देश है, यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि अतीत में टकराव के मौकों पर हम सैन्य आपूर्ति से वंचित किए गए हैं तथा बाकी समय भारत पर इस बात का दबाव बनाया जाता रहा है कि भारत अपनी नीतियों में बदलाव लाए। दूसरी वास्तविकता के सबसे प्रमुख उदाहरणों में से एक है पोखरन II के बाद भारत पर प्रतिबंध कायम किया जाना। इन ठहरावों का परिणाम अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में भारत की रक्षा सहायता में कटौती के रूप में सामने आया है। सरकार ने भारत के ढांचे का इस्तेमाल रक्षा सामानों के सबसे बड़े आयातक के रूप में 'मेक इन इंडिया' की खातिर विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए किया। कंपनियां एक बड़े निर्माण आदेश तथा सस्ते श्रम के प्रति आश्वस्त होंगी, जबकि भारत की सुरक्षा आवश्यक उपकरणों को लेकर भरोसेमंद होगी, साथ ही साथ इससे रोजगार सृजन की संभावनाओं को भी बल मिलेगा क्योंकि इससे भारत में कई तकनीकों की आमद होगी। हालांकि रक्षा तकनीकें साधारणतया विभिन्न प्रतिबंधात्मक शासनों द्वारा नियंत्रित होती हैं, ऐसे में आवश्यक है कि सरकार विदेशी सरकारों के साथ बातचीत करे ताकि इन तकनीकों की राह में आने वाली रुकावटों को दूर किया जा सके।

राजग सरकार ने सत्ता में आते ही अपने पड़ोसी देशों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया तथा उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की कि भारत का विशाल रक्षा बल किसी को डराने-धमकाने के लिए नहीं है, बल्कि प्राकृतिक आपदा तथा अन्य वैश्विक आपदा के समय उनकी मदद करने के लिए है, जैसा कि भारतीय सेना ने भूकंप पीड़ित नेपाल की सहायता में अपनी अग्रिम भूमिका निभाई है। ठीक उसी तरह, इराक तथा यमन में संघर्ष क्षेत्रों से भारतीय फौज पड़ोसी देशों के नागरिकों को निकालकर बाहर सुरक्षित ले आई। यह साल इस बात का भी गवाह है

लेखक इंडिया फाउंडेशन में सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजी के निदेशक हैं साथ ही वह साऊथ एशियन इंस्टिट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक अफेयर्स के मानद कार्यकारी निदेशक, न्यू देल्ही इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर भी हैं। वह एक दशक से ज्यादा समय से विभिन्न थिंक टैंक के साथ जुड़े रहे। इससे पहले वे भारतीय नौ सेना में कमीशंड ऑफिसर रहे। ईमेल: alokbansal_nda@yahoo.co.in

कि किस तरह भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई देशों के साथ सामरिक भागीदारी की है तथा मौजूदा सामरिक भागीदारी को और मजबूत किया है।

दक्षिण एशिया के बाहर प्रधानमंत्री ने पहले द्विपक्षीय विदेशी दौरे के दौरान, भारत-जापान द्विपक्षीय संबंध को 'विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी' के स्तर तक पहुंचाया तथा रक्षा क्षेत्र में सहयोग और आदान-प्रदान के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और जापान ने विचार-विमर्श की शुरुआत करते हुए सैन्य उपकरण सहयोग को बढ़ावा देने की शुरुआत करते हुए तथा जापानी यूएस-2 उभयचर विमान की बिक्री के लिए तौर तरीकों पर विचार-विमर्श में तेजी लाते हुए अपने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने तथा उसे मजबूत करने का निर्णय भी लिया। रक्षा प्रौद्योगिकी और उपकरणों में सहयोग, शांति और स्थिरता तथा समुद्री सुरक्षा में अपने साझा हितों के दोहराने समेत संयुक्त विज्ञप्ति में रक्षा सहयोग के लिए एक नया जोर और नई दिशा देने के लिए दोनों देशों के इरादों का संकेत दिखा। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जापान ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एलएएल) तथा पांच अन्य भारतीय संस्थाओं पर से प्रतिबंध उठा लिया, जो प्रतिबंध 1998 के परमाण ु परीक्षण के बाद लगाया गया था। नौसैनिक अभ्यास की भारत-अमेरिका मालाबार श्रृंखला में जापान की निरंतर भागीदारी के साथ-साथ दोनों देश नियमित द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास पर भी सहमत हुए। प्रधानमंत्री ने जापानी उद्योगों को 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत निवेश करने का आह्वान किया तथा हर तरह की मदद का आश्वासन दिया।

जापान ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एलएएल) तथा पांच अन्य भारतीय संस्थाओं पर से प्रतिबंध उठा लिया, जो प्रतिबंध 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद लगाया गया था। नौसैनिक अभ्यास की भारत-अमेरिका मालाबार श्रृंखला में जापान की निरंतर भागीदारी के साथ-साथ दोनों देश नियमित द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास पर भी सहमत हुए। प्रधानमंत्री ने जापानी उद्योगों को 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत निवेश करने का आह्वान किया

उस यात्रा के बाद से, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, विदेश राज्य मंत्री के दौरे के साथ-साथ भारत में विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के दौरे के परिणामस्वरूप रक्षा सहयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सौदे हुए। रक्षा सहयोग के क्षेत्र में प्रमुख घटनाओं में से कुछ का विवरण आगे दिया गया है।

भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग

संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक महाशक्ति है, जो रक्षा पर लगभग एक तिहाई वैश्विक व्यय खर्च करता है। ये दोनों बातें इसके प्रौद्योगिक उत्कर्ष के साथ मिलकर रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए अमेरिका को सबसे महत्वपूर्ण देश बना देती हैं। इस एक साल के दौरान, भारत और अमेरिका ने रक्षा में मजबूत सहयोग के लिए एक नई रूपरेखा वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए। रक्षा रूपरेखा समझौता 'भारत की रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए उचित उपायों' पर केंद्रित है। जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान 10 वर्षीय रक्षा रूपरेखा समझौते का नवीनीकरण किया गया तथा भारत में अमेरिकी रक्षा सचिव ऐश कार्टर के दौरे के दौरान इस समझौते पर औपचारिक तौर पर हस्ताक्षर किए गए। इस यात्रा ने संयुक्त रूप से जैविक और रासायनिक युद्ध के खिलाफ सैनिकों के लिए सुरक्षात्मक तैयारी करने के लिए एक सौदे पर तथा ऊर्जा ऊत्पादन के लिए एक अन्य सहमति पर भी अपनी मुहर लगाई।

दोनों देशों के बीच रक्षा संधियों के विस्तार के लिए आयोजित भारतीय नेताओं के साथ वार्ता को लेकर भी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। हाल के वर्षों में रूस को पीछे छोड़ते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय सेना के लिए अब हथियारों के शीर्ष स्रोतों में से एक बन गया है। अमेरिका ने सैन्य प्रौद्योगिकी के संयुक्त विकास और उत्पादन की पेशकश की है। दोनों परियोजनाएं सैनिकों के लिए सुरक्षात्मक आवरण के साथ साथ युद्धक्षेत्र के लिए उन्नत ऊर्जा स्रोत को विकसित करने पर केंद्रित हैं। दोनों देशों द्वारा समान रूप से 10 लाख डॉलर की वित्तीय साझेदारी की जाएगी।

दो अन्य परियोजनाएं रक्षा प्रौद्योगिकी तथा व्यापार पहल के अंतर्गत हैं, जिन्हें कार्टर ने स्वयं रक्षा मंत्री बनने से पहले ही शुरू की थी और ये दोनों परियोजनाएं सी-130 जे सैन्य परिवहन विमान के लिए रेवेन मिनी यूएवी और निगरानी मॉड्यूल से संबंधित हैं। लगभग तीन दशक पहले ब्रिटेन से हासिल किए गए तथा पुराने होते मालवाहक विमान की जगह नई तकनीक से बनाए जा रहे मालवाहक विमान के लिए भारत अमेरिकी विमान लांच प्रौद्योगिकी पर नजर गड़ाए हुए है। दोनों पक्षों के बीच सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया गया है, जिसकी बैठक संयुक्त राज्य अमेरिका में की जाएगी। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी समेत अमेरिकी कंपनियां, 'मेक इन इंडिया' जैसी पहल में बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी करेगी तथा प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण के साथ भारत में अपनी विनिर्माण इकाइयां स्थापित करेंगी तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ जुड़ेगी।

हाल के वर्षों में रूस को पीछे छोड़ते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय सेना के लिए अब हथियारों के शीर्ष स्रोतों में से एक बन गया है। अमेरिका ने सैन्य प्रौद्योगिकी के संयुक्त विकास और उत्पादन की पेशकश की है। दोनों परियोजनाएं सैनिकों के लिए सुरक्षात्मक आवरण के साथ साथ युद्धक्षेत्र के लिए उन्नत ऊर्जा स्रोत को विकसित करने पर केंद्रित हैं। दोनों देशों द्वारा समान रूप से 10 लाख डॉलर की वित्तीय साझेदारी की जाएगी।

भारत-फ्रांस रक्षा सहयोग और रॉफेल सौदा

रक्षा की दृष्टि से प्रधानमंत्री की सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक उनकी फ्रांस यात्रा थी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति रैंकोइस हॉलंडे के साथ प्रधानमंत्री की व्यापक वार्ता के बाद जयपुर तथा महाराष्ट्र में परमाणु परियोजना समेत रक्षा और सुरक्षा पर प्रभाव के साथ करार पर भारत और फ्रांस ने हस्ताक्षर किए। जैतपुर परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार लाने और स्थानीयकरण में वृद्धि से लागत में कमी लाने के लक्ष्य के साथ लार्सन एण्ड टुब्रो तथा एरेवा के बीच एक सहमति पर हस्ताक्षर हुए। यह समझौता भारत में

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को संभव बनाएगा तथा स्वदेशी परमाणु ऊर्जा उद्योग के विकास को संभम बनाएगा। एनपीसीआईएल तथा एरेवा के बीच प्रीइंजीनियरिंग समझौते हुए, इससे संयंत्र के सभी तकनीकी पहलुओं पर स्पष्टता लाने का इरादा है ताकि सभी पक्ष (अरेवा, ऑल्स्टम तथा एनपीसीआईएल) अपनी कीमतों को अंतिम रूप दे सके तथा अब भी इस परियोजना की लागत में इस स्तर पर शामिल जोखिमों के लिए सभी प्रावधानों का अनुकूलन कर सके। हालांकि समझौते नागरिक परमाणु ऊर्जा से संबन्धित हैं, तथापि स्थानांतरित किए जा रहे प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल रक्षा क्षेत्र में भी होगा तथा प्रधानमंत्री मोदी की 'मेक इन इंडिया' परियोजना को भी मजबूती मिलेगी।

सबसे अहम मसौदे पर उस समय हस्ताक्षर हुए, जब फ्रांस सरकार सौदा करने के लिए उड़ सकने की हालत वाले 36 रॉफेल लड़ाकू विमानों की यथाशीघ्र आपूर्ति करने पर सरकारों के बीच के सौदे पर सहमत हुई। भारतीय वायु सेना ने लंबे समय से 126 बहुद्देश्यीय विमान की अपनी आवश्यकता के लिए रॉफेल का चयन किया था। प्रारंभिक 18 विमानों के आयात के बाद इनमें से विमानों का थोक विनिर्माण एचएएल में होना था।

दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग के लिए व्यापक वार्ता की, भारत-फ्रांस मेघा ट्रॉपिकस उपग्रह से दो साल के आंकड़ों से विस्तार देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और अंतरिक्ष अध्ययन के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रीय केंद्र (सीएनईएस) के बीच हस्ताक्षर किए गए, जो 2011 में भारतीय प्रक्षेपण यान पीएसएलवी से प्रक्षेपित किया गया था। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि एक समझौता के तहत उपग्रह सुदूर संवेदन, उपग्रह संचार और अन्यों के बीच उपग्रह मौसम विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए दो अंतरिक्ष संगठनों के बीच हस्ताक्षर किए गए।

हालांकि, सबसे अहम मसौदे पर उस समय हस्ताक्षर हुए, जब फ्रांस सरकार सौदा करने के लिए उड़ सकने की हालत वाले 36 रॉफेल लड़ाकू विमानों की यथाशीघ्र आपूर्ति करने पर सरकारों के बीच के सौदे पर सहमत हुई। भारतीय वायु सेना ने लंबे समय से 126 बहुद्देश्यीय विमान की अपनी आवश्यकता के लिए रॉफेल का चयन किया था। प्रारंभिक 18 विमानों के आयात के बाद इनमें से विमानों का थोक विनिर्माण एचएएल में होना था। हालांकि, सौदे उलझ गए थे, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी एचएएल के साथ संतुष्ट नहीं थी तथा एचएएल से निकलने वाले विमानों की गारंटी लेने के लिए भी तैयार नहीं थी। इस अड़चन से सौदे के कार्यान्वयन में रुकावट आई थी। इसी बीच भारतीय वायु सेना ने अपनी समस्या को महसूस किया, क्योंकि इसकी लड़ाकू क्षमता लगातार छीज रही थी। इस सौदे के साथ 36 विमानों की उसी खेप में आपूर्ति की जाएगी, जैसा कि भारतीय वायुसेना द्वारा जांच की गई थी और उसका अनुमोदन किया गया था तथा फ्रांस द्वारा एक समय सीमा के अंदर लंबे विमानों के दीर्घकालिक रख-रखाव की जिम्मेदारी के साथ भारतीय वायु सेना की संचालन आवश्यकता के साथ तालमेल बनाया जाना है। इसके बाद सरकार शेष राशि के संबंध में कोई भी निर्णय ले सकती है एवं संभवत: एक पूर्व शर्त के रूप में वैश्विक विक्रेताओं को 'मेक इन इंडिया' के साथ देने की पेशकश की जा सकती है।

भारत-रूस रक्षा सहयोग

सोवियत संघ और उसके विघटन के बाद के पांच दशकों के दौरान, रूस भारत को रक्षा संबंधी साज-ओ-सामान की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश रहा है। परिणामत: रूस के साथ रक्षा सहयोग भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपत्ति और आपात स्थिति में रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा हुआ है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने वार्षिक शिखर बैठक के लिए 11 दिसंबर, 2014 को नई दिल्ली का दौरा किया, जो कि प्रधानमंत्री के कार्यभार संभालने के बाद उनका पहला दौरा था। शिखर बैठक में प्रधानमंत्री ने रूस के साथ बढ़ते सैन्य सहयोग के उदाहरण के रूप में रूस निर्मित विमान वाहक आईएनएस विक्रमादित्य का जिक्र किया तथा रक्षा संबंधों के दीर्घकालिक निरंतरता का संकेत करते हुए उल्लेख किया कि भारत के पास विकल्पों के बढ़ने के बावजूद रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझीदार बना रहेगा।

दोनों पक्ष 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को पूरा करने के लिए भारत में रूसी प्रौद्योगिकी से बने एमआई-17 तथा कामोव के -226 हेलीकॉप्टर के संयुक्त उत्पादन पर सहमत हुए तथा इस बात पर भी सहमत हुए कि संयुक्त विकास तथा हल्के परिवहन विमान के उत्पादन जैसी लंबित परियोजनाओं में तेजी लाई जाए। इसी तरह, सुखोई तथा एचएएल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किए जाने वाले पांचवीं पीढ़ी के संयुक्त लड़ाकू विमान पर भी वार्ता हुई। अंतिम डिजाइन अनुबंध पर जल्द ही हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। रूस आईएनएस चक्र के बाद भारत के लिए एक और परमाणु संचालित अकुला श्रेणी की पनडुब्बी पट्टे पर देने के लिए सहमत हो गया, जो पहले से ही सेवा में है।

रक्षा के क्षेत्र में पाकिस्तान-रूस सहयोग की हालिया रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए रूसी एमआई 35 हमलावर हेलीकाप्टरों की संभावित बिक्री को लेकर विशेष रूप से भारत में कुछ आशंका जताई गई थी। हालांकि, भारत में रूसी राजदूत ने ऐसी आशंका को उस समय कम करने की कोशिश की, जब उन्होंने कहा कि रूस ऐसा कोई काम नहीं करेगा, जिससे भारत की सुरक्षा को किसी तरह से खतरा पैदा हो।

रक्षा के क्षेत्र में पाकिस्तान-रूस सहयोग की हालिया रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए रूसी एमआई 35 हमलावर हेलीकाप्टरों की संभावित बिक्री को लेकर विशेष रूप से भारत में कुछ आशंका जताई गई थी। हालांकि, भारत में रूसी राजदूत ने ऐसी आशंका को उस समय कम करने की कोशिश की, जब उन्होंने कहा कि रूस ऐसा कोई काम नहीं करेगा, जिससे भारत की सुरक्षा को किसी तरह से खतरा पैदा हो। इसके बाद भारत के एक समाचार एजेंसी से एक साक्षात्कार में पुतिन ने स्वयं कहा कि 'रूस-पाकिस्तान समझौते सही मायने में भारत के दीर्घकालीन हित में है'।

भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग

इस एक साल के दौरान, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने भी द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग के लिए एक रूपरेखा स्थापित की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय शांति को आगे बढ़ाने और अन्य

चुनौतियों के बीच आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपने रक्षा सहयोग के कदम आगे बढ़ाए। प्रधानमंत्री तथा उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष टॉनी एबॉट ने वार्ता की और दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते तथा रक्षा के विस्तार एवं उसे मजबूत करने को लेकर रक्षा सहयोग के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने पर सहमत हुए। उन्होंने आपसी हितों के क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सहयोग और परामर्श में तेजी लाने के लिए संरचना स्थापित की। इस सहयोग का प्राथमिक ध्यान समुद्री सुरक्षा पर केंद्रित किया जाएगा, जैसा कि ऑस्ट्रेलियाई संसद के सामने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने इसे दोहराते हुए कहा, हमें समुद्री सुरक्षा बनाए रखने पर अधिक सहयोग करना चाहिए। हमें समुद्र पर एक साथ काम करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमें आपसी सहयोग करना चाहिए तथा हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक मानदंडों के अनुरूप एक सार्वभौमिक सम्मान के लिए काम करना चाहिए।

ऑस्ट्रेलियाई संसद के सामने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने इसे दोहराते हुए कहा, हमें समुद्री सुरक्षा बनाए रखने पर अधिक सहयोग करना चाहिए। हमें समुद्र पर एक साथ काम करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमें आपसी सहयोग करना चाहिए तथा हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक मानदंडों के अनुरूप एक सार्वभौमिक सम्मान के लिए काम करना चाहिए।

यह आह्वान पहले ही समुद्री सुरक्षा सहयोग पर म्यांमार में में आयोजित पूर्वी एशिया और आसियान शिखर में किया गया था। इसके बाद, भारतीय तथा ऑस्ट्रेलियाई दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा एक कार्य-योजना पर सहमति जताई गई। कार्य-योजना के मुताबिक, एक वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा और विदेश नीति के आदान-प्रदान और उसका समन्वय किया जाएगा। इस योजना में बहुपक्षीय बैठकों के अलावा प्रधानमंत्रियों की एक वार्षिक बैठक शामिल है। इसमें रक्षा मंत्रियों की निरंतर बैठक, वार्षिक रक्षा नीति वार्ताएं, नियमित उच्च स्तरीय यात्राओं वाली सेवा-दर-सेवा संलग्नता, वार्षिक कर्मचारी वार्ताएं, संयुक्त प्रशिक्षण तथा नियमित अभ्यास एवं नियमित द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास शामिल है। यह कार्य-योजना यह ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय रक्षा सामग्री प्रतिनिधिमंडलों की यात्राओं तथा संयुक्त उद्योग जुड़ाव को मजबूत करने के माध्यम से रक्षा शोधों की खोज तथा विकास को लेकर सहयोग का आह्वान करती है।

सबसे अहम बात है कि आतंकवाद के खिलाफ तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर एक संयुक्त कार्यकारी समूह, तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों, बम घटनाओं और प्रौद्योगिकियों और अन्य संबंधित पहलुओं का मुकाबला करने पर विशेषज्ञों के बीच आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण और आदान-प्रदान में सहयोग भी इस वार्षिक कार्य-योजना के अहम हिस्से हैं। कार्य-योजना के तहत हो रही प्रगति की समीक्षा स्थापित संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से की जाएगी, जिसमें विदेश मंत्रियों की वार्ता तथा रक्षा मंत्रियों की बैठक शामिल हैं।

अन्य देशों के साथ रक्षा सहयोग

वर्ष के दौरान, भारत और दक्षिण कोरिया ने रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए हाल ही में सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसके दस में से सात बिंदु रक्षा सहयोग पर ही केंद्रित थे। इनमें मुख्यत: दक्षिण कोरियाई तथा भारतीय पोत कारखाने तथा इनकी नौ-सेनाओं के बीच आदान-प्रदान शामिल हैं। पहले दक्षिण कोरियाई पोत कारखाने में भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों का निर्माण शामिल था, बाद में दक्षिण कारियाई सहयोग से भारतीय पोत कारखाने में इसका निर्माण होना है।

इसी तरह, परमाणु ऊर्जा, एयरोस्पेस और रक्षा के क्षेत्र में कनाडा और भारतीय कंपनियों के बीच कई वाणिज्यिक समझौतों की घोषणा की गई। ससकैच्वा आधारित कामेको को संलग्न करने वाले एक वाणिज्यिक समझौते के तहत अगले पांच वर्षों में सात लाख पाउंड के यूरेनियम की आपूर्ति भारत को ये कंपनी करेगी। यह सौदा भारत सरकार द्वारा कनाडा-भारत परमाणु सहयोग समझौता के कारण ही संभव हो पाया।

इसी तरह, गत एक साल के दौरान भारत के साथ पारंपरिक रूप से रक्षा संधियों के साथ निकटस्थ रूप से जुड़े देश मॉरिशस के साथ भी रक्षा सहयोग को बढ़ाया गया। 2 नवंबर 2014 को विदेश मंत्री की इस द्वीपीय देश की पहली यात्रा के दौरान अप्रवासी दिवस मनाया गया। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र की रक्षा और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना और मॉरीशस के तट रक्षक बल के बीच सहयोग उस समय एजेंडे के शीर्ष पर था। समारोह के दौरान, भारतीय नौसेना और मॉरीशस के तट रक्षक के बीच सहयोग के लिए अधिक से अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए मॉरीशस के पानी में तीन प्रमुख भारतीय युद्धपोत उतारे गए।

जिन अन्य देशों के साथ भारत का निकटस्थ रक्षा सहयोग रहा है, उनमें इजरायल भी है। भारत और इजरायल दोनों देशों ने आतंकवाद से लड़ने के क्षेत्र में सहयोग किया है तथा इजरायल भी मिसाइल और मानवरहित हवाई वाहनों सहित भारत के लिए परिष्कृत रक्षा हार्डवेयर की आपूर्ति के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। वर्ष के दौरान आपसी सहयोग का विस्तार किया गया और प्रधानमंत्री अगले एक साल के भीतर इजरायल की यात्रा करेंगे, यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली इजरायल यात्रा होगी।

सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र की रक्षा और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना और मॉरीशस के तट रक्षक बल के बीच सहयोग उस समय एजेंडे के शीर्ष पर था। समारोह के दौरान, भारतीय नौसेना और मॉरीशस के तट रक्षक के बीच सहयोग के लिए अधिक से अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए मॉरीशस के पानी में तीन प्रमुख भारतीय युद्धपोत उतारे गए।

निष्कर्ष

दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भारत के रक्षा सहयोग में काफी विस्तार हुआ है। यह उज्जवल भविष्य से जुड़ा हुआ है, जो भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की परिकल्पना है, साथ ही भारत के रक्षा बलों में बढ़ रही आस्था से भी जुड़ा है। ज्यादा से ज्यादा देश अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत के साथ होना चाहते हैं। आने वाले दिनों में इस सहयोग में और बढ़ोतरी होगी तथा यह 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को एक सुदृढ़ आधार प्रदान करेगा, जिसमें भारत को रूपांतरित करने की असीम संभावना है। ❑

क्या आप जानते हैं?

ट्रिप्स

ट्रिप्स यानी *ट्रेड रिलेटेड असपेक्टस ऑफ इनटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स* बौद्धिक संपदा के अधिकारों के न्यूनतम मानकों को तय करता है और सदस्य देशों को उसके अनुपालन के लिए बाध्य करता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो बौद्धिक संपदा के अधिकार से जुड़े मसलों को हल करने के लिए अमल में लाया जाता है। इस कानून के तहत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नकल और बौद्धिक संपदा की किसी भी प्रकार की चोरी के मामले में कार्रवाई की जाती है। यह कानून बौद्धिक संपदा के उपयोग, उपलब्धता और पेटेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह कानून उन सभी देशों में लागू है, जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। इन सभी देशों के लिए ट्रिप्स के प्रावधानों को मानना अनिवार्य है। इस समझौते के तहत बौद्धिक संपदा के मानकीकरण, अनुपालन और विवादों के निपटारे किए जाते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार तंत्र को ट्रिप्स समझौते के माध्यम से लागू किया गया था और दुनिया के तमाम देशों में यह तीव्र बहस का मसला है। ट्रिप्स समझौता तमाम विकासशील देशों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है क्योंकि इन देशों को इसे लागू करने के लिए अपने विधेयक में बड़े परिवर्तन करने पड़े हैं। इनमें सबसे गहन बहसें पेटेंट को लेकर हुई हैं जिसके तहत अविष्कारकों को समयबद्ध अधिकार उपलब्ध कराए जाते हैं और निजी क्षेत्र के उद्यमों के विकास के लिए अनिवार्य रियायतें दी जाती हैं। कई देशों में पारंपरिक तौर पर पेटेंट की संभावना पर कठोर सीमाएं लागू हैं। ट्रिप्स के तहत यह बाध्यता है कि प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में पेटेंट मुहैया हो। इसका अर्थ यह हुआ कि स्वास्थ्य को भी पेटेंट तंत्र के बाहर नहीं रखा जा सकता। इतना ही नहीं, ट्रिप्स के तहत पौधा किस्मों के संरक्षण को भी थोपा गया है और इस तरह समूचा खाद्य क्षेत्र भी उसके दायरे में आ जाता है। जैव रूपों पर भी कुछ अपवादों के साथ ट्रिप्स लागू है। इस तरह ट्रिप्स जैव प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास से बुनियादी तौर पर जुड़ा हुआ है। आईईएलआरसी का बौद्धिक संपदा अधिकार कार्यक्रम बौद्धिक संपदा अधिकारों और पेटेंट पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के इर्द-गिर्द केंद्रित है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में बौद्धिक संपदा के मानकों को मजबूत किए जाने से पड़ने वाले प्रभावों को आम तौर पर संज्ञान में लिया जाता है। इसके तहत इन अधिकारों का कृषि क्षेत्र में पेटेंट व उत्पादक के अधिकारों के संदर्भ में लागू किया जाना और उसके प्रभाव पर ज्यादा जोर है। यह पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण से जुड़े मसलों की भी पड़ताल करता है, खासकर उन तरीकों पर जिनके माध्यम से इस ज्ञान को बचाया जा सके।

मरकोसर

मरकोसर अथवा मरकोसल लैटिन अमेरिका का एक वाणिज्यिक ब्लॉक है। इसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पराग्वे और वेनेजुएला भी शामिल हैं। इन देशों को मताधिकार का पूर्ण अधिकार नहीं है और मरकोसर के सदस्य देशों के बाज़ार में इनको पर्याप्त छूट भी हासिल नहीं है, लेकिन इन्हें टैक्स में छूट हासिल है। इस ब्लॉक का गठन 1991 में सदस्य देशों के बीच सामान, सेवाओं, पूंजी और नागरिकों के मुक्त आवागमन की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।

मरकोसर में पांच एसोसिएट देश चिली, कोलंबिया, पेरु, बोलिविया और इक्वाडोर शामिल हैं। पराग्वे में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर भारत और मरकोसर ने हस्ताक्षर किए थे। इस फ्रेमवर्क के पहले चरण में टैरिफ में एक-दूसरे को छूट के जरिए बातचीत के लिए परिस्थितियां तैयार करने और तंत्र विकसित करने की बात की गई थी। जबकि दूसरे चरण में दोनों पक्षों के बीच विश्व व्यापार संगठन के नियमों के मुताबिक मुक्त व्यापार को लेकर बातचीत किए जाने पर सहमति बनी थी। इसी के तहत नई दिल्ली में 2004 में प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का उद्देश्य भारत और सदस्य देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करना और बढ़ाना था। जिसके तहत मरकोसर के सदस्य देशों के बीच टैरिफ में छूट देने और मुक्त व्यापार क्षेत्रों का विकास करना शामिल था।

इस समझौते का लक्ष्य एक ऐसे मैकेनिज्म और स्थितियों की तैयारी जो प्रथम चरण में व्युत्क्रमटैरिफ प्राथमिकता के आधार पर बातचीत शुरू करे और दूसरे चरण में डब्ल्यूटीओ नियमों के मुताबिक द्विपक्षीय फ्री ट्रेड एरिया बनाने की दिशा में प्रयास करे। भारत और मरकोसर के बीच 2005 में छह राउंड की बैठक के बाद प्रीफ्रेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया। संयुक्त राष्ट्र के लैटिन अमेरिका एवं कैरीबिया संबंधी आर्थिक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2013 में लैटिन अमेरिका का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निवल रूप में 179 बिलियन डॉलर था, जो विश्व 2 के किसी भी क्षेत्र के लिए उच्चतम रिकॉर्ड है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1990 में कुछ सौ मिलियन डॉलर था, जो 2013 में 42 बिलियन अमरीकी डॉलर का हो गया है। लैटिन अमेरिका, जिसे प्राय: भारतीय राजनय के अंतिम मोर्चे के रूप में वर्णित किया जाता है, भारत के साथ बेहतर व्यवसाय के लिए खुला है और भारत को, ठीक से भुनाना चाहिए। ❑

प्रस्तुति: वाटिका चंद्रा, उपसंपादक (योजना, अंग्रेजी) ईमेल: vchandra.iis2014@gmail.com

ALS Alternative Learning Systems

ISGS Indian School of General Studies

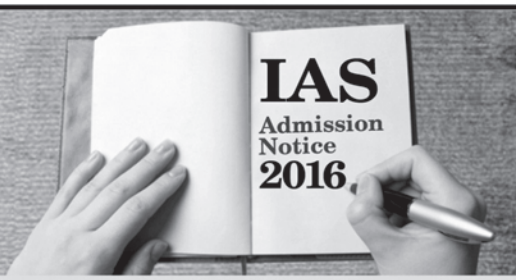

ALS
Training Steel Pillars For The Nation
"Celebrating 22 years of Excellence"

सामान्य अध्ययन हेतु हिन्दी माध्यम का सर्वश्रेष्ठ संस्थान

The Most Comprehensive Course for General Studies

सामान्य अध्ययन EXTENSIVE GS
AN IAS EXECUTIVE PROGRAMME

MAIN Paper I, II, III, IV + Essay + Prelim + CSAT + Interview

One of the finest teams of GS *Stalwarts Combine to form* THE BEST EVER TEAM

आधुनिक भारत, विश्व इतिहास, कला एवं संस्कृति **Hemant Jha**	भारतीय अर्थव्यवस्था **Arunesh Singh & R.C. Sinha**	संविधान व शासन व्यवस्था **R.C. Sinha, Manoj Kumar Singh & Manish Gautam**	**CSAT** Civil Services Aptitude Test **Arbind Singh, K.M. Pathi & Sachin Arora**
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **Sharad Tripathi & Dr. Sanjay Pandey**	भूगोल एवं पर्यावरण **Sachin Arora & Dr. Shashi Shekhar**	आंतरिक सुरक्षा **Manish Gautam**	
नीतिशास्त्र (ETHICS) **Hemant Jha & K.M. Pathi**	अंतर्राष्ट्रीय एवं द्विपक्षीय संबंध, समसामयिक मुद्दे **Sharad Tripathi**	राष्ट्रीय एवं सामाजिक मुद्दे **Y.D. Misra & Sharad Tripathi**	

Programme Director
MANOJ KUMAR SINGH
Managing Director: ALS, ISGS, Competition Wizard

बैच प्रारंभ JULY 2 एवं AUG 10

IMPORTANT

For Registration: Please deposit Rs. 25,000 as a Registration fee through DD/cash in favour of Alternative Learning Systems Pvt. Ltd. Balance Fee should be paid on or before starting of the batch. You can also deposit full fee through DD/Cash.

For Admission Fee: Please contact our counsellors.

सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन (325 सत्र) GS मुख्य परीक्षा Paper I, II, III, IV + GS प्रारंभिक परीक्षा + CSAT (75 सत्र) + निबंध (15 कक्षाएँ) + साक्षात्कार + अंग्रेजी फाउंडेशन + लेखन कला संवर्धन + मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज (10 टेस्ट) + प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज (30 टेस्ट) + 20-Day समसामयिकी क्रैश कोर्स (प्रारंभिक) + 20-Day समसामयिकी क्रैश कोर्स (मुख्य)

सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट

ALS संस्थान से अब तक 1808 सफल अभ्यर्थियों का चयन, वर्ष 2014 में कुल चयन = 215, अब तक 2 IAS TOPPERS का चयन।

AIR 9 AIR 15 AIR 23 AIR 28 AIR 40 AIR 46 AIR 52 AIR 54

इतिहास
By **Hemant Jha**
Batch Begins: **July 14**

लोक प्रशासन
By **R.C. Sinha**
"A Professional of National Repute"
के निर्देशन में
Batch Begins: **July 05**

9999343999
9311331331
9891990011

ALS Alternative Learning Systems

Alternative Learning Systems (P) Ltd.
Corporate Office: ALS, B-19, ALS House, Commercial Complex, Dr Mukherjee Nagar, Delhi-110009.
Visit us at www.iasals.com

Be in touch...
Manoj Kumar Singh
Managing Director: ALS, ISGS & Competition Wizard
mksalsadm@gmail.com

YH-78/2015

बहुपक्षीयता और क्षेत्रीय सहयोगः कुछ प्रश्न

दिलीप सिन्हा

भूमंडलीकरण के बाद की दुनिया एक छोटी सी जगह प्रतीक होती है, जहां आप एक दूसरे के विकास के लिए मना नहीं कर सकते। इस वक्त कई देश मिलकर संयुक्त राष्ट्र, जी-20, जी-7, ब्रिक्स और जलवायु परिवर्तन पर अंतर्सरकारी पैनल जैसे मंचों पर साथ बैठकर चर्चा करते हैं, ताकि आंतकवाद, अर्थव्यवसथा, जलवायु और महत्वपूर्ण विषयों से जुड़ी समस्या हल की जा सके। भारत ने भी बहुपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग में पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता और भारत-बांग्लादेश-भूटान-नेपाल मोटर वाहन समझौता किया। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भारत ब्रिक्स में काफी सक्रिय रहा है, जो अब उनके सहयोग से ब्रिक्स विकास बैंक का प्रस्ताव पास करवाया और अब बैंक का पहला अध्यक्ष भारतीय होगा

पूरब और पश्चिम के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ने और लगातार वैश्विक वित्तीय संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर दबाव बढ़ रहा है और बहुपक्षीय संगठनों को घुटन महसूस हो रही है। वैश्वीकरण और लोकतंत्र को लेकर 1990 के दशक में जो उत्साह पैदा हुआ था वह अब क्षीण हो चुका है। बेरोजगारी, असमानता बढ़ने और धार्मिक टकराव के कारण वैश्वीकरण के सबसे उत्साही समर्थकों का जोश भी ठंडा पड़ गया है। महत्वाकांक्षी योजनाओं के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अफगानिस्तान, इराक, लीबिया और दक्षिण सूडान जैसे देशों में स्थायित्व लाने में असमर्थ रहा है, जिससे हस्तक्षेप करने वाली नीतियों की साख कमजोर हुई है। विकासशील देशों को ऐसे माहौल में पश्चिमी देशों की मंशा पर पूरी तरह संदेह भले ही न हो लेकिन वे ज्यादा सतर्क हैं। इनके सहित कई दूसरे देशों में अव्यवस्था के कारण मानवीय आपदा पैदा हुई है और शरणार्थियों की बाढ़ आ गई है।

शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के सिर उठाना, कई क्षेत्रों पर उनके कब्जे और दुनिया भर के देशों से आतंकवादी गुटों में भर्ती करना और उनका पूंजी जुटाना दुनिया के सामने एक नए तरह का संकट है। मौजूदा बहुपक्षीय संगठनों का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था के हिस्से के तौर पर किया गया था। इन संगठनों ने न सिर्फ शीत युद्ध बल्कि अपने सैन्य गठबंधन के विरोधियों से भी खुद को सुरक्षित रखा लेकिन क्या पूरब और पश्चिम के बंटवारे ने आज इन्हें निरुत्साह कर दिया है? और क्या मौजूदा बहुपक्षीय ढांचा ही इसकी एक और चुनौती है?

पूर्व-पश्चिम तनाव की वापसी

पूर्व-पश्चिम के तनाव ने एक अनहोनी का भय पैदा कर दिया है। ऐसा लग रहा मानो शीत युद्ध का खात्मा नहीं हुआ हो, सिर्फ कुछ समय का ठहराव आया है। 7- 8 जून को जर्मनी के स्कॉल्सब इमाउ में जी 7 का सम्मेलन हुआ। पश्चिम के सात प्रमुख देशों के नेताओं ने यूक्रेन के मुद्दे पर रूस को एक सख्त संदेश दिया कि वे क्रीमिया पर रूस का कब्जा मानने को तैयार नहीं हैं और वे रूस पर प्रतिबंधात्मसक कदम उठा सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन क्रीमिया वापस करने की मनोदशा में नहीं हैं। क्रीमिया में रहने वाले ज्यादातर लोग रूसी मूल के हैं। मार्च 2014 में इन लोगों ने यूक्रेन से टूटकर रूसी संघ के साथ रहने का जबरदस्त ढंग से समर्थन किया। पुतिन के पास भी ऐसी कोई वजह नहीं थी जिसके कारण वह पूर्वी यूक्रेन में रहने वाले रूसी मूल के लोगों की मदद ना करें। रूस पश्चिम देशों के सैन्य गठबंधन नाटो के विस्तार से खुश नहीं है। वारसा संधि में शामिल करीब 10 देश अब नाटो के सदस्य हैं। रूस भयभीत है और राजनीतिक एवं वाणिज्यिक लाभ के लिए चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है।

रूस पर लगाए गए प्रतिबंध यूरोपीय संघ के लिए महंगे साबित हुए हैं। यूरोपीय संघ का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रूस है और वह एक तिहाई प्राथमिक ऊर्जा का आयात यहीं से करता है। अस्थिर मध्य

लेखक संयुक्त राष्ट्र, जेनेवा तथा ग्रीस में भारत के राजदूत रहे हैं। वह विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मामलों से संबंधित विभाग के प्रमुख भी रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने जर्मनी, मिस्र, पाकिस्तान व बांग्लादेश में भी अपनी सेवाएं दी हैं। ईमेलः dilipsinha@hotmail.com

पूर्व पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए यूरोप ने लगातार रूस से तेल एवं गैस का आयात बढ़ाया था। रूस की बढ़ती समृद्धि के कारण यूरोप को वहां अपने महंगे उत्पादों का आकर्षक बाज़ार भी मिला। दोनों के बीच 2012 में व्यापार अपने चरम पर था। हालांकि यूरोपीय संघ ऊर्जा ज़रूरतों के लिए रूस पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है लेकिन प्रतिस्पर्धी विकल्पों की कमी के कारण प्रगति काफी धीमी है।

शीत युद्ध के शुरुआती दिनों में चीन भी पश्चिम का निशाना बना था। समूह सात के नेताओं ने हालांकि किसी का नाम नहीं लिया लेकिन उनकी घोषणाओं में यह संदर्भ साफ है, 'हम पूर्व और दक्षिणी चीन सागर के तनाव से चिंतित हैं। हम विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे की बात करते हैं। साथ ही महासागरों के न्यायसंगत और बेराक-टोक इस्तेमाल की अहमियत पर

शीत युद्ध के बाद सुरक्षा परिषद ने जो सक्रियता दिखाई थी वह अब खत्म होने लगी है। अब यह फिर से मानवीय अपीलों वाले मौखिक प्रस्तावों को पारित करने तक सीमित रह गया है, जबकि संघर्ष लगातार बढ़ते जा रहे है। इसका आखिरी शांति अभियान 2011 में दक्षिणी सूडान में था जबकि लीबिया में किया गया इसका आखिरी सैन्य अभियान सवालों के घेरे में है।

जोर देते हैं। बड़े पैमाने पर जमीन पर दावे से यथास्थिति को ख़तरा उत्पन्न हो गया है, जिसके हम ख़िलाफ हैं। हम भय, जबरदस्ती, बल के द्वारा किए जाने वाले ऐसे किसी भी एकपक्षीय कार्रवाई का पुरजोर विरोध करते हैं।'

तो क्या शीत युद्ध लौट आया है? विशेषज्ञों की ऐसी राय नहीं है और इसकी अच्छी वजह भी है। दुनिया आज उस तरह के तनाव और अस्थिरता के निकट नहीं है जैसा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। उस वक्त पूरी दुनिया तीन हिस्सों में बंट गई थी। आज हम पहले से कहीं ज्यादा संगठित हैं। व्यावसायिक हितों की वजह से आज बयानबाजी पर लगाम है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में देश आज भी अपनी समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि संगठनों में पहले जैसी ताकत नहीं रही और

संयुक्त राष्ट्र में भारत

- सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने पहले भाषण में प्रधानमंत्री ने सुरक्षा परिषद में सुधारों तथा आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे साझा चुनौतियों के समाधान के लिए अधिक सहयोग पर जोर दिया।
- प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में त्वरित सुधार तथा सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए मजबूती से बात रखी।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रधानमंत्री के प्रखर भाषण के मात्र 75 दिन बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी।

ये महाशक्तियों के शिथिल रवैये से तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें फैसले लेने में मुश्किल हो रही है और अलग-अलग देश अपने बीच समन्वय के लिए क्षेत्रीय समूहों में लौट रहे हैं।

जी-20

एक प्रयोग के तौर पर वैश्विक वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के लिए एक दर्जन से ज्यादा उभरती अर्थव्यवस्थाओं को आमंत्रित किया गया, जिससे 1999 में जी 20 का गठन हुआ। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से निपटने में इस समूह ने खुद को कारगर साबित किया था। समय-समय पर जी 20 देशों की बैठक होती है लेकिन वैश्विक कार्रवाई का मुख्य मंच नहीं है। पिछले साल नवंबर में जी 20 ब्रिस्बेन सम्मेलन द्वारा किए आहवान की अनदेखी कर दी गई।

इस बैठक की एक अहम अपील यह थी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कामकाज में सुधार और 2010 में पारित उसके 15वें कोटा समीक्षा जल्द लागू की जाए। इस सम्मेलन में जारी आधिकारिक पत्र के मुताबिक, 'अगर यह साल के अंत तक नहीं होता है तो हम आईएमएफ को अगले चरण के विकल्पों के साथ तैयार रहने को कहेंगे।' इसे मंजूरी देने वाले सभी प्रमुख देशों के जी 20 के सदस्य होने के बावजूद इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

शीत युद्ध के बाद सुरक्षा परिषद ने जो सक्रियता दिखाई थी वह अब खत्म होने लगी है। अब यह फिर से मानवीय अपीलों वाले मौखिक प्रस्तावों को पारित करने तक सीमित रह गया है, जबकि संघर्ष लगातार बढ़ते जा रहे है। इसका आखिरी शांति अभियान 2011 में दक्षिणी सूडान में था जबकि लीबिया में किया गया इसका आखिरी सैन्य अभियान सवालों के घेरे में है। पश्चिम की अगुवाई में लीबिया पर की गई बमबारी ने सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी देशों के बीच दो दशकों से चले आ रहे सहयोग को खत्म कर दिया। रूस और चीन ने ऐसे किसी प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया है। दोनों देशों ने पिछले साल मार्च में सीरिया के ख़िलाफ निंदा प्रस्ताव पर वीटो किया और इस पर सैन्य कार्रवाई की मंजूरी को रोक दिया।

इमाउ में जी7 की घोषणा ने दुनिया को पश्चिम का एजेंडा थमा दिया। जबकि बहुपक्षीय बातचीत से दुनिया पर एजेंडा थोपने की जी 7 की क्षमता पर संदेह है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यापार वार्ता की काफी अहमियत है। विश्व व्यापार संगठन के 15 साल पुराने दोहा दौर की व्यापार वार्ता का असर भी अब घटने लगा है क्योंकि पश्चिमी देशों ने व्यापार सुविधा समझौते को इससे निकाल दिया।

सुरक्षा परिषद में सुधार की बात भी अब ठंडे बस्ते में चली गई। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बुतरस घाली ने 1992 में अपनी रिपोर्ट 'एन एजेंडा फॉर पीस' सुरक्षा परिषद को सौंपी थी, जिसके बाद इसमें सुधार की बात उठी और 2005 में यह मुख्य मुद्दा बन गया था। सुरक्षा परिषद के ज्यादातर सदस्य सुधार की ज़रूरत पर सहमत थे। कुछ स्थायी सदस्य भी इसके समर्थन में थे लेकिन इसका प्रारूप कैसा हो, इस पर आम सहमति नहीं बन पाई। इस तरह से सुरक्षा परिषद में दरार आई, एक प्राधिकार के तौर पर मिला वैश्विक सम्मान धूमिल हुआ और अब इसकी वैसी अपील नहीं रही।

जी-7

पश्चिमी देश एक बार फिर अपने सलाहकारी संगठन जी 7 में लौट आए हैं।

इसका गठन इन्हीं देशों ने आपसी सलाह के लिए 1975 में किया था। रूस के साथ जी 8 बनाने का प्रयोग रद्द कर दिया गया। इसका असर घोषणाओं के विषय और लहजे पर हुआ। पिछले साल से इस समूह में रूस की गैर मौजूदगी के बाद इसका रुख एकपक्षीय दिख रहा है। पिछले साल रूस को इस समूह ने निकाल दिया गया था और सम्मेलन स्थल सोची से सेशेल्स कर दिया गया था। न सिर्फ रूस और चीन को जी 7 की घोषणाओं में निशाना बनाया बल्कि विकासशील देशों की मांगों पर उनका रुख और सख्ती दिखा।

इमाउ में जी 7 की घोषणा ने दुनिया को पश्चिम का एजेंडा थमा दिया जबकि बहुपक्षीय बातचीत से दुनिया पर एजेंडा थोपने की जी 7 की क्षमता पर संदेह है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यापार वार्ता की काफी अहमियत है। विश्व व्यापार संगठन के 15 साल पुराने दोहा दौर की व्यापार वार्ता का असर भी अब घटने लगा है क्योंकि पश्चिमी देशों ने व्यापार सुविधा समझौते को इससे निकाल दिया। इस समझौते के शुरुआती अनुमोदन के लिए जी 7 को बुलाया गया ताकि दिसंबर में नैरोबी में हो रहे डब्ल्यूटीओ के मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में इसे लागू किया जा सके।

उम्मीद है कि पेरिस में नए समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रत्येक देश की 'राष्ट्रीय स्तर पर योगदान की मंशा' तय की जाएगी। इसका घोषित लक्ष्य वैश्विक औसत तापमान को 2050 तक 2 डिग्री सेल्सियस कम करने का है लेकिन इस पर अभी अस्पष्टता बनी हुई है।

बाकी मुद्दों के लिए ऐसी जल्दबाजी नहीं दिखाई गई जबकि उन्हें डिवेलपमेंट राउंड की बातचीत में शामिल किया गया था। इमाउ समझौते में इस बात पर जोर था कि जो भी देश चाहें, आपस में बहुपक्षीय समझौते कर सकते हैं। इसके बावजूद नियमित तौर पर मांगों को खारिज करने से वैश्विक व्यापार प्रणाली खोखली हो गई। इसमें कहा गया है, 'बहुपक्षीय व्यापार तंत्र को मजबूत बनाना प्राथमिकता है लेकिन हम नये उच्चस्तरीय द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते की कोशिशों का भी स्वागत करते हैं। सेवाओं के व्यापार, सूचना समझौते का विस्तार और पर्यावरणीय वस्तु समझौते सहित बहुपक्षीय बातचीत की प्रगति की तरफ देख रहे हैं।' अंतर-प्रशांत क्षेत्र भागीदारी और अंतर-अटलांटिक क्षेत्र व्यापार और निवेश की भागीदारी का भी स्वागत किया गया है, जिसमें कुछ पश्चिमी देशों की दिलचस्पी है। इस घोषणा में यह भरोसा दिया गया है कि ये समझौते पारदर्शी, उच्च स्तरीय और व्यापक होंगे और डब्यूटीओ के ढांचे को मजबूती देने वाला बने रहेंगे।

जी-20 में भारत

- प्रधानमंत्री ने आस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में नवंबर 2014 में आयोजित दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के समूह जी-20 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया।
- जी-20 समूह ने कालेधन और करदाताओं से संबंधित विशिष्ट नियमों पर पारदर्शिता के संबंध में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री के सुझाव का समर्थन किया।
- जी-20 समूह के संयुक्त वक्तव्य में रोजगार सृजन और वृद्धि आधारित अजेंडा पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- इसी वक्तव्य में व्यापार सुविधा समझौतों पर भारत और अमेरिका के बीच संपूर्ण सहमति तथा इसे त्वरित रूप से लागू किए जाने के कदम का स्वागत किया गया।
- समूह ने वैश्विक अक्षय ऊर्जा केंद्र की स्थापना के प्रधानमंत्री के सुझाव का समर्थन किया।

जलवायु परिवर्तन राजनय

इस साल पेरिस में होने वाले जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 21वीं पार्टी कॉन्फ्रेंस के साथ ही जलवायु परिवर्तन की बातचीत एक नए चरण में पहुंचेगी। उम्मीद है कि पेरिस में नए समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रत्येक देश की 'राष्ट्रीय स्तर पर योगदान की मंशा तय की जाएगी।' इसका घोषित लक्ष्य वैश्विक औसत तापमान को 2050 तक 2 डिग्री सेल्सियस कम करने का है लेकिन इस पर अभी अस्पष्टता बनी हुई है कि वैश्विक उत्सर्जन में जरूरी कमी के लिए स्वैच्छिक 'योगदान' कैसे करेंगे। आईपीसीसी ने यह अनुमान रखा है कि 2 डिग्री तापमान घटाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2010 के मुकाबले 2050 में 40 से 70 फीसदी कटौती की आवश्यकता होगी।

अब यह साफ है कि यूएनएफसीसी में शामिल 'आम लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारी' के सिद्धांत 1992 को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके बावजूद ऊपर से नीचे उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य का विचार 1997 के क्योटो प्रॉटोकॉल के तौर पर रहेगा। विकसित देश जिनकी संचित कार्बन उत्सर्जन ग्लोबल वॉर्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं वे नए नियमों के लिए तैयार नहीं हैं। नए नियमों का मामला निश्चित तौर पर कार्बन उत्सर्जन के लिए सीमित वायुमंडलीय क्षेत्र से जुड़ा होगा। वे पर्यावरण अनुकूल तकनीकों के हस्तांतरण में किसी तरह की रियायत की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उन्हें यह व्यावसायिक रूप से खरीदना होगा। अभी यह देखना है कि कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन में पश्चिमी देशों ने नए समझौते के लिए जो राशि देने का वादा किया था क्या वे देंगे। यह साफ है कि विकासशील देशों को सख्त उत्सर्जन नियम के अतिरिक्त बोझ के साथ विकास का लक्ष्य हासिल करना होगा।

अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए देश क्षेत्रीय समूहों पर जोर दे रहे हैं। इन परिस्थितियों में भारत ने सही ढंग से अपने पड़ोसी देशों पर फोकस किया है। दूरियां मिटाकर भारत पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। भारत की विदेश नीति मुश्किल समय में पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने से तालमेल खाती है।

इस तरह एक वैश्विक पर्यावरण विकास के सहयोग को बढ़ावा देने लायक है। भारत जैसे देश जो विदेशी निवेश की मांग कर रहे हैं और अपनी आर्थिक वृद्धि के लिए निर्यात बाज़ार बढ़ा रहे हैं उन्हें काफी मुश्किलें आएंगी। कमजोर विकास और कम प्रतिस्पर्धा में फंसे विकसित देश विकासशील देशों की कोई मदद नहीं कर रहे हैं। ये देश न सिर्फ सहयोग देने से हिचक रहे हैं बल्कि कृषि उत्पादों के लिए

अपने बाज़ारों को खोलना नहीं चाहते। अपनी कंपनियों को विदेशी कंपनियों से बचाने के लिए वे कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और उसे मजबूत करने के लिए पर्यावरणीय और श्रम मानकों का मुद्दा उठा रहे हैं।

भारत का पड़ोस राजनय

बहुपक्षीय संगठनों में सुधार के लिहाज से यह सही समय नहीं है। अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए देश क्षेत्रीय समूहों पर जोर दे रहे हैं। इन परिस्थितियों में भारत ने सही ढंग से अपने पड़ोसी देशों पर फोकस किया है। दूरियां मिटाकर भारत पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। भारत की विदेश नीति मुश्किल समय में पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने से तालमेल खाती है। लंबे समय से चले आ रहे बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद सुलझाने के द्विपक्षीय प्रयासों के अलावा भारत, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के बीच मोटर वाहन समझौता हुआ है।

अपने नजदीकी पड़ोसी देशों के अलावा भारत इस साल भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन में 52 अफ्रीकी देशों की मेजबानी करने वाला है। 1983 के गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन के बाद यह भारत में होने वाली विदेशी नेताओं की दूसरी सबसे बड़ी सभा होगी। हालांकि यह भी सही है कि इन देशों को वित्तीय मदद देने के मामले में भारत का चीन से कोई मुकाबला नहीं है। मानव संसाधन विकास और सूचना प्रौद्योगिकी में भारत मजबूत है और वह इसका पूरा फायदा उठाएगा।

ब्रिक्स

अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भारत ब्रिक्स में काफी सक्रिय है। भारत ने ब्रिक्स विकास बैंक बनाने का प्रस्ताव रखा था जिसे संगठन से स्वीकार कर लिया। इस बैंक का कामकाज अगले साल से शुरू होने की उम्मीद है। यह पहले से तय था कि इस बैंक का पहला अध्यक्ष भारतीय होगा। इस बैंक का कामकाज 50 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ शुरू होगा और यह विकास से जुड़ी परियोजनाओं की आर्थिक मदद करेगा। इसमें एक मुद्रा रिजर्व भी बनाया जाएगा ताकि भुगतान संतुलन की जरूरत पड़ने पर सदस्य देशों की मदद की जा सके।

ब्रिक्स बैंक बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पश्चिमी देशों ने मौजूदा वैश्विक वित्तीय संस्थानों में अर्थव्यवस्था के आकार के आधार पर अधिकार देने से मना कर दिया। इन संस्थाओं द्वारा मनमाने ढंग से लगाए पर्यावरण और मानवाधिकार शर्तों से विकासशील देश भयभीत थे। ब्रिक्स बैंक के तौर पर अब इन्हें अलग विकल्प मिल गया है।

क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने वाला भारत अकेला देश नहीं है। चीन अपनी नई अर्थव्यवस्था का इस्तेमाल करते हुए अपना विकास बैंक 'एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक' बना रहा है। इस बैंक का पूंजी आधार 100 अरब अमेरिकी डॉलर है। भारत सहित 57 देश इसके सदस्य बने गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ओशनिया और एशिया के कुछ चुनिंदा देशों के बीच नजदीकी आर्थिक रिश्ते बनाने के लिए एक अंतर-प्रशांत क्षेत्र भागीदारी की कोशिश कर रहा।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहल

बहुपक्षीय मंचों को खासतौर पर संयुक्त राष्ट्र समर्थन देने में लंबे समय से भारत की जो उत्साहपूर्ण परंपरा रही है उसमें भारत ने दुनिया के तमाम लोगों को एक ऐसे कार्यक्रम से जोड़ने का गैरपरंपरागत तरीका अपनाया है जो एक तरफ तो नितांत व्यक्तिगत है और दूसरी तरफ इसके व्यापक सामाजिक आयाम भी हैं।

ब्रिक्स में भारत

- जुलाई 2014 में ब्राजील के फोर्टलेज में प्रधानमंत्री जी ने ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया
- ये उनकी एशियाई महाद्वीप के बाहर उनकी पहली यात्रा थी।
- ब्रिक्स देशों द्वारा एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई है।
- जिसका पहला अध्यक्ष एक भारतीय होगा।
- 100 अरब डॉलर के आधार कोष के साथ ब्रिक्स कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर।
- ब्रिक्स देशों के निर्यात साख गारंटी एजेंसियों के बीच तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
- ब्रिक्स देशों के बैंकों के बीच नवोन्मेष पर समझौतों द्वारा सहयोग।

विश्व स्तर पर मौजूद बड़े राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरण सबंधी समस्याओं का समाधान करना कभी भी आसान नहीं होगा। ये मसले जितने बहुपक्षीय संगठनों की जिम्मेदारी हैं उतना ही जवाबदेही हर देश की भी है। इनमें से हर एक क्या कर सकता है इस बारे में जागरूकता पैदा करना एक अच्छी शुरुआत करने की दिशा में अहम कदम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना एक छोटा-सा कदम है। यह एक राष्टीय आदर्श को प्रोत्साहित करने की खातिर अंतर्राष्ट्रीय सर्वसम्मति बनाने के लिए बहुपक्षीय मंचों के इस्तेमाल का एक अच्छा उदाहरण है। इसमें बेहतरीन सफलता भी मिली है। दुनिया के 177 देशों ने भारत के इस प्रस्ताव के सह-प्रायोजक बनने में दिलचस्पी दिखाई है और इसे संयुक्त राष्ट्रों आम सभा में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है।

यह एक ऐसे देश द्वारा अपनाई गई नरम कूटनीति का उदाहरण है जिसने पिछले कई दशकों के दौरान संयुक्त राष्ट्र को अपना चाल और चरित्र बदलने की प्रक्रिया में मदद की है। इस दौरान द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की यथास्थिति बनाए रखने भर की जिम्मेदारी निभा रहे संयुक्त राष्ट्र को बदलाव का एक दूत बनने, गैर उपनिवेशवाद को प्रोत्साहित करने, रंग भेद से लड़ने और विकास का झंडा बुलंद करने वाली संस्थान बनने में भारत ने अहम भूमिका निभाई है। प्राकृतिक संसाधनों के शोषण से अस्तित्व का जोखिम झेल रही दुनिया में प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर जीने का प्राचीन भारतीय दर्शन युवाओं और दूरदर्शी चिंतकों के साथ तुरंत तारतम्यता स्थापित कर लेता है।

वैसे तो अभी यह कह पाना जल्दबाजी होगी कि उपर चर्चा किए गए ये क्षेत्रीय पहल कितने सफल होंगे। फिर भी यह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि वे द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पैदा हुई बहुपक्षीय संस्थाओं के उददेश्यों से मेल खाते हैं।

अब यह जिम्मेदारी इन संस्थाओं में शामिल पश्चिमी देशों और दूसरे ताकतवर देशों की है ताकि वे इनके बहुपक्षीय ढांचे को इस प्रकार फिर से खड़ा कर सके कि वे नए अंतर्राष्ट्रीय हालात की हकीकत और जरूरत का प्रतिनिधित्व कर सकें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुपक्षीयता का सिद्धांत और उससे जुड़े संस्थानों पर अप्रासंगिक होकर कहीं खो जाने का ख़तरा बढ़ता जाएगा। ❑

तकनीकी युग में नए राजनयिक आयाम

पश्यंती शुक्ला

सोशल मीडिया आज एक हथियार सा बन गया है और सभी अपने-अपने तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यह हथियार है संदेशों के सधे हुए आदान-प्रदान का। ऐसे में राजनयिक संवाद में तो इसकी अहमियत होगी ही। भारत के रहनुमाओं ने इसको बखूबी समझा है और इसका इस्तेमाल भी किया है। प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्रालय तक इस मंच पर सफलतापूर्वक अपनी बात रख पा रहे हैं और दुनिया को समझा पा रहे हैं

वर्तमान सरकार ने बीते एक साल में राजनय को नए अंदाज में पेश करते हुए विदेश नीति में नयी कहानी लिखी है। सरकार की नई और ऊर्जावान विदेश नीति दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल रही है कि यही कारण है जानकार सरकार के एक साल के कार्यकाल को भारतीय विदेश नीति के एक नए अध्याय के तौर पर देख रहे हैं। यहां तक कि स्वयं विदेश मंत्री ने सरकार के 6 महीने पूरे होने के बाद के कार्यकाल पर टिप्पणी करते हुए 2014 को 'राजनय की नई राहों का वर्ष' माना था साथ ही यह भी कहा था कि 2015 'विकास के राजनय' के नाम होगा।

बीते एक साल में राजनयिक जगत की इन नई राहों के तहत जहां छोटे देशों के साथ दोस्ती पर बल दिया गया, पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की गई, वहीं अमेरिका, जापान, चीन और फ्रांस जैसे देशों की यात्रा कर प्रधानमंत्री ने 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की अच्छी मार्केटिंग कर भारत को दुनिया के समक्ष ब्रांड इंडिया के तौर पर पेश किया, जिसका सीधा लाभ विदेशी निवेशकों के भारत के प्रति सेंटिमेंट्स को सुधारने में मिला है। यही कारण है कि भारत वैश्विक पटल पर अपनी एक सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रहा है जिसमें भारत सरकार के यमन में चलाए गए 'ऑपरेशन राहत' जैसे विभिन्न साहसिक फैसले, प्रधानमंत्री की लगभग डेढ़ दर्जन विदेश यात्राओं समेत विभिन्न मंत्रियों की करीब 115 विदेश यात्राएं, आपदाग्रस्त नेपाल की मदद को स्वयं आगे आने के साथ-साथ 'सॉफ्ट डिप्लोमेसी' के वे नए आयाम भी शामिल हैं जिनका लाभ उठाने में पिछली सरकार बहुत पीछे छूट गई।

डिजिटल डिप्लोमेसी (ट्विप्लोमेसी)

प्रधानमंत्री घरेलू स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इच्छानुसार अपने संदेश देने में सफल रहे हैं और इन संदेशों को मिनटों में दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाने में ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया माध्यमों की विशेष भूमिका रही है। लोकप्रियता के ग्राफ में प्रधानमंत्री को मिली लगातार ऊंचाईयों ने देश की छवि मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई और प्रतिद्वंद्वियों को एक मजबूत संदेश दिया है। 16 मई 2014 को चुनाव जीतने के तुरंत बाद किया गया प्रधानमंत्री का ट्विट 'इंडिया हैज वन! भारत की विजय। अच्छे दिन आने वाले हैं' 74 हजार से ऊपर री-ट्विट किया गया जो अपने आप में एक रिकार्ड है। यानि नई सरकार के कामकाज में डिजिटल माध्यमों की क्या भूमिका रहने वाली है इसका संदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ओर से पदभार संभालने से पहले ही होने वाले प्रधानमंत्री की ओर से दे दिया गया था। सोशल मीडिया पर अपनी शुरुआत के समय से ही प्रधानमंत्री उस माध्यम पर अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के संपर्क में रहे हैं और ये हस्तियां भी उनको फॉलो करती रही हैं। सार्वजनिक मंचों पर राजनयिक संदेशों का यह द्विपक्षीय आदान-प्रदान आज डिप्लोमेसी को बंद कमरे की नीति से कहीं अलग ला खड़ा करता है।

डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स में जिस तरह की सक्रियता आजकल सोशल मीडिया पर

लेखिका स्वतंत्र पत्रकार और ब्लागर हैं। पूर्व में वह विभिन्न समाचार चैनलों व पत्रों के लिए काम कर चुकी हैं। नीतिगत मुद्दे, नारी विमर्श आदि उनके पसंदीदा विषय हैं। इन विषयों पर सोशल मीडिया उनकी मुखर उपस्थिति रहती है। ईमेल: pashyanti.zeenews@gmail.com, ट्विटर: @pashyantii

रहती है उसकी शुरुआत भले ही 6 साल पहले संप्रग सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे शशि थरूर ने की हो लेकिन उसके जरिए अपने साथ-साथ भारत की छवि निर्माण करने का काम वर्तमान सरकार ने किया है।

केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, अन्य मंत्रालय भी सूचना-प्रौद्योगिकी के इस उपकरण का इस्तेमाल बेहतर संवाद के लिए कर रहे हैं। इनमें विदेश मंत्रालय भी अहम है। स्वयं विदेश मंत्री से लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता तक ट्विटर और फेसबुक जैसे मंचों पर लाखों फॉलोवर के साथ सक्रिय हैं। इतना ही नहीं विदेश में मौजूद भारतीयों के साथ उनकी जरूरतों में संवाद करना इसी नीति का हिस्सा है। इसे प्रशंसकों ने भी हाथों-हाथ लिया है और अपनी आवश्यकतानुसार इसका उपयोग किया है जिससे विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों, उच्चायोगों और सबसे आगे बढ़कर भारत की छवि निखरी है।

वर्तमान सरकार की तमाम राजनयिक सफलताओं की चर्चा की जाए तो नेपाल और यमन में चलाए गए 'ऑपरेशन मैत्री' और 'ऑपरेशन राहत' का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है। वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में इन दोनों ही अभियानों का खासा योगदान रहा है।

प्रधानमंत्री की ट्विटर रणनीति पर मिशिगन यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर जायजित पाल ने शोध किया है। 'बनलिटीज टर्नड वायरल: नरेंद्र मोदी एंड द पॉलिटिकल ट्वीट' नामक अपने शोध में पाल लिखते हैं कि 'मोदी ने सफलतापूर्वक सामाजिक मीडिया का इस्तेमाल कर के भारत की युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं के साथ खुद को जोड़ लिया हैं,' चुनाव प्रचार के दौरान उनके ट्विट उनकी राजनीतिक सोच के बारे में अधिक संकेत देता थे। वर्तमान में प्रधानमंत्री के निजी क्षेत्र @narendramodi के ट्विटर पर एक करोड़ 20 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं जो उन्हें इस सोशल मीडिया माध्यम पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बाद दूसरा सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता बनाता है। भारतीय प्रधानमंत्री ट्विटर के अलावा फेसबुक, यूट्यूब, टम्बलर, लिंकडिन, पिन्ट्रेस्ट और स्टम्बलअपॉन पर भी एक्टिव हैं। नवंबर 2014 में उन्होंने अपनी

पहली पिक्चर इंस्टाग्राम पर डाली जो म्यांमार में हो रहे 25वें आसियान सम्मेलन की थी, इस तस्वीर को 32,000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया।

ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन राहत और सोशल मीडिया

वर्तमान सरकार की तमाम राजनयिक सफलताओं की चर्चा की जाए तो नेपाल और यमन में चलाए गए 'ऑपरेशन मैत्री' और 'ऑपरेशन राहत' का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है। वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में इन दोनों ही अभियानों का खासा योगदान रहा है। यहां उल्लेखनीय यह भी है कि इन दोनों ऑपरेशनों में भारत के प्रयासों से विश्वभर को परिचित कराने में सोशल मीडिया ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

यमन में करीब 9 दिन तक चले ऑपरेशन राहत के दौरान विदेश मंत्री ने स्वयं ट्विटर के जरिए लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया और यमन से 8 महीने के भारतीय बच्चे और उसकी यमन मूल की मां को निकालने में अहम भूमिका निभाई। बच्चे की मां सबा ने ट्विटर पर विदेश मंत्री से अपने बच्चे को निकालने की अपील की थी। भारत पहुंचने के बाद 6 अप्रैल को सबा ने ट्वीट किया 'आखिरकार हम सुरक्षित भारत पहुंच गए हैं, सुषमा स्वराज और उनकी शानदार टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद ..जय हिंद' इसके बाद विदेशमंत्री ने ट्वीट कर ही जवाब दिया, 'हमें धन्यवाद देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबा, यह हमारे देश और देशवासियों के प्रति हमारा कर्तव्य है, ईश्वर आपके बच्चे - (हमारे नन्हें नागरिक) पर कृपा बनाए रखें' विदेश मंत्री के इस ट्वीट को सोशल नेटवर्किंग साइट पर चौतरफा तारीफ मिली।

ट्विटर के जरिए विदेश मंत्रालय की ओर से यह भी बताया गया कि अमेरिका, स्वीडन, सिंगापुर, श्रीलंका व बांग्लादेश समेत 26 देशों ने लिखित संदेश भेजकर अपने नागरिकों को यमन से बाहर निकालने के लिए भारत की मदद मांगी। भारतीय सेना ने 10 दिन चले ऑपरेशन में करीब 5600 लोगों को बाहर निकाला, जिनमें 41 देशों के 960 नागरिक भी शामिल थे।

विदेश राज्यमंत्री जनरल वी के सिंह युद्ध प्रभावित यमन में स्वयं पहुंचे, देश के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी बचाव ऑपरेशन का नेतृत्व स्वयं सरकार के एक मंत्री ने मौके पर पहुंचकर किया था। सोशल मीडिया पर जनरल वी के सिंह को बहुत

ट्विटर के जरिए विदेश मंत्रालय की ओर से यह भी बताया गया कि अमेरिका, स्वीडन, सिंगापुर, श्रीलंका व बांग्लादेश समेत 26 देशों ने लिखित संदेश भेजकर अपने नागरिकों को यमन से बाहर निकालने के लिए भारत की मदद मांगी। भारतीय सेना ने 10 दिन चले ऑपरेशन में करीब 5600 लोगों को बाहर निकाला, जिनमें 41 देशों के 960 नागरिक भी शामिल थे।

समर्थन मिला और उनके समर्थन में शुरू किया गया #HatsoffGeneral हैशटैग लगभग दो दिन भारत में ट्रेंड करता रहा। इस हैशटैग ने अपनी उपस्थिति वर्ल्डवाइड भी दर्ज कराई जिसके जरिए भी भारत के सफलतापूर्वक खत्म हुए ऑपरेशन राहत की जानकारी विदेश तक पहुंची।

नेपाल त्रासदी के समय फिर एक बार सोशल मीडिया सूचना के एक मजबूत तंत्र के तौर पर भारत सरकार की ओर से इस्तेमाल किया गया। नेपाल में 25 अप्रैल 2015 को जब भूकंप आया तो वहां के प्रधानमंत्री थाइलैंड में थे, अपने देश में आई इस भीषण विपदा की जानकारी का पहला स्त्रोत उनके लिए भारतीय प्रधानमंत्री का 12 बजकर 23 मिनट पर किया गया वह ट्विट बना जिसमें उन्होंने लिखा था कि– 'नेपाल में भूकंप की जानकारी मिली है। भारत के भी कुछ स्थानों

में झटके महसूस किए गए', अगले ही मिनट 12 बजकर 24 मिनट पर उन्होंने फिर ट्विट किया जिसमें नेपाल की सहायता का ऐलान करते हुए लिखा- 'हम ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, नेपाल और भारत दोनों ही जगह प्रभावित इलाकों तक कैसे पहुंचा जाए इस पर काम कर रहे हैं'। नेपाल के विदेश मंत्री महेंद्र बहादुर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया था कि खुद उनके लिए भी नेपाल में भूकंप की सूचना का पहला स्रोत भारतीय पीएम का ट्विटर हैंडिल था।

भारत सरकार ने नेपाल त्रासदी के तुरंत बाद राहत-बचाव दल तो नेपाल रवाना किए ही साथ ही त्वरित जानकारी के आदान प्रदान के लिए ट्विटर का भी सहारा लिया। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से लगातार लोगों से ट्विटर के जरिए जानकारी साझा की जाती रही। स्वयं विदेश मंत्री ने नेपाल में फंसे कई भारतीयों के परिवारों की ट्विटर पर की गई अपील को सुनकर तुरंत एक्शन

भारत सरकार ने नेपाल त्रासदी के तुरंत बाद राहत-बचाव दल तो नेपाल रवाना किए ही साथ ही त्वरित जानकारी के आदान प्रदान के लिए ट्विटर का भी सहारा लिया। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से लगातार लोगों से ट्विटर के जरिए जानकारी साझा की जाती रही।

लेते हुए उनकी मदद की। सुपर्णा सिंह नामक एक महिला को उसके पिता से मिलवाने में विदेश मंत्री की भूमिका की काफी चर्चा हुई, इस महिला ने विदेश मंत्री को टैग करते हुए ट्विटर पर मदद की गुहार लगाई थी। भारतीय सेना के प्रयासों की प्रशंसा में ट्विटर पर #Salute2IndianForces हैशटैग से हजारों ट्वीट किए गए इन ट्वीट्स को करने वालों में भारत और नेपाल के तमाम नागरिकों समेत सैकड़ों विदेशी नागरिक भी थे। यही कारण था कि ट्विटर पर यह हैशटैग 30 अप्रैल को कई घंटों तक वर्ल्ड वाइड ट्रेंड करता रहा।

प्रधानमंत्री स्वंय खासे टेक सेवी माने जाते हैं। लिहाजा पदभार संभालने के बाद ही उनकी ओर से सभी मंत्रालयों और मंत्रियों को अपने अपने ट्विटर एकाउंट खोलने का संदेश दे दिया गया था। ट्विटर के जरिए ई-प्रशासन पर प्रधानमंत्री ने 30 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय

संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने के प्रस्ताव को अमेरिका व चीन समेत सभी के सभी 177 राष्ट्रों का समर्थन दिलवाना प्रधानमंत्री मोदी की योग डिप्लोमेसी की एक बड़ी सफलता माना जा रहा है।

सम्मेलन को संबोधित किया जिसकी मुख्य थीम 'डिजिटल गवर्नेंस-न्यू फ्रंटियर्स' थी। जुलाई 2014 में भारतीय विदेश मंत्रालय ने ''फॉलो योर पीएम' नाम से एक स्मार्टफोन एप लॉच किया जो उपयोगकर्ताओं को भारतीय विदेश नीति से जुड़ी सूचनाओं के साथ प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के बारे में सूचित करने के लिए बना।

विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता सैयद अकबरूद्दीन अपने कार्यकाल के दौरान, खासतौर से वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद से ट्विटर का इस्तेमाल करने में खासे सक्रिय माने जाते थे। सैयद अकबरूद्दीन को अपने कार्यकाल में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पद का सफलतापूर्वक कार्यभार संभालने वाले लोगों में जाना जाता था और साथ जनता से सीधा संवाद स्थापित स्थापित करने में भी उनका कोई मेल नही रहा। यही कारण था कि विदेश मंत्रालय से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी और अपडेट्स पर नजर रखने के लिए सैयद अकबरूद्दीन का ट्विटर एकाऊंट सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता था। अपने कार्यकाल के आखिरी दिन उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक सेल्फी लेकर उसे ट्विटर पर पोस्ट किया जिसमें लिखा 'काम के अंतिम दिन पर प्रधानमंत्री के साथ एक सेल्फी का अवसर मिला'। फिलहाल, विदेश मंत्रालय के नये प्रवक्ता विकास स्वरूप भी @meaindia हैंडल के साथ ट्विटर पर मौजूद हैं जहां उनके 3.64 लाख फॉलोअर हैं।

सेल्फी डिप्लोमेसी

प्रधानमंत्री की सेल्फी डिप्लोमसी भी बहुत खास है। चीन दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब चीन के प्रधानमंत्री ली किचियांग के साथ सेल्फी लेकर उसे चीन की सोशल नेटवर्किंग साइट वीबो पर हजारों बार रीट्वीट किया गया। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने इसे फेसबुक पर लाइक किया जिसके बाद यह सेल्फी पूरी दुनिया मे छा गई। प्रधानमंत्री मोदी की इस सेल्फी डिप्लोमेसी की चर्चा भारत और चीन से लेकर अमेरिका तक हुई। बीजिंग के मशूहर टेंपल ऑफ हेवेन में चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग के साथ ली गई इस अनौपचारिक सेल्फी के खास होने की वजह यह थी कि चीन में नेताओं का जन्मदिन तक 'स्टेट सीक्रेट' माना जाता है और अनौपचारिक तौर पर जनता के बीच वह अपनी उपस्थिति से बचते हैं ऐसे में इस तरह की अनौपचारिक मुस्कुराती हुई सेल्फी का सामने आना चीन के करोड़ों नागरिकों के लिए चौंकाने वाला था।

क्रिकेट डिप्लोमेसी

नवंबर के ऑस्ट्रेलिया दौरे मे प्रधानमंत्री मोदी की क्रिकेट डिप्लोमेसी पहली बार दुनिया के सामने आई। क्रिकेट के प्रति अपना खास लगाव दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में ग्राउंड अधिकारियों के साथ

बीजिंग के मशूहर टेंपल ऑफ हेवेन में चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग के साथ ली गई इस अनौपचारिक सेल्फी के खास होने की वजह यह थी कि चीन में नेताओं का जन्मदिन तक 'स्टेट सीक्रेट' माना जाता है और अनौपचारिक तौर पर जनता के बीच वह अपनी उपस्थिति से बचते हैं ऐसे में इस तरह की अनौपचारिक मुस्कुराती हुई सेल्फी का सामने आना चीन के करोड़ों नागरिकों के लिए चौंकाने वाला था।

भी तस्वीरें खिंचवाई। पीएम के उस बयान के सोशल मीडिया पर खासे चर्चे हुए जिसमें उन्होने मेलबर्न किक्रेट ग्राउंड की सराहना करते हुए कहा कि एमएसजी यानि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की यादें उनके साथ हमेशा जुड़ी रहेंगी, इस ऐतिहासिक मैदान पर बोलना मैकग्रा और ब्रेट ली की बॉलिंग के सामने सेंचुरी बनाने जैसा है जिसके बाद उन्होनें यह दौरा अपने चिरपरिचित अंदाज यानि ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ सेल्फी लेकर खत्म किया।

क्रिकेट डिप्लोमेसी का दूसरा पड़ाव फरवरी 2015 में आया जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तथा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाग लेने वाले दक्षेस देशों के अन्य प्रमुखों को विश्वकप के लिए भारत की ओर शुभकामनाएं दीं गईं और इसकी जानकारी

योग भारत की सांस्कृतिक-दार्शनिक विरासत माना जाता है ऐसे में विश्वभर में योग को भारत की देन के तौर स्थापित कर पीएम मोदी ने देश के आम जनमानस में भारतीय विद्याओं की वसीयत और विरासत को सहेज कर रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है।

ट्विटर के माध्यम से साझा की। वर्ल्ड कप में पांच दक्षेस देशों के खेलने पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने लिखा 'मुझे पक्का विश्वास है कि वर्ल्ड कप में खेल भावना का जश्न होगा और खेलप्रेमियों के लिए यह एक सौगात होगी।

योग और सांस्कृतिक राजनय

संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने के प्रस्ताव को अमेरिका व चीन समेत सभी के सभी 177 राष्ट्रों का समर्थन दिलवाना प्रधानमंत्री मोदी की योग डिप्लोमेसी की एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद दिसंबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लिखा- 'आह्लादित' मेरे पास इस खुशी को बयान करने के लिए शब्द नहीं है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं' योग भारत की सांस्कृतिक-दार्शनिक विरासत माना जाता है ऐसे में विश्वभर में योग को भारत की देन के तौर स्थापित कर पीएम मोदी ने देश के आम जनमानस में भारतीय विद्याओं की वसीयत और विरासत को सहेज कर रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है।

कुल मिलाकर देखें तो मई 2014 में देश को मिली नई सरकार कामकाज के दशकों पुराने ढर्रे को बदलकर उसमें जान फूंकने में सफल हुई है। सरकार प्राचीन संस्कृति और आधुनिकता के साथ सामंजस्य स्थापित कर डिप्लोमेसी के वह नए आयाम खोज रही है जिनके द्वारा प्राचीन सभ्यता को आधुनिक सांचे में ढालकर भारत की वास्तविक विश्वगुरु की

सरकार कामकाज के दशकों से चले आ रहे ढर्रे को बदलकर उसमे जान फूंकने में सफल हुई है। सरकार प्राचीन संस्कृति और आधुनिकता के साथ सामंजस्य स्थापित कर डिप्लोमेसी के वह नए आयाम खोज रही है जिनके द्वारा प्राचीन सभ्यता को आधुनिक सांचे में ढालकर भारत की वास्तविक छवि को पुनर्जीवित किया जा सके।

छवि को पुनर्जीवित किया जा सके। छोटे-छोटे त्योहारों के समय बधाई संदेशों से लेकर प्राकृतिक विपदाओं और मुसीबतों के समय सोशल मीडिया का सशक्त इस्तेमाल स्थापित कर यह संदेश देने में प्रधानमंत्री और उनकी टीम सफल हुई है कि वर्तमान सरकार यंग इंडिया की सरकार है, जिसे यह भलीभांति मालूम है कि घरेलू स्तर पर आम जनता से सीधा संवाद स्थापित कर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की मार्केटिंग 'ब्रांड इंडिया' की तरह कैसे करनी है। ❑

(पृष्ठ 22 का शेषांश)

आने वाले वर्षों में एक नए विकास में, सांस्कृतिक कूटनीति और लोगों से लोगों का जुड़ाव भारत और चीन के रिश्तों को और गहरा करने वाला है। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने चीन के दौरे के दौरान भारत और चीन के विस्तृत संबंधों के मध्य लोगों से लोगों के बीच के जुड़ाव को महत्व देने का प्रयास किया है। ताई-ची प्रदर्शन के संयुक्त मंचन ने यह स्थापित किया कि भारत और चीन के रिश्ते कितने प्रगाढ़ हो सकते हैं अगर साझे सांस्कृतिक संबंधों को द्विपक्षीय संबंधों को आकार देने की स्वतंत्रता दी गई तो। 15 मई को बीजिंग के टेंपल ऑफ हेवेन में एक अजब ही उत्साह का माहौल था जब प्रधानमंत्री और चीन के प्रीमियर के समक्ष चीन के बच्चों ने योग और भारत के बच्चों ने ताई ची का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि "मुझे खुशी है की प्रीमियर ने इस प्रोग्राम का आयोजन टेंपल ऑफ हेवेन करवाया। अगर स्वर्ग चाहिए तो शरीर और मन में सामंजस्य चाहिए। योग हमारे शरीर और मस्तिष्क को संतुलित करने की एक कला है। आज विश्व के हर हिस्से में निराशा का वातावरण छाया हुआ है। इससे बचने के लिए योग ही एकमात्र विकल्प है।" इससे बाद प्रधानमंत्री ने कहा ये एक अद्भुत संयोग है की चीनी बच्चे योग कर रहे हैं और भारतीय बच्चे ताई ची। यह एक दूसरे की राजनीतिक विरासत को जोड़ने का अद्भुत माध्यम है। हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। सांस्कृतिक संबंध को बढ़ाने के लिए कई नए कदम उठाए गए हैं जिनमें फुदान विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर गांधिनिअन स्टडीज की स्थापना, द्विपक्षीय थिंक टैंक फोरम की स्थापना, कुन्मिंग में योग कॉलेज की स्थापना और इंडियन कौंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के साथ यूनान नेशनल यूनिवर्सिटी के योग कॉलेज की स्थापना।

कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है। भारत और चीन के बीच में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए वर्तमान लिपुलेख दर्रे के अतिरिक्त सिक्किम के नाथूला दर्रे से भी रास्ता बनाया जाएगा। नाथूला दर्रे वाला यह रास्ता वृद्ध जनों के लिए भी यात्रा को सुगम बनाएगा और कठिनाइयों को कम करते हुए यात्रा के समय में भी कमी करेगा।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ने एक तरफा फैसला लेते हुए चीनी पर्यटकों के लिए ई-वीजा सुविधा की घोषणा की जिसका सिंघुआ विश्वविद्यालय के छात्रों ने ताली बजा के स्वागत किया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इसे तोहफा कहा। उन्होंने कहा कि ष्यह एक बड़ी खबर है। भारतीय प्रधानमंत्री को इस तोहफे के लिए शुक्रिया अदा करें।

2015 में जारी विजिट इंडिया इयर इन चाइना और 2016 में विजिट चीन इयर से लोगों के बीच में संवाद में वृद्धि की संभावना है। एक दूसरे के बारे में पूर्वाग्रहों को बदलने में संयुक्त फिल्म निर्माण पर समझौते का लागू होना भी इन परिवर्तनों को नई दिशा देने वाला होगा। फिल्म थ्री इडियट और पी के की लोकप्रियता इस क्षेत्र में संभावनाओं को प्रदर्शित करती है। लोकप्रिय संस्कृति एशिया की दो उभरती हुई शक्तियों के बीच में एक शक्तिशाली सूत्र और सेतु निर्माता के रूप में स्थापित हुई है जो आपस में एक उदार मूल्य प्रणाली, पारिवारिक परंपराओं के प्रति आदर और शिक्षा पर बल व दिमागी विकास द्वारा एक दूसरे से जुडी हुई हैं। ❑

संभावनाओं से भरपूर 'एक्ट ईस्ट'

रहीस सिंह

एक्ट ईस्ट से सर्वाधिक लाभ पूर्वोत्तर को मिलेगा। भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के तमू-कलेवा-कलेम्यो सेक्टरों के पूरे होने पर पूर्वोत्तर के राज्यों की आर्थिक गतिशीलता बढ़ जाएगी। पूरब की नीति में नया आयाम जोड़ने का निर्णय लिया है। इस नीति पर आगे जाने के लिए रास्ता तीन 'सी' यानि कामर्स, कल्चर और कनेक्टिविटी से होकर जाता है। एक्ट ईस्ट होगा तभी नई विश्व व्यवस्था में भारत अपनी क्षमता प्रदर्शित कर पाएगा। भारत को पूर्वी एशिया और आसियान बाज़ारों में घुसने के लिए चीन, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों के साथ प्रतियोगिता करनी है। इसके लिए भारत को 'मेक इन इंडिया' को साकार करने के साथ-साथ सेवा क्षेत्र में भी नवोन्मेषी बनना पड़ेगा

गत वर्ष अगस्त माह में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हनोई में जब यह कहा था कि अब समय आ गया है कि भारत 'लुक ईस्ट' की जगह 'एक्ट ईस्ट पालिसी' को अपनाए क्योंकि अब समय सिर्फ देखने का नहीं बल्कि करने का है। बाद में आसियान सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में इस बात पर जोर दिया कि नये युग के साथ आगे बढ़ने के लिए 'लुक ईस्ट' को नहीं 'एक्ट ईस्ट' नीति को बढ़ाना है। इसका तात्पर्य यही हुआ कि भारत अब 'जानने की सीमा' को पार कर चुका है इसलिए उसे अब 'एक्ट मोड' में आ जाना चाहिए। यह सच है कि भारत को यदि जनसांख्यिकीय लाभांश (डेमोग्राफिक डिविडेंड) प्राप्त करने का लक्ष्य है तो एक्ट मोड में आना पड़ेगा लेकिन इसके बावजूद कुछ पक्ष जानने ज़रूरी हैं। पहला यह कि क्या पिछले ढाई दशक में भारत उन बाधाओं को पार करने में सफल हो गया है, जिनके कारण उसे देखने की नीति का अनुसरण करना पड़ा था? दूसरा यह कि क्या भारत अपनी स्वयं की अन्वेषण क्षमता अथवा अन्वेषणात्मक प्रकृति, नवोन्मेष की स्थिति, कुशलता और प्रतियोगी क्षमता का सही आकलन कर चुका है? तीसरा यह क्या भारत अब उन दायरों से परे जाकर ऐसी वृहत्तर व्यवस्था का निर्माण करने में समर्थ हो चुका है जिससे कि अगली सदी भारत और भारतीयों के नाम हो सके या अभी इस दिशा में काफी परिश्रम करने की जरूरत होगी?

'एक्ट ईस्ट' नीति को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के उन शब्दों में देखा जा सकता है जो उन्होंने वर्ष 2014 की दूसरी छमाही में सरकार की विस्तारवादी कूटनीति की सक्रियता के बारे में बोलते हुए संसद में कहे थे। उन्होंने संसद को बताया था कि ''प्रधानमंत्री जी ने विदेश नीति, जो राष्ट्रीय आर्थिक विकास को गति प्रदान करने की हमारी सरकार की प्राथमिकता लक्ष्य से जुड़ा हुआ है, इसके लिए उन्होंने सकारात्मक और नवोन्मेषी दृष्टिकोण अपनाए जाने की सिफारिश की है। भारत को पूंजी, प्रौद्योगिकी, संसाधन, ऊर्जा, बाज़ार और कौशल तक पहुंच, एक सुरक्षित वातावरण, पड़ोसी का शांतिपूर्ण व्यवहार तथा एक स्थिर वैश्विक व्यापार प्रणाली की आवश्यकता है।'' इसके लिए पूरब के देशों के साथ संबंधों में नये आयामों की ज़रूरत होगी और यह सब केवल पूरब की ओर देखने से संभव नहीं हो सकता बल्कि कार्य करने से ही हो सकता है। हालांकि देखने की नीति में अध्ययन और अवलोकन का पक्ष जुड़ा होता है लेकिन यह तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है इसलिए देखने की प्रक्रिया में निहित ठहराव से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वैसे भी भारत ने वैश्वीकृत व्यवस्था में कदम रखने के बाद से अब तक जो प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्मित किया है उसे देखते हुए यह स्वीकार किया जा सकता है कि भारत पूरब में कूटनीतिक-आर्थिक 'रनवे' तैयार कर चुका है और उड़ान भरने (टेक ऑफ) का समय है जिसे देखते हुए सक्रिय होने की ज़रूरत होगी।

आज भारत-आसियान क्षेत्र के पास करीब 1.9 अरब की आबादी है और 4 खरब

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने ऐतिहासिक-सामाजिक, आर्थिक विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। ये पुस्तकें प्रकाशन केंद्र (लखनऊ), पियर्सन (किंडर्सले डार्लिंग प्रकाशन ब्रिटेन की दक्षिण एशिया के लिए फ्रेंचाइजी) तथा हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय आदि प्रतिष्ठित प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की गई है। एक अन्य पुस्तक ''नई विश्व व्यवस्था में भारत'' प्रकाशनाधीन है। ईमेल: raheessingh@gmail.com

अमेरिकी डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था। इसका लाभ उसे ही प्राप्त होगा जो आज की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने की क्षमता रखता होगा। स्वाभाविक तौर पर भारत को 'लुक' की जगह 'एक्ट' की रणनीति अपनाने की ज़रूरत है। संभवत: प्रधानमंत्री ने इस स्थिति का अवलोकन करते हुए पूरब की नीति में नया आयाम जोड़ने का निर्णय लिया है। इस नीति पर आगे जाने के लिए रास्ता तीन 'सी' यानि कामर्स (वाणिज्य), कल्चर (संस्कृति) और कनेक्टिविटी (संपर्क), से होकर जाता है। यह बात एशियाई देशों के साथ भारत के जुड़ने की नहीं है बल्कि आज का संपूर्ण विश्व व्यापक संपर्कों के इर्द-गिर्द घूम रहा है जिसके मूलभूत उपकरण हैं-सड़क, रेलमार्ग, समुद्री बंदरगाह के साथ-साथ विचार और आभासी राजमार्ग (वर्चुअल हाइवे)। सड़क, रेलमार्ग, जलमार्ग और समुद्री बंदरगाहों के जरिए जहां भौतिक अवसंरचनाओं को जोड़ा जा सकता है वहीं विचार के जरिए राष्ट्र की सीमाओं के भीतर और उसके बाहर एक ऐसा सेतु तैयार किया जा सकता है जो सांस्कृतिक और भावनात्मक संबद्धता के लिए ज़रूरी है। आज के डिजिटल युग में, आभासी राजमार्ग (वर्चुअल हाइवे) अपनी व्यापक भूमिका में आ चुके हैं लेकिन इन राजमार्गों के अपने ख़तरे हैं और नेवीगेशन के अपने तरीके व क्षेत्र जिसके लिए अलग तरह की कुशलता की आवश्यकता होती है। यह संपर्क को जितना ही आसान बनाता है उतने ही तरह की चुनौतियां भी साथ लाता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या भारत डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट के महासागर में नेवीगेशन या आभासी राजमार्गों पर फर्राटा भरने की कुशलता प्राप्त कर चुका है? दूसरा सवाल यह है कि क्या इन आभासी साधनों के उपलब्ध होने मात्र से ही बात पूरी हो जाएगी अथवा क्या भौतिक और डिजिटल अवसंरचना तैयार कर लेना ही पर्याप्त है? क्या इसके लिए नीतिगत, विनियामक और प्रक्रियागत आवश्यकताएं जरूरी नहीं होंगी? क्या इनके लिए उस कुशलता की जरूरत नहीं होगी जो हमारे संपर्कों के उद्देश्यों और उसके मायनों को निर्धारित करे? क्या भारत के पास इन सभी प्रश्नों का सकारात्मक जवाब देने की मेधा वर्तमान में है?

बात एशियाई देशों के साथ भारत के जुड़ने की नहीं है बल्कि आज का संपूर्ण विश्व व्यापक संपर्कों के इर्द-गिर्द घूम रहा है जिसके मूलभूत उपकरण हैं-सड़क, रेलमार्ग, समुद्री बंदरगाह के साथ-साथ विचार और आभासी राजमार्ग (वर्चुअल हाइवे)। सड़क, रेलमाग, जलमार्ग और समुद्री बंदरगाहों के जरिए जहां भौतिक अवसंरचनाओं को जोड़ा जा सकता है वहीं विचार के जरिए राष्ट्र की सीमाओं के भीतर और उसके बाहर एक ऐसा सेतु तैयार किया जा सकता है जो सांस्कृतिक और भावनात्मक संबद्धता के लिए जरूरी है।

उदाहरण के तौर पर भारत 1951 के 4 लाख किमी सड़क मार्ग के मुकाबले 2013 में 4.6 मिलियन किमी सड़क मार्ग का निर्माण करा चुका है लेकिन उसकी गुणवत्ता, राजमार्ग का संपूर्ण सड़कों के मुकाबले प्रतिशत और उन पर चेकप्वाइंट्स की उपस्थिति विकसित दुनिया के मुकाबले कितनी है, यह हमें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार प्रस्तावित हाई स्पीड फ्रेट कॉरीडोर से देश में रेल परिवहन में बड़ा और महत्वपूर्ण सुधार होने की संभावना है लेकिन वर्तमान अवसंरचना क्या इसकी इजाज़त देती है। संचार पर बात करें तो भारत में मोबाइल टेलीफोन के साथ आई संचार क्रांति ने देश में 900 मिलियन से अधिक लोगों तक मोबाइल पहुंचा दिया और इसमें प्रतिवर्ष काफी बढ़ोत्तरी हो रही है। इससे संपर्क, नए बाज़ारों के सृजन, उत्पादकों को उपभोक्ताओं से अधिक प्रभावशाली ढंग से जोड़ने और समुदायों के बीच विशाल मात्रा में डाटा के निर्बाध प्रवाह में सक्षम बनाने के लिए मंच होना चाहिए और होता भी है, लेकिन इसकी गुणात्मक प्रगति उतनी नहीं है जितनी कि एक प्रतियोगी देश के लिए होनी चाहिए।

पड़ोसी से संपर्क (कनेक्टिविटी) की बात करें तो भारत ने आसियान देशों के साथ अपने संपर्क को प्राथमिकता दी है और भारत व आसियान अपनी-अपनी संपर्क योजनाओं का निर्माण भी कर रहे हैं। इनमें सीमा-पार रेल एवं सड़क संपर्क, सामुद्रिक, वायुमार्गीय एवं डिजिटल संपर्क शामिल हैं। लेकिन अभी इन्हें बेहतर संभारतंत्रीय एवं प्रभावी सीमा-स्वीकृतियों के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ा जाना बाकी है और जब तक ऐसा नहीं हो पाता तब तक भारत के लिए क्षेत्रीय एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भाग लेना संभव नहीं हो पाएगा।

वाणिज्य (कामर्स) के लिहाज से देखें तो भारत और आसियान, आर्थिक स्पंदनशीलता, नवाचार और उद्यम का केंद्र हैं। इसलिए इस क्षेत्र में व्यापार संभावनाएं अधिक होनी चाहिए। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो इस क्षेत्र के साथ मुक्त व्यापार समझौता हस्ताक्षरित होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार में मात्रात्मक उछाल आया है जो इस समय लगभग 80 अरब डॉलर के आसपास है। दोनों पक्ष इसे 2015 तक 100 बिलियन डॉलर तक और वर्ष 2022 तक 200 बिलियन डॉलर के स्तर तक ले जाने के प्रति आश्वस्त हैं। रोजगार सृजन के लिहाज से निवेशों की आवश्यकता होती है। भारत के लिए इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि भारत के युवा वर्ग का आकार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसी के संगत अनुपात में बेरोजगारों का आकार भी चिंताजनक होता जा रहा है।

वाणिज्य (कामर्स) के लिहाज से देखें तो भारत और आसियान, आर्थिक स्पंदनशीलता, नवाचार और उद्यम का केंद्र हैं। इसलिए इस क्षेत्र में व्यापार संभावनाएं अधिक होनी चाहिए। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो इस क्षेत्र के साथ मुक्त व्यापार समझौता हस्ताक्षरित होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार में मात्रात्मक उछाल आया है जो इस समय लगभग 80 अरब डॉलर के आसपास है।

अगर तमाम अध्ययनों की बात मानी जाए तो 2014 से पहले एक दशक में 'शून्य रोजगार वाली ग्रोथ' रही। ऐसे में भारत को तेजी से निवेशों की ज़रूरत है। हालांकि पिछले आठ वर्षों में आसियन देशों ने भारत 27.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का का निवेश किया जबकि भारत न 32.4 बिलियन डॉलर का लेकिन अब विशेषकर 'मेक इन इंडिया' प्रोजेक्ट के तहत विशेषकर पूरब के देशों से निवेश आने की संभावनाएं अधिक हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री की इसे क्षेत्र के देशों की यात्राओं के समय उनके नेतृत्व द्वारा दिए गये आश्वासनों से लगता है। वाह्य व्यापार के लिए यह आवश्यक होता है कि कूटनीतिक और सामरिक संबंध बेहतर रहें। इस दृष्टि से दोनों पक्ष ट्रांस-नेशनल आतंकवाद, तटीय दस्युता और परमाणु प्रसार के मुद्दे पर

सहयोग की दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं।

भारत और आसियन देशों में सांस्कृतिक समरूपता के व्यापक तत्व विद्यमान हैं जिसके चलते दोनों के बीच मानसिक एवं आध्यात्मिक ऊर्जा संबंधों की स्फूर्त करने में मदद कर सकती है। आज भी भागवत पुराण में 'भूमि कान्चन्य' के वर्णन में लिखे गए ये शब्द-''मेरु से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक जितना अंतर है, उतनी ही भूमि शुद्धोदक समुद्र के उस ओर है। उसके आगे सुवर्णमयी भूमि है जो दर्पण के समान स्वच्छ है। इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं मिलती, इसलिए वहां देवताओं के अतिरिक्त कोई प्राणी नहीं रहता।'', पूरब के देशों के लोगों के हृदय को स्पंदित करते हैं जिससे उनमें भारत के प्रति आकर्षण बढ़ता है। ऐसे में यदि भारतीय संस्कृति को कूटनीतिक में सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सका तो

भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के तमू-कलेवा-कलेम्यो सेक्टरों के पूरे होने पर पूर्वोत्तर के राज्यों की आर्थिक गतिशीलता बढ़ जाएगी। भारत की योजना कंबोडिया, लाओ पीडीआर, म्यांमा और वियतनाम में चार सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की है। इसका असर पूर्वोत्तर पर दिखेगा। दरअसल पूर्वोत्तर के राज्य पूरब के लिए प्रवेश द्वार हैं। इसलिए पूरब के साथ भारत के जुड़ाव का लाभ इन राज्यों का अवश्य मिलेगा।

इसके कम से कम पूर्वी एशिया के देशों की तरफ काफी अच्छे परिणाम आएंगे। फिलहाल तमाम सभ्यतागत स्मृतियां हैं जो पूर्वी व दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में मौजूद हैं, भारत के साथ साझी विरासत का निर्माण करती हैं।

दरअसल 1990 के दशक में भारत ने अपने आर्थिक नजरिए को बदला तो उसने सबसे पहले दक्षिण-पूर्व एशिया की ओर ही देखा। उस समय दुनिया शीतयुद्ध की छाया से निकलकर पूंजीवाद के कृत्रिम प्रकाश को दैवीय समझकर उड़ान भरने के लिए अपने पंख फैलाकर आतुर हो रही थी। भारत भी दुनिया के उन देशों में से एक था जिसने भी शायद कुछ ऐसा ही सपना देखा था। उसने क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपने आपको दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ जोड़ने की रणनीति अपनाने का निर्णय लिया। इस दृष्टि से 1991 भारत के लिए राजनीतिक बदलाव का वर्ष था। इस दिशा में पहला कदम बढ़ाने का कार्य तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहराव ने किया था और अटल बिहारी वाजपेयी तथा मनमोहन सिंह ने उसे समृद्ध व ठोस आधार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नीति में कुछ नये आयामों को जोड़कर इसे रणनीति रूप देने की अपनी मंशा को व्यक्त किया है। इस नीति से सबसे अधिक इससे सबसे अधिक लाभ पूर्वोत्तर भारत को मिलेगा जो अभी तक पूरी तरह से मूलधारा में शामिल नहीं हो पाया है। भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के तमू-कलेवा-कलेम्यो सेक्टरों के पूरे होने पर पूर्वोत्तर के राज्यों की आर्थिक गतिशीलता बढ़ जाएगी। भारत की योजना कंबोडिया, लाओ पीडीआर, म्यांमा और वियतनाम में चार सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की है। इसका असर पूर्वोत्तर पर दिखेगा।

दरअसल पूर्वोत्तर के राज्य पूरब के लिए प्रवेश द्वार हैं। इसलिए पूरब के साथ भारत के जुड़ाव का लाभ इन राज्यों का अवश्य मिलेगा। उल्लेखनीय है कि भारत का यह हिस्सा (पूर्वोत्तर राज्य) प्रभूत प्राकृतिक संसाधन व जैवविविधता, हाइड्रो-एनर्जी की पर्याप्त संभावनाओं से संयुक्त, तेल व गैस, कोयला, चूना, वन संपदा, फल और वनस्पति, फूल, हर्ब्स और सुगंध युक्त पौधों, विरल और धनी 'फ्लोरा और फौना' (प्रादेशिक वनस्पतियां और पशुवर्ग) के वरदान से परिपूर्ण है। भारत के इस क्षेत्र के पास वे सभी संभाव्यताएं हैं जो उसे वाणिज्यिक धुरी (हब) और पयर्टक स्वर्ग में रूपांतरित करने के लिए पर्याप्त हैं। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण पूर्वोत्तर के सभी भारतीय राज्य अकेले ही या मिल-जुलकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए आर्थिक और व्यापार के विशेष अवसर उपलब्ध कराने में समर्थ होते रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मणिपुर ऊर्जा, कृषि-आधारित उद्योग आदि के क्षेत्र में विशिष्ट और पर्याप्त क्षमताओं से सम्पन्न है। असम हाइड्रोकार्बन, तेल और प्राकृतिक गैस, बांस, हथकरघा और चाय उद्योग के क्षेत्र में निवेश की पर्याप्त संभावनाएं रखता है। मिजोरम के पास 90 प्रतिशत से अधिक साक्षरता की विशेषता तो ही है साथ ही वह कुशल शिक्षित और कठोर परिश्रमी युवा जनसंख्या जैसे मानव संसाधन से सम्पन्न है, जो विदेशी और घरेलू कारपोरेट को सक्रिय सुविधा (डायनामिक एडवांटेज) प्रदान कर सकता है।

पूर्वोत्तर की विशिष्ट सापेक्षिक महत्ता दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए बहुत सी शुभकामनाओं का कार्य कर सकती हैं, जो भारत के साथ पारस्परिक लाभ के लिए निकट आने की भरसक कोशिश कर रहा है। पूर्वोत्तर के साथ दक्षिण पूर्व एशिया का निकटतम सांस्कृतिक संबंध इस दिशा में और अधिक मदद करेगा। अगर पूर्वोत्तर अपने संसाधनों को सही तरह से सक्रिय कर ले जाता है तो व्यवसायिक पक्ष दक्षिण एशिया को आकर्षित करने में त्वरक की तरह कार्य करेगा। हालांकि 2 जुलाई 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 'पीस प्रोग्रेस एण्ड प्रॉस्पैरिटी इन द नार्थ ईस्टर्न रीजन : विज़न 2020' की घोषणा की थी जिसमें उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को दक्षिण ापूर्व एशिया, दक्षिण पश्चिम चीन और इससे भी दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने वाले 'इकोनॉमिक स्प्रिंगबोर्ड' कहा था। दुर्भाग्यवश अब तक यह

एक्ट ईस्ट का लाभ अवसंरचनात्मक विकास तथा रोजगार के क्षेत्र में मिल सकता है। इस दिशा में भारत आसियान के साथ सेवाओं और निवेश के क्षेत्र में मुक्त व्यापार समझौते पर 9 सितंबर 2014 को हस्ताक्षर कर चुका है जिससे दोनों के बीच जनशक्ति और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे।

क्षेत्र बहुत हद तक विलगाववादी नजरिए का शिकार रहा जिसके कारण इसकी क्षमता का प्रयोग नहीं हो पाया है।

एक्ट ईस्ट का लाभ अवसंरचनात्मक विकास तथा रोजगार के क्षेत्र में मिल सकता है। इस दिशा में भारत आसियान के साथ सेवाओं और निवेश के क्षेत्र में मुक्त व्यापार समझौते पर 9 सितंबर 2014 को हस्ताक्षर कर चुका है जिससे दोनों के बीच जनशक्ति और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने अगले पांच वर्षों में भारत में लगभग 35 अरब डालर की सहायता देने और निवेश करने का आश्वासन दिया है। यही नहीं जापान ने पूर्वोत्तर राज्यों में सड़क नेटवर्क का आधुनिकीकरण करने तथा समुद्रतटीय भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच मरीन गलियारा विकसित करने का वायदा किया है। चीन बीसीआईएम कोरिडोर जो चीन

के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत यूनान को म्यांमार, बांग्लादेश और भारत से जोड़ेगा, का विकास करने में भारतीय भागीदारी करना चाहता है। प्रधानमंत्री ने सियोल में इच्छा व्यक्त की थी कि भारत में जल, परिवहन, रेलवे, बंदरगाह, जहाज़ निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा सहित विद्युत, सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत ढांचा और सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण उद्योग क्षेत्रों में जो उभरती हुई संभावनाएं हैं, दक्षिण कोरिया उसमें अपनी निर्णायक भागीदारी निभाए।

दक्षिण कोरिया भारत के सामाजिक अवसंरचनात्मक क्षेत्र में भारी निवेशों के जरिए सक्रिय भागीदारी भी निभा सकता है जिससे प्रधानमंत्री की 2022 तक 5 करोड़ घर बनाने की योजना का तो स्फूर्ति मिलेगी ही, साथ ही स्मार्ट सिटी एवं इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के निर्माण में बेहतर सहयोग दे सकता है। संभावनाएं है कि दक्षिण कोरिया प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के तहत निवेश करता है तो भारत में रोजगारों में वृद्धि के साथ-साथ भारतीय बाज़ार में सकल मांग में वृद्धि होगी जिसका फायदा कोरियाई कंपनियों को भी मिलेगा। भारत-दक्षिण कोरिया के बीच सहयोग के कई क्षेत्र हो सकते हैं, विशेषकर भारत का सॉफ्टवेयर और कोरिया का हार्डवेयर उद्योग, कोरियाई कार निर्माण और भारतीय डिजाइन क्षमता, कोरियाई स्टील निर्माण क्षमता और भारतीय लौह अयस्क के संसाधन, कोरियाई जहाज़ निर्माण की क्षमता और भारतीय बंदरगाहों पर आधारित विकास। वैसे सेपा (कॉम्प्रेहेन्सिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट) के बाद से भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आर्थिक साझेदारी तेजी से बढ़ रही है और उम्मीद है कि आगे और तेजी से गति पकड़ेगी। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने 'एक्ट ईस्ट' नीति में दक्षिण कोरिया को 'एक अपरिहार्य भागीदार के रूप में' स्वीकार किया है।

एक्ट ईस्ट की नीति की ज़रूरत है तभी नई विश्व व्यवस्था में भारत अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर पाएगा। लेकिन भारत को यह भी देखना होगा कि एशिया-प्रशांत का यह क्षेत्र ऐसी चुनौतियों से सम्पन्न है जो भारत के लिए सामरिक संकट भी उत्पन्न कर सकता है। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जिसमें एशियाई ताकत बनने की पर्याप्त संभावनाएं हैं, लेकिन व्यवस्था, गवर्नेंस, अन्वेषण, नवोन्मेष और कुशलता के स्तर पर उसे अभी बहुत काम करना होगा।

कुल मिलाकर एक्ट ईस्ट की नीति की ज़रूरत है तभी नई विश्व व्यवस्था में भारत अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर पाएगा। लेकिन भारत को यह भी देखना होगा कि एशिया-प्रशांत का यह क्षेत्र ऐसी चुनौतियों से सम्पन्न है जो भारत के लिए सामरिक संकट भी उत्पन्न कर सकता है। एक अन्य पक्ष यह भी है कि भारत को पूर्वी एशिया और आसियान देशों के बाज़ारों में घुसने के लिए चीन, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों के साथ प्रतियोगिता करनी होगी जिसमें भारत अभी बहुत पीछे है। इसके लिए भारत को 'मेक इन इंडिया' को साकार करने के साथ-साथ सेवा क्षेत्र में भी नवोन्मेषी बनना पड़ेगा। फिलहाल भारत इस विचारधारा पर आगे बढ़ता दिख रहा है कि बीते कुछ बरसों में दुनिया का शक्ति केंद्र बदला है। लेकिन इस केंद्र तक भारत को पहुंचने में अभी बहुत वक़्त लगेगा। हां भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जिसमें एशियाई ताकत बनने की पर्याप्त संभावनाएं हैं, लेकिन व्यवस्था, गवर्नेंस, अन्वेषण, नवोन्मेष और कुशलता के स्तर पर उसे अभी बहुत काम करना होगा। स्वाभाविक है कि इसमें समय लगेगा। ❑

सार्क के चार देशों में ऐतिहासिक मोटर वाहन समझौता

दक्षेस के चार महत्वपूर्ण देशों भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश ने भूटान की राजधानी थिंपू में 15 जून, 2015 को ऐतिहासिक मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत यात्री और मालवाहक वाहनों की निर्बाध आवाजाही हो सकेगी। दक्षेस के इन चार महत्वपूर्ण देशों के बीच हुए इस समझौते से भारत समेत सभी देशों में लोग बेहद आसानी से आवाजाही कर सकेंगे।

इसके अलावा भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रीय एकता भी स्थापित हो सकेगी और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। इस समझौते को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, ''मोटर वाहन समझौता क्षेत्रीय संपर्क स्थापित करने की दिशा में हमारी व्यापक योजना के साकार होने जैसा है। इसके बाद जरूरी है कि इस परियोजना पर तेजी से काम हो ताकि दक्षेस देशों के बीच आम जन और माल का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित हो सके। इस समझौते को कामयाब बनाने और सामान, सेवाओं, पूंजी एवं तकनीक के सीमाओं के दोनों तरफ मुक्त आवागमन के लिए सड़कों के सुधार और निर्माण, रेल और जल परिवहन के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, ऊर्जा ग्रिड, संचार और हवाई यातायात को सुदृढ़ करने की आवश्यकता होगी। यदि हम इन दोनों मोर्चों पर काम करने में सक्षम हो पाते हैं तो दक्षेस के इन महत्वपूर्ण देशों में क्षेत्रीय एकता और विकास के पर्याप्त अवसर मौजूद होंगे।''

दक्षेस के अलावा आसियान देशों के साथ भी इस तरह के समझौते की दिशा में प्रयासों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, ''भारत-थाईलैंड-म्यांमार के बीच इस प्रकार के समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। तीनों देशों के बीच दक्षेस देशों की तरह ही मोटर वाहन समझौते को लेकर सहमति बनी है।'' दक्षेस के चारों देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर के बाद संयुक्त बयान में कहा, इस समझौते के बाद दक्षेस देशों का आपस में 60 फीसदी कारोबार हो सकेगा। जबकि दुनिया के अन्य देशों के साथ यह कारोबार महज 30 फीसदी के आसपास ही रह जाएगा। भारत-बांग्लादेश-नेपाल और भूटान (बीबीआईएन) के बीच आर्थिक गलियारे के विकास के साथ ही उसके रेगुलेशन के लिए भी नियमों की आवश्यकता थी, जो मोटर वाहन समझौते से पूरी हो सकेगी।''

ब्रिक्स की तर्ज पर ही चारों देशों की इस यूनियन को बीबीआईएन नाम दिया गया है। चारों देशों के बीच लोगों और सामान के मुक्त आवागमन, क्षेत्रीय एकता, व्यापार को बढ़ावा देने और मित्रता की भावना प्रदर्शित करने के लिए इसी साल अक्टूबर में एक फ्रेंडशिप रैली का भी आयोजन किया जाएगा।

मध्य-पूर्व की ओर संतुलित कदम

संजय राय

किसी भी शिक्षित व्यक्ति से यह पूछा जाए कि देश में सबसे ज्यादा डॉलर कहां से आता है, उसका जवाब होगा अमेरिका लेकिन प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स में कुछ साल पहले एक सर्वे छपा था। जिसका निष्कर्ष चौंकाने वाला था। अमेरिका से भी ऊपर अगर कोई देश है तो वह है संयुक्त अरब अमीरात। तीसरे नंबर का देश इसी इलाके में बसा सऊदी अरब है। इन सभी तथ्यों को देखते हुए साफ समझा जा सकता है कि पश्चिम एशिया के साथ भारत के सुरक्षा और रणनीतिक हित काफी गहराई से जुड़े हुए हैं

मध्यपूर्व जिसे भारत के मीडिया जगत में पश्चिम एशिया के नाम से जाना जाता है, कुल 17 से 19 देशों का समूह है, जिसमें अधिकतर इस्लामिक देश हैं। इसी क्षेत्र में चारों तरफ इस्लामिक राष्ट्रों की लगभग 41 करोड़ आबादी से घिरा 84 लाख की आबादी वाला देश इजराइल है जो समस्त इलाके की कुल आबादी का मात्र 2 प्रतिशत है, लेकिन पश्चिम एशिया की राजनीति पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव है। इस प्रभाव के पीछे इजराइल की आत्म-जिजीविषा और विशेष रूप से अमेरिका व ब्रिटेन का सहयोग प्रमुख कारण है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वर्षों से जारी दुश्मनी ने समूचे इलाके की राजनीति के साथ-साथ भारत पर गहरा असर डाला है।

समूचे पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंधों का इतिहास उतना ही पुराना है, जितना कि हिंद महासागर है। इस वास्तविकता को कोई नकार ही नहीं सकता है कि हिंद शब्द इसी इलाके में बोली जाने वाली अरबी भाषा से निकला हुआ है। दुनिया के सात महासागरों में यही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। भारत और मध्य पूर्व के बीच इस महासागर के अलावा जमीन से भी व्यापार होता था और सदियों से चली आ रही इस तिजारत ने एक दूसरे को अपने ज्ञान के भंडार से सदा समृद्ध किया है। अगर यह कहा जाए कि आधुनिक विश्व के विकास का मूल आधार भारत और मध्य एशिया की देन है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी।

लगभग एक हजार साल पहले अरब के प्रसिद्ध नक्षत्रशास्त्री, गणितज्ञ, इतिहासकार और पर्यटक अलबरूनी ने ईस्वी सन् 900 में भारत पर एक किताब लिखी थी। तारीख अल हिंद नाम की इस पुस्तक में अलबरूनी ने भारत के इतिहास, धर्म, भूगोल, गणित, भाषा, संस्कृति और समाज का निष्पक्ष और विश्वसनीय वर्णन किया है। पुस्तक में अलबरूनी ने हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच संबंधों के साथ-साथ हिंदुओं के विभिन्न वर्गों के बीच आपसी संबंधों की विस्तार से समीक्षा भी की है। माना जाता है कि अलबरूनी ने पतंजलि के योगसूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया। इस पुस्तक का नाम है- रिसाला फी फिहरिस्त। यहां से योग यूरोप में पहुंचा। सिखों के प्रथम गुरू नानक देव ने इजराइल के येरूशलम और मक्का-मदीना की यात्रा की थी। भारत और पश्चिम एशियाई देशों की भाषाओं में हजारों ऐसे शब्द हैं जो हमारे संबंधों की प्राचीनता और इसकी गहराई का प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं। स्पष्ट है भारत और पश्चिम एशिया के संबंधों का इतिहास काल गणना के दायरे से परे है। दुनिया में अरब से बाहर अरबी भाषा के सबसे ज्यादा जानकार भारत में हैं।

आज भी इस इलाके का हमारे लिए काफी ज्यादा महत्व है। भारत सरकार इस तथ्य को समझती है, लेकिन इस इलाके में राजनीतिक अस्थिरता और अंतर्कलह के अलावा अमेरिका और यूरोपीय देशों के मनमाने हस्तक्षेप के कारण भारत को कई तरह की चुनौतियों से जूझना पड़ता रहा है। भारत की लगभग 70 लाख आबादी पश्चिम एशिया में जीविकोपार्जन में जुटी हुई है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए इस इलाके पर पूरी तरह निर्भर रहा है। खनिज तेल और गैस का लगभग तीन-चौथाई

लेखक पिछले पंद्रह वर्षों से राष्ट्रीय मीडिया से जुड़े हैं और विदेश नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर लगातार लिखते रहे हैं। ईमेल: babasanjay.kumar@gmail.com

हिस्सा पश्चिम एशिया के देशों से ही पूरा होता है। किसी भी शिक्षित व्यक्ति से यह पूछा जाए कि देश में सबसे ज्यादा डॉलर कहां से आता है, उसका जवाब होगा अमेरिका लेकिन प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स में कुछ साल पहले एक सर्वे छपा था। जिसका निष्कर्ष चौंकाने वाला था। अमेरिका से भी ऊपर अगर कोई देश है तो वह है संयुक्त अरब अमीरात। तीसरे नंबर का देश इसी इलाके में बसा सऊदी अरब है। इन सभी तथ्यों को देखते हुए साफ समझा जा सकता है कि पश्चिम एशिया के साथ भारत के सुरक्षा और रणनीतिक हित काफी गहराई से जुड़े हुए हैं। सभ्यता के आरंभ से ही भारत के लिए हर नजरिए से उपयोगी रहे इस इलाके को लेकर हमारी विदेशनीति में जो प्रखरता दिखाई देनी चाहिए वह अब तक कहीं न कहीं गायब रही थी। यहां सिर्फ मानव संसाधन के सहारे हमारी अर्थव्यवस्था को जो मजबूती मिलती रही है, वह समय-समय पर आंतरिक उथल-पुथल के बहुत ही नाजुक दौर से गुजरी है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार के पास अपने नागरिकों को इन इलाकों से आपात योजना के तहत निकालने के अलावा कोई दूसरा रास्ता अब तक नहीं दिख पाया है।

भारत के पास इस इलाके में अवसंरचना, विज्ञान, चिकित्सा, अंतरिक्ष और कृषि के अलावा सूचना तकनीक के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता से कमाई करने का अपार अवसर उपलब्ध है और यह समय की मांग है कि भारत इस दिशा में अब जल्द से जल्द ठोस पहल करके कदम आगे बढ़ाए। अमेरिका ने भारत को सस्ती कीमत पर शेल गैस देने का वादा किया है, लेकिन अघोषित शर्त यही थी कि भारत ईरान से तेल और गैस की खरीद को कम कर दे।

लंबे समय से इस बात की जरूरत महसूस की जाती रही है कि लुक ईस्ट और ऐक्ट ईस्ट की नीति को अमल में लाने की धुन में भारत की विदेशनीति के रणनीतिकारों का ध्यान पश्चिम एशिया पर जितना केंद्रित होना चाहिए था, उतना हो नहीं पाया। फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर हम सिद्धांत और जमीनी हकीकत के बीच अभी भी सही तरीके से तालमेल नहीं बैठा पाए हैं। फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान के परमाणु कार्यक्रम, इराक पर अमेरिकी हमले, आईएसआई की गतिविधियों जैसे विषयों पर विदेशनीति पाकिस्तान और मुसलमान के अलावा परमाणु हथियारों जैसे विषयों के मकड़जाल में लंबे अरसे से फंसी हुई है। इसे भारत की विदेशनीति के रणनीतिकार समझते तो हैं, लेकिन इससे बाहर निकलकर संबंधों को रणनीतिक स्तर तक लाने के लिए जो तेजी दिखनी चाहिए वह कहीं न कहीं गायब दिख रही है।

भारत की इस उलझन का फायदा अमेरिका और यूरोप के अलावा अब चीन भी बड़ी तेजी से उठाने में जुटा हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि पश्चिम एशिया में अभी अवसंरचना, विज्ञान, चिकित्सा, विमानन, अंतरिक्ष और कृषि के अलावा दूरसंचार व तकनीक के क्षेत्र में कार्य करने की असीम संभावनाएं बनी हुई हैं। चीन बड़ी तेजी से इसका फायदा उठाने में जुटा है। मक्का और मदीना के बीच बन रही रेल परियोजना को चीन पूरा कर रहा है। वहां के बाज़ार में भी चीन के उत्पाद छाए हुए हैं। इन क्षेत्रों में भारत अभी भी काफी पीछे है।

ईरान के साथ गैस पाईप लाइन लाने की योजना अमेरिका के दबाव में ठंडे बस्ते में चली गई है। भारत के पास इस इलाके में अवसंरचना, विज्ञान, चिकित्सा, अंतरिक्ष और कृषि के अलावा सूचना तकनीक के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता से कमाई करने का अपार अवसर उपलब्ध है और यह समय की मांग है कि भारत इस दिशा में अब जल्द से जल्द ठोस पहल करके कदम आगे बढ़ाए। अमेरिका ने भारत को सस्ती कीमत पर शेल गैस देने का वादा किया है, लेकिन अघोषित शर्त यही थी कि भारत ईरान से तेल और गैस की खरीद को कम कर दे। अब चर्चा यह है कि चीन इस पाइपलाइन को अपने देश में लाने के लिए तेजी से प्रयास कर रहा है।

वर्तमान प्रधानमंत्री के सत्ता संभालते ही भारत की विदेशनीति को इस इलाके से दोहरी चुनौती मिली। जहां इराक में आईएसआईएस और यमन में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच अपने लोगों की जान बचाने की गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा। सरकार ने तेजी के साथ इस चुनौती का सामना किया। आईएसआईएस के कब्जे से नर्सों को तो छुड़ा लिया, लेकिन अभी भी 39 भारतीयों का कोई अतापता नहीं है। हालांकि भारत सरकार अपने आठ सूत्रों का हवाला देकर दावा करती है कि वे अभी भी जीवित हैं और उन्हें सुरक्षित वापस लाने के प्रयास चल रहे हैं। सीरिया में आंतरिक उथल-पुथल के कारण भारत को वहां से अपने नागरिकों को निकालना पड़ा। इस चुनौती का इस्तेमाल भारत ने एक अवसर के रूप में किया और अमेरिका सहित कई अन्य देशों के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने में भारतीय वायु सेना ने अपनी भूमिका निभाई।

स्पष्ट है कि पश्चिम एशिया में भारत के समक्ष इस तरह की कई पेंचीदगियां अचानक पैदा हो जाती हैं और ऐसे समय में उसे आनन-फानन में बचाव के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है। वर्तमान सरकार से पहले भी विदेश नीति निर्धारक इस हकीकत को समझ तो रहे थे, लेकिन जितनी तेजी से इन देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूती देने का प्रयास होना चाहिए था, उसपर कभी अमेरिका, तो कभी पाकिस्तान और कभी देश के अंदर ही कुछ धड़ों की नाराजगी का साया दिखा। केंद्र सरकार ने उसी नीति को तेजी से आगे बढ़ाने की दिशा में पहल शुरू कर दी है। संप्रग सरकार के शासनकाल में ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए सहमति बनी थी, अब भारत सरकार इस दिशा में जमीनी स्तर पर काम करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। भारत ने पश्चिम एशिया के महत्व को रेखांकित करते हुए सऊदी अरब, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इराक, बहरीन, अल्जीरिया और इजराइल जैसे देशों के साथ संबंधों को रणनीतिक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास आरंभ किया है। मौजूदा सरकार के सत्ता में आते ही भारत के विदेश मंत्रालय ने अरब लीग के

ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए सहमति बनी थी, अब भारत सरकार इस दिशा में जमीनी स्तर पर काम करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। भारत ने पश्चिम एशिया के महत्व को रेखांकित करते हुए सऊदी अरब, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इराक, बहरीन, अल्जीरिया और इजराइल जैसे देशों के साथ संबंधों को रणनीतिक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास आरंभ किया है।

सिद्धांत से व्यवहार की ओर भारत-इजरायल संबंध

भारत और इजरायल के बीच संबंध अब धीरे-धीरे सिद्धांतों एवं घरेलू राजनीति के बंधन से मुक्त होकर यथार्थ के धरातल पर आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे रहे रणनीतिक संबंध अब घनिष्ठता के नये आयाम की ओर अग्रसर हैं। फिलिस्तीन के साथ भारत और विश्व के मुस्लिम समुदाय की संवेदनाओं की चिंताओं के समानांतर अब आगे बढ़े भारत-इजरायल संबंध को सरकार पर्दे के पीछे से ला रही है तो इसके पीछे एक सोची समझी और दूरदर्शी नीति काम कर रही है।

यासिर अराफात के समय भारत और फिलिस्तीन के संबंधों में जो गर्माहट थी अब वह कहीं नहीं दिखती है। अराफात का नाम और चेहरा भारत के लोगों के दिलोदिमाग में अभी भी बसा हुआ है, लेकिन अब स्थितियां बहुत बदली हुई हैं। इजरायल के साथ पश्चिम एशिया के कई मुस्लिम देशों के साथ संबंध मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में भारत भी अगर इजरायल के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कमजोर के साथ अपने हितों की बलि देकर खड़ा होकर एक मजबूत को दुश्मन बनाने से बेहतर है कि गलत बात का विरोध कर कमजोर को नैतिक समर्थन दिया जाए, जिससे कि उसे अपनी ताकत के बूते अधिकारों को हासिल करने का मौका मिले।

मौजूदा सरकार ने सता में आने के साथ ही इजरायल के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में तेजी से पहल शुरू कर दी है। भाजपा हमेशा से इजरायल के साथ मजबूत संबंधों का समर्थन करती रही है। स्वाभाविक है सत्ता में आने के बाद अब भारत-इजरायल संबंध अभूतपूर्व तेजी के साथ प्रगाढ़ता की दिशा में बढेंगे। प्रधानमंत्री ने इसकी झलक भी दिखा दी है। पिछले साल नवंबर में गृहमंत्री को रक्षा, प्रतिरक्षा और कृषि सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा के लिए इजरायल भेजा। इस दौर से एक सप्ताह पहले इजरायल के पूर्व राष्ट्रपति शिमोन पेरेज भारत आए थे। इसी महीने के आखिरी सप्ताह में प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ की आमसभा के दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेत्यानाहू से मुलाकात की।

इसी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने इजरायल के विदेशमंत्री अविग्डोर लिबरमैन से मुलाकात की और इसके एक हफ्ते बाद ही भारत ने लंबे समय से रुके 262 बराक-1 वायु प्रतिरक्षा मिसाइल सौदे को अपनी हरी झंडी दिखा दी। दोनों देश इस मिसाइल का साझा उत्पादन करेंगे और इसका परीक्षण भी हो चुका है। इसके साथ ही 8356 इजरायली स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों और 321 लांचरों की खरीद के बारे में भी सरकार गंभीरता से आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर ये दोनों सौदे 6620 करोड़ डॉलर के हैं। भारत और इजरायल अब साझा रक्षा उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

गृहमंत्री ने इजरायल दौर के वक्त नेत्यानाहू से मुलाकात के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया अभियान के बारे अवगत कराया और रक्षा उपकरणों के साझा उत्पादन पर चर्चा की। भारत को उम्मीद है कि आने वाले समय में इजरायल से भारत में भारी निवेश आ सकता है। प्रधानमंत्री और विदेशमंत्री इजरायल के दौर जल्द ही जाने वाले हैं। वह इजरायल का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। माना जा रहा है कि इसी दौरे में भारत इजरायल के साथ रक्षा सौदों को अंतिम रूप देगा।

फिलहाल रक्षा क्षेत्र को छोड़कर भारत-इजरायल द्विपक्षीय व्यापार 5 अरब डॉलर है। दोनों देशों की कंपनियां एक दूसरे के यहां निवेश को लगातार बढ़ा रही हैं। भारत और इजरायल मुक्त व्यापार समझौता करने के बारे में भी विचार कर रहे हैं। इसके अलावा परमाणु, कृषि, तकनीक, साईबर सुरक्षा, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में भारत और इजराइल के संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं।

देशों के मीडियाकर्मियों की एक कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला में भारत के पत्रकारों को भी बुलाया गया। काफी अच्छी बातें हुईं। विदेश मंत्री ने भारत और पश्चिम एशिया के बीच संबंधों का जिक्र करते हुए इस बात का विशेष उल्लेख किया कि किस तरह से वहां की आम जनता भारत को अपने दिल में रखती है। वहां के लोग अक्सर अलहिंद या अलहिंदी नाम अभी भी रखते हैं।

अरब देशों में लोकतंत्र की कमी और मीडिया के प्रचार प्रसार के निम्न स्तर के कारण भारत और पश्चिम एशिया के बीच एक तरह से दूरी बढ़ी हुई दिखती है। एक कारण यह भी दिखाई देता है कि वहां से विदेशी मुद्रा भेजने वाले लोग समाज के कमजोर और निम्न वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में सरकारी अमला भी इन्हें ज्यादा तरजीह नहीं देता है। इस कार्यशाला के बाद विदेश मंत्री ने कतर का दौरा भी किया। उनके कतर दौरे के समय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि हमने विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, प्रतिरक्षा, सुरक्षा और जनसंपर्क के माध्यमों का जायजा लिया है। इसका सीधा अर्थ यही लगाया जा रहा है कि भारत अब पश्चिम एशिया के साथ अपने संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर सुरक्षा में सहयोग और व्यापार के साथ-साथ जनसंपर्क को मजबूत करने के बारे में गंभीरता से पहल कर रहा है।

इस बीच मीडिया में ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि प्रधानमंत्री जल्द ही इजराइल का दौरा करेंगे। यह पहला मौका होगा जब भारत का प्रधानमंत्री इजराइल जाएगा। भारत और इजराइल के संबंधों में फिलिस्तीन की भूमिका अभी भी बनी हुई है। भारत इजराइल के करीब तो आना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि अगर फिलिस्तीन को छोड़ दिया गया तो बाकी अरब देश नाराज हो जाएंगे और पड़ोसी पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर राजनीतिक करने का मौका मिल जाएगा। भारत को इसी पेंच को सुलझाना है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच भारत की विदेश नीति धीरे-धीरे सिद्धांतों से हटकर यथार्थ की ओर जा रही है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यथार्थ की ओर हो रहे इस प्रस्थान के दौरान पाकिस्तान को खेल करने का कोई मौका मिलने न पाए। अरब देशों के साथ संबंधों को मजबूती देने के दौरान भारत को अमेरिका की छाया से भी बाहर निकलना होगा। ऐसा करके ही हम पश्चिम एशिया के साथ संबंधों को स्वर्णिम काल के इतिहास को दोबारा दोहरा सकते हैं। ❑

Mc Graw Hill

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2015

₹ 1350/-
ISBN: 9789339217945

₹ 1050/-
ISBN: 9789339217952

₹ 265/-
ISBN: 9789339220853

₹ 225/-
ISBN: 9789339219079

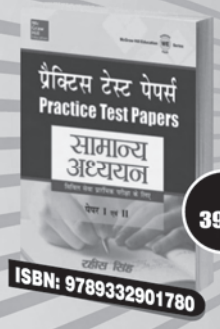

₹ 395/-
ISBN: 9789332901780

₹ 425/-
ISBN: 9789339217754

₹ 395/-
ISBN: 9789339205140

₹ 395/-
ISBN: 9789383286959

अन्य उपयोगी पुस्तकें

ISBN	Author	Title	Price
9789339204204	हुसैन एवं सिंह	भारत का भूगोल	510/-
9789351342663	लक्ष्मीकांत, एम	भारत की राजव्यवस्था	450/-
9789332901186	लक्ष्मीकांत, एम	1000 Plus Questions भारत की राजव्यवस्था	240/-
9781259003752	हुसैन, माजिद	1000 Plus Questions भारत एवं विश्व का भूगोल	285/-
9781259027192	सिंह एवं रस्तोगी	अंतर्वैयक्तिक सह-सम्प्रेशन कौशल सामान्य अध्ययन प्रश्न-II	370/-
9781259064166	सिंह शीलवन्त	सामान्य अध्ययन एनसीईआरटी विषयवार सार संग्रह	315/-
9781259063992	शीलवंत सिंह	सामान्य विज्ञान	390/-

शीघ्र प्रकाशित

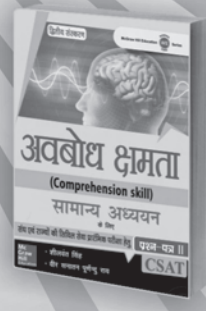

Mc Graw Hill Education

मैक्ग्रॉ हिल एजुकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

बी-४, सैक्टर-६३, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201 301

उत्तर भारतः दिल्ली/हरियाणा/पंजाब/चंडीगढ़/जम्मू-कश्मीर/हिमाचल प्रदेश/राजस्थान/मध्य प्रदेशः *आशीष पराशर* (ashish.prashar@mheducation.com); **दिल्ली/राजस्थानः** *दिलीप चौरसिया* (09560072125); *आनन्द सिंह* (09599196777) **हरियाणा/पंजाब/चंडीगढ़/जम्मू-कश्मीर/हिमाचल प्रदेश/दिल्ली/एन॰सी॰आरः** *जनेन्द्र अत्री* (09599295604); **मध्य प्रदेशः** *रोहित शैल* (07042799341); **उत्तरप्रदेश/उत्तराखंडः** *जगदीश ध्यानी* (07042799338); *जितेन्द्र मिश्रा* (07042799339)

पूर्वी भारतः बिहार/झारखंड/उड़ीसाः रणविजय कुमार (07042799348); नितेश कुमार निशु (09560779393)

पश्चिम भारतः महाराष्ट/गोवा/गुजरात/छत्तीसगढ़: *जूनियस रॉड्रिक्स* (09833054319)
नागपुर/छत्तीसगढ़: *सौरभ कानूनगो* (07718812361); **गुजरातः** *नरेश महतो* (07718812363)

विक्रय एवं प्रकाशन हेतु जानकारी हेतु लिखें *reachus@mheducation.com*

Prices are subject to change without prior notice.

Join us on UPSC http://on.fb.me/1yDCZBW

Join us on Civil Services Main http://on.fb.me/1OzG28E

Helpline No.: 1800 103 5875

To buy these products, visit www.mheducation.co.in

YH-82/2015

सुशासनः सिद्धांत व व्यवहार

ए सूर्य प्रकाश

जब आप हर क्षेत्र में हुए बदलाव का परीक्षण करेंगे तो आपको सरकार चलाने की शैली में एक प्रत्यक्ष बदलाव नजर आएगा। एक साल के भीतर गरीबों को फायदा पहुंचाने वाली, किसानों की हितैषी, निवेश को बढ़ावा देने वाली और रोजगार बढ़ाने वाली नई योजनाएं पेश की गईं जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक सुखद आश्चर्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश को एक ऐसा नेता मिला, जिसने फिर से उम्मीद जगाई और युवाओं को प्रोत्साहित किया ताकि वे भारत को बदलने वाले मुहिम से जुडें

भारत की राष्ट्रीय राजनीति में 1989 के दौरान जब गठबंधन युग का उदय हुआ उस समय लोगों में यह धारणा बैठ चुकी थी कि हम अपना राष्ट्रीय उद्देश्य खो चुके हैं और हमारा कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है। लोगों के राष्ट्रीय-सामाजिक जीवन के हर पहलू पर इसका असर नजर आने लगा था और प्रशासन के तौर तरीकों पर भी इसकी छाया साफ दिखने लगी थी, चाहे मुद्दा सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हो या फिर आर्थिक। इस राजनीतिक अनिश्चितता ने अक्षमता और फैसलों में पारदर्शिता के अभाव का रास्ता तैयार किया लेकिन अक्षमता और उलझन के इस माहौल का सबसे ज्यादा असर दुनिया के साथ भारत के व्यवहार में नजर आ रहा था। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ढुलमुल बयानों और लचर प्रतिक्रियाओं से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लगने लगा था कि भारत में नेतृत्व का अभाव है।

यह सब नाटकीय ढंग से मई 2014 में उस वक्त बदल गया जब लोगों ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को जनादेश दिया और स्पष्ट बहुमत के साथ लोकसभा पहुंचाया। ज्यादातर लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री को पिछले 12 महीनों में काम करते हुए देखा है, वे इस बात से सहमत होंगे कि वह पक्के इरादे वाले काम के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध इंसान हैं। उन्होंने न सिर्फ आगे बढ़कर देश का नेतृत्व संभाला, बल्कि उन लाखों लोगों को भी प्रोत्साहित किया जो आधुनिक भारत के निर्माण में हिस्सेदार बनना चाहते हैं।

इस बात पर बहस हो सकती है कि चुनावी वादों और वास्तविक क्रियान्वयन के बीच का अंतर एक हकीकत है या फिर पिछले साल लोकसभा चुनावों के दौरान राजग ने जनता के मन में उम्मीदों का जो पहाड़ खड़ा कर दिया था, यह दरअसल उसे काबू कर पाने की नाकामी है लेकिन कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि निराशा की भावना अब पुरानी बात हो गई है और नई सरकार अपने वादों को एक एक करके पूरा कर रही है। वह भी शानदार रफ्तार और प्रभावशाली नतीजों के साथ।

सरकार की सफलता और विफलता को जानने के लिए हमें सरकार के कामकाज के अलग-अलग हिस्सों पर नजर डालनी होगी और फिर पूरे मामले का जायजा लेना होगा। सरकार का पहला साल हलचलों से भरा रहा, जिस दौरान दरअसल सरकार ने प्रशासन का दायरा बढ़ाकर कुछ उन क्षेत्रों को भी इसमें समाहित किया, जो अब तक इससे अछूते थे। कई राष्ट्रीय योजनाएं शुरू की गईं ताकि लैंगिक समानता, स्वच्छता और सफाई, बैंकिंग सेवाओं के विस्तार जैसी पुरानी चुनौतियों से निपटा जा सके। बिजली उत्पादन, रेलवे, राजमार्ग निर्माण आदि बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े कामों पर ज्यादा ध्यान दिया गया। विदेश मामलों के मोर्चे पर व्यापक पैमाने पर संचार साधनों का इस्तेमाल हुआ। संकट के समय और आपदा प्रबंधन के मामले में इस सरकार का जैसा रुख रहा, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। ऐसे तमाम अवसरों पर केंद्रीय मंत्रियों ने सीधे अपनी निगरानी में पूरा अभियान चलवाया।

लेखक प्रसार भारती के चेयरमैन हैं। उन्हें मीडिया में लगभग चार दशक का अनुभव है। संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन और शासन संबंधी विषय में उन्हें विशेषज्ञता प्राप्त है। वह नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक इंडिया फाऊंडेशन के निदेशक भी हैं तथा विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के विशिष्ट विद्वान हैं। ईमेलः chairman@prasarbharati.gov.in

जब आप हर क्षेत्र में हुए बदलाव का परीक्षण करेंगे तो आपको सरकार चलाने की शैली में एक प्रत्यक्ष बदलाव नजर आएगा। एक साल के भीतर गरीबों को फायदा पहुंचाने वाली, किसानों की हितैषी, निवेश को बढ़ावा देने वाली और रोजगार बढ़ाने वाली नई योजनाएं पेश की गईं जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक सुखद आश्चर्य है।

विदेश नीति पर फोकस

प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण समारोह के दिन से ही विदेशी संबंधों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अपने शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री ने दक्षेस देशों के सभी नेताओं को आमंत्रित किया। उसके बाद से वह लगातार आधिकारिक विदेश दौरे पर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, रूस के राष्ट्रपति ब्लादमिर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसिस्को ऑलांदे, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे और कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर जैसे विश्व स्तरीय नेताओं से मुलाकात की।

आपदा प्रबंधन और मानवीय मसलों पर मौजूदा सरकार ने जो रुख अपनाया है, वह भी ध्यान देने लायक है। इसकी शुरुआत इराक से नर्सों को सुरक्षित निकालने से हुई। उसके बाद जब यमन के भारतीय दूतावास पर संकट गहराया, तब भारतीय वायु सेना और नौसेना ने कठिन परिस्थितियों में हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी थे।

अपने पहले विदेश दौरे के लिए भूटान का चयन कर प्रधानमंत्री ने साफ संकेत दिए कि वे अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए तत्पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री दो बार नेपाल दौरे पर गए। एक वर्ष के छोटे समय अंतराल में प्रधानमंत्री ने 19 देशों का दौरा किया है। दुनियाभर के नेताओं के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने के अलावा प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर और फ्रांस, जर्मनी और कनाडा में हजारों लोगों को अपनी जनसभाओं में आकर्षित किया। इन देशों में इससे पहले कभी किसी भारतीय प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान भारतीय प्रवासियों की ऐसी स्वभाविक और उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं देखी गई।

शासन का नया अंदाज

आपदा प्रबंधन और मानवीय मसलों पर मौजूदा सरकार ने जो रुख अपनाया है, वह भी ध्यान देने लायक है। इसकी शुरुआत इराक से नर्सों को सुरक्षित निकालने से हुई। उसके बाद जब यमन के भारतीय दूतावास पर संकट गहराया, तब भारतीय वायु सेना और नौसेना ने कठिन परिस्थितियों में हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी थे। अपनी नई शैली के तहत प्रधानमंत्री ने विदेश राज्यमंत्री जनरल वी के सिंह को जिबूती भेजा ताकि सभी भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा सके। संघर्षरत क्षेत्र से लोगों को सकुशल बाहर निकालने में भारतीय भूमिका की दुनिया भर के देशों से सराहना की क्योंकि इनमें सिर्फ भारतीय ही नहीं थे। भारतीय सेना ने 5600 लोगों को निकाला था, जिनमें भारतीयों के अलावा 41 देशों के 960 नागरिक भी थे।

प्रधानमंत्री ने आम लोगों से सीधे संवाद स्थापित करने के लिए लीक से हटकर तरीका अपनाया और रेडियो पर टॉक शो 'मन की बात' शुरू की। हर महीने होने वाले इस कार्यक्रम के जरिए आकाशवाणी ने श्रोताओं को दोबारा अपनी तरफ खींचा और यह कार्यक्रम टेलीविजन पर भी काफी लोकप्रिय हुआ है। दर्जनों खबरिया चैनलों ने इसे लाइव दिखाया है।

नए शासन मॉडल का एक बेहतरीन उदाहरण विदेश मंत्री ने पेश किया। विदेश जाने वाले भारतीयों की वर्षों से शिकायत थी कि भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय का रवैया उनके प्रति असंवेदनशील रहता है लेकिन अब यह बीते वक्त की बात हो चुकी है। आज स्थिति यह है कि भारत की विदेश मंत्री सुबह के दो बजे तक दुनिया भर से आए परेशान भारतीयों के ट्वीट का जवाब देती हैं। वह नजदीक के दूतावास को अलर्ट भेजती हैं और हर मामले की निगरानी खुद करती हैं जब तक मदद मिलना पक्का नहीं हो जाता। मदद की गुहार लगाने वाले ये लोग भारतीय कामगारों के समूह हो सकते हैं जो संकटग्रस्त इलाकों से निकलना चाहते हैं या फिर घरेलू हिंसा की शिकार कोई महिला हो सकती है या फिर कोई भारतीय नागरिक, जिसका पासपोर्ट खो चुका हो। इन लोगों को मदद के लिए बस विदेश मंत्री को एक ट्वीट करना होता है और पूरी मशीनरी हरकत में आ जाती है और तुरंत मदद पहुंचती है। भारत में कभी न तो ऐसी विदेश मंत्री थीं और न ऐसा विदेश मंत्रालय। उनके कामकाज का तरीका दूसरे देशों के विदेश मंत्रियों के लिए बेहतरीन उदाहरण बन सकता है।

अर्थव्यवस्था को सही प्रोत्साहन

सरकार की चिंता का एक महत्वपूर्ण विषय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति थी। अनेकानेक घोटालों और प्रशासनिक तंत्र के धराशायी होने के कारण भारत पर विदेशी निवेशकों का भरोसा खत्म होने लगा था। किसी सरकार की कामयाबी और नाकामी इस बात पर निर्भर करती है कि वह देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर को कितना तेज कर पाती है। इस लिहाज से प्रधानमंत्री को दुनिया भर के कारोबारी और औद्योगिक नेताओं से मिलने और उन्हें यह भरोसा दिलाने की फिक्र थी कि भारत निवेश के लिए बिल्कुल सही और सुरक्षित है। परिणामस्वरूप अपने पहले बजट में वित्त मंत्री ने काफी योजनाएं बनाईं। इसका फायदा भी हुआ और बजट को कारोबारी और उद्योग जगत ने पूरे मन से स्वीकार किया। इसमें निवेश को आकर्षित करने का मजबूत संदेश था। अर्थव्यवस्था में सुधार साफ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ मंत्रालय ने उन उलझनों को सुलझाना शुरू किया जिनसे निवेशकों को भय था। सरकार अड़चनों को दूर करके देश में कारोबार शुरू करने की सहूलियतें बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री ने एक रोड मैप भी तैयार कर लिया है, जिससे अगले तीन साल में राजकोषीय घाटे को कम करके जीडीपी के 3 फीसदी तक लाने की योजना है।

धीरे-धीरे निवेश के माहौल में सुधार हुआ और मौजूदा अनुमानों के तहत भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़कर सालाना 9 फीसदी तक पहुंच सकती है। जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में भारत निकट भविष्य में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। साथ ही देश का विदेशी मुद्रा भंडार 350 अरब डॉलर तक पहुंच गया है।

इन सब उपायों से धीरे-धीरे निवेश के माहौल में सुधार हुआ और मौजूदा अनुमानों के तहत भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़कर सालाना 9 फीसदी तक पहुंच सकती है। जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में भारत निकट भविष्य में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। साथ ही देश का विदेशी मुद्रा भंडार 350 अरब डॉलर तक पहुंच गया है।

जितनी अहम अर्थव्यवस्था है, उतना ही अहम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाना है। पिछले कुछ वर्षों में हम घोटालों में डूबे थे, लिहाजा भ्रष्टाचार मुक्त सरकार एक बड़ी कामयाबी है। पुरानी सरकार ने इन घोटालों की बड़ी कीमत चुकाई है। मौजूदा सरकार ने स्पेक्ट्रम और कोयला खदानों के आवंटन में पारदर्शी तरीका अपनाकर नए मानक तय किए हैं। परिणामस्वरूप नीलामी में कोई बाधा नहीं आई और सरकारी खजाने को काफी आमदनी हुई।

प्रशासनिक ढांचे को ठीक करने से संबंधित सरकार का एक अहम फैसला योजना

14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32 फीसदी से 42 फीसदी करने का क्रांतिकारी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने तत्परता से ये सुझाव मान लेने का ऐलान किया, जिससे राज्यों को 2015-16 में केंद्र से अतिरिक्त 1.78 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे।

आयोग को खत्म करना था। वैचारिक तौर पर मरणासन्न हालत में पहुंच चुकी यह संस्था भारत की ग्रोथ को नए आयाम दे पाने में बुरी तरह नाकाम साबित हुई थी। यह समाजवादी युग का अवशेष मात्र था जो आज भी काम कर रहा था।

यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री ने इस आयोग को खत्म करने और इसकी जगह नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग को लाने का फैसला किया तो किसी को दुख नहीं हुआ। नीति आयोग एक पॉलिसी थिंक टैंक है जो आधुनिक भारत की जरूरतों से पूरी तरह मेल खाता है। सरकार को सामाजिक और आर्थिक मामलों में सुझाव देने के अलावा यह आर्थिक नीति निर्माण में भी शामिल होगा। नीति आयोग के बदलाव उसके नाम से कहीं ज्यादा हैं। सरकार ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया और दूसरे सदस्यों को नियुक्त किया, जो आयोग को वैचारिक गहराई देंगे। इन सब के अलावा वास्तविक संघीय व्यवस्था का उदाहरण पेश करते हुए राज्य सरकारों और केंद्र के बीच संबंध सुधारने की सही मायने में कोशिश की गई।

14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32 फीसदी से 42 फीसदी करने का क्रांतिकारी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने तत्परता से ये सुझाव मान लेने का ऐलान किया, जिससे राज्यों को 2015-16 में केंद्र से अतिरिक्त 1.78 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 42 फीसदी करना अभी तक का सबसे बड़ा बदलाव है। इन सुझावों को स्वीकार करने से यह साफ है कि सरकार सहकारी संघीय ढांचे को लेकर प्रतिबद्ध है।

मजबूत बुनियादी ढांचे की जरूरत

आने वाले सालों में भारत की ग्रोथ की जो रूपरेखा तय की गई है, उसे तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक बुनियादी ढांचे का सहयोग न मिले। विदेशी निवेशकों में यह चिंता का अहम विषय है और प्रधानमंत्री दुनिया भर के कारोबारी नेताओं और उद्योग जगत को यह भरोसा दिला रहे हैं कि अवसंरचना का विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। यही वजह है प्रधानमंत्री कार्यालय ने अवसंरचना परियोजनाओं पर करीबी नजर बना रखी है और कोयला, पावर, हाइवे, रेलवे और पोर्ट सहित विभिन्न मंत्रालयों के लिए कड़े लक्ष्य तय किए गए हैं।

पीएमओ ने ठीक इसी तरह के लक्ष्य बिजली कंपनियों के लिए भी तय किए थे, जिसके कारण देश में बिजली की कमी 10 फीसदी से घटकर 3.6 फीसदी रह गई है। सरकार कई राज्यों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहती है और इसकी शुरुआत दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान और आंध्रप्रदेश से हो रही है। बिजली मंत्रालय यह भी चाहता है उसका मंत्रालय बिजली उत्पादन में 12वीं योजना के लक्ष्य से आगे निकल जाए। ठीक इसी तरह का जोर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण पर है जो यूपीए शासन काल के दौरान सुस्त पड़ गया था। सभी मंत्रालयों और मंत्रियों को तय समय में लक्ष्य हासिल करना है। कोई भी मंत्री काम में कोताही नहीं कर सकता।

स्वच्छ भारत

देश में स्वच्छ भारत और सैनिटेशन प्रोग्राम जैसी मुहिम चलाई गई। स्वच्छ भारत मुहिम महात्मा गांधी की जन्मतिथि पर शुरू की गई। प्रधानमंत्री ने कई तुच्छ माने जाने वाले मुद्दों को सार्वजनिक तौर पर उठाने की हिम्मत दिखाई। जैसे, देश के 70 फीसदी घरों में शौचालय नहीं होने का महिलाओं की प्रतिष्ठा पर असर। हर घर में शौचालय बनाने की मुहिम जोरशोर से चलाई जा रही है और घरों में शौचालय बनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है। सरकार का लक्ष्य 6 करोड़ शौचालय बनाना है।

प्रधानमंत्री की एक और योजना, जिसे बहुत कामयबी मिली है, वह है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस कार्यक्रम का मकसद गरीबों का बैंक में खाता खुलवाकर उन्हें वित्तीय सेवाओं से जोड़ना और उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत

प्रधानमंत्री की एक और योजना, जिसे बहुत कामयबी मिली है, वह है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस कार्यक्रम का मकसद गरीबों का बैंक में खाता खुलवाकर उन्हें वित्तीय सेवाओं से जोड़ना और उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत बनाना है। इस कार्यक्रम के जरिए गरीबों को भी बैंकिंग सेवाओं के दायरे में आने का मौका मिला।

बनाना है। इस कार्यक्रम के जरिए गरीबों को भी बैंकिंग सेवाओं के दायरे में आने का मौका मिला। इस कार्यक्रम को अपार सफलता मिली और स्कीम लॉन्च होने के एक महीने के भीतर 1.50 करोड़ खाते खोले गए। ध्यान देने वाली बात है कि इन खातों में देश के गरीब 15.800 करोड़ रुपये रखते हैं। जन धन योजना के तहत खोले गए सभी खातों पर एक लाख रुपये का दुर्घटना कवर और छह महीने तक खातों के संतोषजनक संचालन के बाद 5000 रुपये की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी है।

जन धन की कामयाबी के बाद सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को एक नए स्तर पर पहुंचाते हुए तीन और योजनाएं शुरू कीं। ये योजनाएं हैं- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत

12 रुपये सालाना के प्रीमियम पर दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलता है। जीवन ज्योति योजना के तहत सालाना 330 रुपये प्रीमियम देने पर जीवन बीमा की सुविधा मिलेगी। वहीं, अटल पेंशन योजना कम प्रीमियम वाली स्कीम है, जिसमें बुजुर्गों को 1000 से 5000 रुपये का मासिक पेंशन मिलेगा। यह पेंशन नौकरी के दौरान जमा की गई रकम के आधार पर तय होगी। युवाओं में काम करने की क्षमता बढ़ाने और रोजगार मुहैया कराने के लिए स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया की मुहिम शुरू की गई है। प्रधानमंत्री ने सरकारी अमले में कमी कर बेहतर प्रशासन देने (लेस गवर्नमेंट, मोर गवर्नेंस) का नारा दिया है, जिसका मतलब सरकारी कामकाज को आसान बनाना, योजनाओं को लागू करने में पारदर्शिता लाना और अफसरों को जिम्मेदार बनाना है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव

कुछ महीने पहले हमें मंत्रिमंडल में अहम बदलाव देखने को मिले, जब प्रधानमंत्री ने सुरेश प्रभु को रेल मंत्री और मनोहर परिकर को रक्षा मंत्री के तौर पर अपने कैबिनेट में शामिल किया। अपने पहले रेल बजट में प्रभु ने साफ कर दिया कि रेल की वित्तीय स्थिति को लेकर उनके पास व्यापक नजरिया है और वह सिर्फ सांसदों की वाहवाही लूटने की कोशिश नहीं करने वाले हैं। इस मोर्चे पर प्रभु का दूरदर्शी नजरिया देखने को मिला।

निष्कर्ष

इतनी बातों के बाद कुछ व्यापक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से केंद्र सरकार को चलाया है, उससे उन्होंने अपने समर्थकों और आलोचकों, दोनों को चौंकाया है। उनके आलोचकों की उलझन यह है कि प्रधानमंत्री ने पिछली सरकार की सभी योजनाओं को बगैर सोचे-समझे खत्म नहीं किया। यह गवर्नेंस के सधे हुए और जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है।

यह टी-20 क्रिकेट मैच नहीं है। एक प्रधानमंत्री, जो प्रचंड बहुमत के साथ संसद में आता है, वह एक ऐसी टीम का कप्तान होता है जिसे पांच दिवसीय टेस्ट मैच खेलना है। पहला साल पहले दिन के खेल की तरह होता है जब चौथे या पांचवें दिन के मैच के लिए मैदान तैयार होता है।

हालांकि आलोचकों के लिए इतना काफी नहीं है। उनका मानना है कि पहले साल के अंत में सरकार का बहीखाता कमजोर रहा। उन्हें यह याद रखना होगा कि यह टी-20 क्रिकेट मैच नहीं है। एक प्रधानमंत्री, जो प्रचंड बहुमत के साथ संसद में आता है, वह एक ऐसी टीम का कप्तान होता है जिसे पांच दिवसीय टेस्ट मैच खेलना है। पहला साल पहले दिन के खेल की तरह होता है जब चौथे या पांचवें दिन के मैच के लिए मैदान तैयार होता है। ठीक इसी तरह चुनाव प्रचार के दौरान किए वादों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री के पास पांच साल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश को एक ऐसा नेता मिला, जिसने फिर से उम्मीद जगाई और युवाओं को प्रोत्साहित किया ताकि वे भारत को बदलने वाले मुहिम से जुड़ें। एक साल के बाद ही जब आपके बहीखाते में ऐसी बड़ी चीजें हों, तो छोटे कर्जों से खास फर्क नहीं पड़ता। ❑

YH-76/2015

महिला एवं बाल विकासः प्रगति की आस

पवन रेखा कुमारी

देश और समाज के विकास के लिए हमें सबके साथ की जरुरत होती है। खासकर, इस प्रगति में आधी आबादी की कदमताल ना रहे तो प्रगति की चमक अधूरी रह जाती है। सुखद है कि देश की प्रगति की उड़ान में आज आधी आबादी की उपस्थिति भी समान रूप से रखने की कोशिश हो रही है। इसी क्रम में महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में भारत सरकार ने इस साल कई जरूरी कदम उठाते हुए, *स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय का निर्माण* व *बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, बाल स्वच्छता अभियान* व *मिशन इंनद्रधनुष* जैसी योजनाएं शुरु की। सरकार के इन ठोस कदमों का परिणाम है कि हरियाणा में ग्राम-पंचायतों ने *सेल्फी विद डॉटर* जैसी प्रतियोगिताओं की शुरुआत कर दी है

राज्य की बुनियाद जिन चार तत्वों पर टिकी होती है, उनमें जनसंख्या एक अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण तत्व है। जनसंख्या का भी अगर वर्गीकरण किया जाए तो कई अलग-अलग वर्ग तैयार होते हैं। वर्तमान भारतीय समाज के संदर्भ में अगर जनसंख्या का वर्गीकरण करें तो पुरुष, महिला एवं बच्चे तीन बहुसंख्यक वर्ग नज़र आते हैं। इन तीन वर्गों में महिला एवं बाल विकास को सरकार अलग करके विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए स्वतंत्रता के बाद से ही प्रयासरत रही है। इसमें कोई शक नही है कि बच्चों में देश का भविष्य है तो वहीं महिलाएं समाज के आधे प्रतिनिधित्व का पूरा प्रतिबिम्ब हैं। इन दोनों का विकास किए बिना राज्य के विकास की किसी भी परिकल्पना को साकार रूप नहीं दिया जा सकता है।

आज जब देश में पूर्ण बहुमत की एक सरकार है, तो इस बात का मूल्यांकन अनिवार्य हो जाता है कि बाल विकास एवं महिला उत्थान के क्षेत्र में सरकार की नीतियां कितनी कारगर एवं लाभकारी हैं। पिछली सरकारों द्वारा भी महिला एवं बाल विकास को लेकर नीतिगत स्तर पर काम होता रहा है एवं वर्तमान सरकार भी अपनी नीतियों के साथ इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है। अगर देखा जाए तो महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में भारत सरकार ने गत एक वर्ष में कई कारगर कदम उठाए हैं। स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय का निर्माण, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरुआत, 'सुकन्या समृद्धि योजना', 'बाल स्वच्छता अभियान', गुमशुदा बच्चों के लिए 'खोया-पाया' वेबसाइट, टीकाकरण के लिए 'मिशन इंद्रधनुष' जैसी कुछ योजनाएं सरकार ने शुरू की हैं। साथ ही सरकार ने जन्म से पूर्व लिंग की जांच तकनीकों की निगरानी, अस्पताल में प्रसव की बढ़ोत्तरी के आवश्यक उपाय, जन्मे बच्चे का पंजीकरण पर जोर देकर और निगरानी समितियों का गठन करके महिला और बाल विकास के लिए कारगर कदम उठाए हैं।

वर्तमान सरकार के गठन के दो महीने बाद से ही प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 'कन्या भ्रूण हत्या' और 'महिलाओं की सुरक्षा' का मामला उठाया था। प्रधानमंत्री ने तब कहा था कि 'लोगों को बेटियों से नहीं बल्कि अपने बेटों से भी घर से बाहर निकलने पर पूछना चाहिए कि वे कहां जा रहे हैं क्योंकि किसी महिला के साथ दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति किसी का बेटा होता है। आप अपने बेटों पर वैसे ही बंधन क्यों नहीं लगाते।' प्रधानमंत्री ने यहां पर समाज में बेटे और बेटी के बीच बढ़ते भेदभाव, लड़कियों की सुरक्षा एवं स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताई थी। लोग बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार देते हैं। 'कन्या भ्रूण हत्या' पर कानून होने के बावजूद कई राज्यों में लड़कियों की संख्या घटती जा रही है।

आकड़ों के मुताबिक 0-6 साल की उम्र के बीच प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या (जन्म के समय) (सीएसआर) में वर्ष 1961 से लगातार गिरावट आ रही है। वर्ष 1991 में लड़कियों की संख्या जहां 945 थी वही 2001 में यह संख्या घटकर 927 और 2011 में 918 हो गई। एक तरफ लड़कियों के प्रति बढ़ता भेदभाव और दूसरी

लेखिका एबीपी न्यूज के साथ बतौर वेब पत्रकार कार्यरत हैं। पूर्व में जनसत्ता, द संडे इंडियन आदि में कार्य-अनुभव। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रुजएट। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं एवं ब्लॉग के लिए लेखन। ईमेलः rekhatripathi.221@gmail.com

तरफ उपकरणों की उपलब्धता और उसके दुरुपयोग का यह नतीजा आज हमारे सामने है। यह आंकड़ा और न बढ़े इसलिए सरकार ने लड़कियों के अस्तित्व को बचाने, उनके संरक्षण और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान की घोषणा की। टेलीविजन, अखबार वेबसाइट से लेकर हर जगह सरकार इसका प्रचार-प्रसार कर रही है। इस अभियान के माध्यम से सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 100 जिलों का चयन किया गया है जहां बाल लिंग अनुपात सबसे कम है और फिर वहां विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर कार्य किया जाएगा। इसमें हरियाणा के भी 12 जिले शामिल हैं जहां से प्रधानमंत्री ने इसी साल जनवरी में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना की शुरुआत की। लिंग अनुपात में सबसे ज्यादा अंतर हरियाणा में हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक हरियाणा में 1000 लड़कों पर 879 लड़किया हैं। 2001 में यह 1000 लड़कों पर 861 लड़कियों की संख्या थी। हरियाणा के महेंद्र गढ़ जिले में तो यह संख्या घटकर 745 रह गई है। सरकार के इस कदम के बाद अब हरियाणा के लोग इस योजना को सफल बनाने के लिए खुद आगे आ रहे हैं। यहां पर ग्राम पंचायत ने 'सेल्फी विद डॉटर' (बेटी के साथ सेल्फी खींचो और इनाम पाओ) की शुरुआत की है जिसमें स्थानीय लोग बढ़ चढकर हिस्सा ले रहे हैं। (https://mygov.in)

अभियान के माध्यम से सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 100 जिलों का चयन किया गया है जहां बाल लिंग अनुपात सबसे कम है और फिर वहां विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर कार्य किया जाएगा। इसमें हरियाणा के भी 12 जिले शामिल हैं जहां से प्रधानमंत्री ने इसी साल जनवरी में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना की शुरुआत की।

'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' अभियान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम, बालिकाओं के अस्तित्व को बचाना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने वाले गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसी और पीएनडीटी) कानून का सख्ती से अमल हो। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संबंधी अधिनियम, 2012 (पॉक्सोस) को लागू करके लड़कियों को सुरक्षित माहौल देना भी इस अभियान का मकसद है। इस अभियान में मुख्य रूप से लड़कियों के जन्म के लिए बेहतर माहौल देने पर जोर है। इसके अलावा मां और शिशु को बेहतर माहौल देना, गर्भवती महिलाओं के प्रसव और लड़कियों के महत्व को समझाने के प्रति जागरूकता लाना इस दिशा में एक कदम है। इसमें गर्भावस्था के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों/स्वास्थ्य केंद्रों में पंजीकरण कराने को भी बढ़ावा दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत स्कूलों में लड़कियों का दाखिला सुनिश्चित करने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों को सक्रिय बनाने के बारे में भी कहा गया है।

ऊपर दिए गए आंकड़े की हकीकत को देखकर समाज में लड़कियों की स्थिति का आकलन किया जा सकता है। हमारे समाज में जन्म से ही लड़कियों को बोझ समझा जाता है। पैदा होने के साथ माता-पिता को यह चिंता सताने लगती है कि उसकी पढ़ाई-लिखाई और शादी कैसे होगी? शादी के लिए दहेज कहां से देंगे? हालांकि दहेज लेना और देना कानूनन जुर्म है लेकिन यह कानून कितना कारगर हुआ यहा ऊपर के आंकडे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इसके उलट अगर बेटियां, लड़कियां जागरूक हों, शिक्षित हों और उनके पास रोजगार हो तो शायद समाज में हो रहे भेदभाव को कम किया जा सकता है। अगर ऐसा हो तो 'कन्या भ्रूण हत्या' पर लगाम लगाई जा सकती है।

बेटी और उसकी पढ़ाई लिखाई, शादी बोझ ना लगे इसके लिए सरकार ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' अभियान के साथ ही 'सुकन्या समृद्धि योजना' की शुरुआत भी की। यह योजना बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी पर आने वाले खर्च को आसानी से पूरा करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत बेटी पैदा होने के साथ या फिर दस साल की उम्र तक 'सुकन्या समृद्धि खाता' किसी भी डाकघर अथवा अधिकृत बैंक शाखा में खुलवाया जा सकता है। खाता खुलवाने के समय कम से कम 1000 रुपये और एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा करवाने होते हैं। यह पैसा खाता खुलने के 14 साल तक ही जमा करवाना पड़ेगा। मगर, खाता बेटी के 21 साल की होने पर ही मैच्योर होगा। बेटी के 18 साल के होने पर आधा पैसा निकलवा सकते हैं। बेटी के 21 साल के बाद खाता बंद हो जाएगा।

बेटी की उम्र 18 वर्ष होने पर आप जमा राशि का 50 प्रतिशत बेटी की शिक्षा अथवा शादी के लिए निकलवा सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अभिभावक बेटी की शादी 18 साल से पहले ना करें। खाते में जमा संपूर्ण राशि और ब्याज की रकम को खाते के 21 साल होने पर निकाली जा सकती है। अगर बेटी की 18 से 21 साल के बीच शादी हो जाती है तो अकांउट उसी वक्त बंद हो जाएगा। उदाहरण के लिए अगर 2015 में कोई व्यक्ति 1,000 रुपये महीने से अकाउंट खोलता है तो उसे 14 साल तक यानी 2028 तक हर साल 12 हज़ार रुपये (कम से कम) डालने होंगे। मौजूदा हिसाब से उसे हर साल 9.1 फीसदी ब्याज मिलता रहेगा तो जब बेटी 21 साल की होगी तो उसे 6,07,128 रुपये (6 लाख सात हजार एक सौ अठाइस रुपये) मिलेंगे। जबकि उस व्यक्ति ने 14 वर्षों में अकाउंट में कुल 1.68 लाख रुपये ही जमा करने पड़े। बाकी जो मिले कुल 4,39,128 रुपये ब्याज के हैं। (http://www.indiapost.gov.in/SukanyaSamriddhi.aspx)

बेटी और उसकी पढ़ाई लिखाई, शादी बोझ ना लगे इसके लिए सरकार ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' अभियान के साथ ही 'सुकन्या समृद्धि योजना' की शुरुआत भी की। यह योजना बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी पर आने वाले खर्च को आसानी से पूरा करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने और दुनिया से कदम से कदम मिलाकर चल सकें इसके लिए कई योजनाएं शुरू कर चुकी है। केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत सभी केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बल में कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर रैंक तक महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण को हरी झंडी देकर

कहीं न कहीं तंत्र में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने का एक सकारात्मक प्रयास किया है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर पुलिस बल में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का सुझाव दिया है। सरकार ने राज्यों से यह भी कहा है कि यदि राज्य सरकार पुलिस बल में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देती है तो इसके लिए केंद्र सरकार इंसेटिव के रूप में कुछ पैसा भी देगी। आपको बता दें कि अभी ओड़िशा, राजस्थान, सिक्किम और महाराष्ट्र में पुलिस बल में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण है। बिहार के मुख्यमंत्री ने भी हाल ही में 35 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है।

देशभर में महिला पुलिस और महिला थाने की मांग 2012 में हुए निर्भया कांड के बाद उठी। जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में रेप की शिकायत की जांच महिला पुलिस कर्मी से कराने की सिफारिश की थी। गृह मंत्रालय ने इसके मुताबिक सीआरपीसी और आइपीसी में ज़रूरी संशोधन भी किया था लेकिन महिला पुलिस कर्मियों की कमी की वजह से इसे पूरी तरह लागू करना संभव नहीं हो पा रहा था।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने महिलाओं की मौजूदा फोन हेल्पलाइन के साथ 'हिम्मत' एपलिकेशन भी शुरू कर दी है। इस एपलिकेशन में एक पावर बटन है जिसे फिक्स टाइमिंग तक दबाए रखने के बाद इलाके की पुलिस फौरन सक्रिय हो जाएगी। इसके जरिए शिकायतकर्ता और पुलिस कंट्रोल रूम चंद सेकेंड में एक-दूसरे से जुड़ जाएंगे।

अगर महिला पुलिसकर्मियों की संख्या पर गौर करे तो हैरानी भरे आंकड़े देखने को मिलेंगे। गृह मंत्रालय के मुताबिक देश के पुलिस बल में महिलाओं की वर्तमान हिस्सेदारी सिर्फ 5.33 फीसदी हैं। देश में 15,85,117 पुलिस कर्मी हैं जिनमें से केवल 84,479 के करीब महिलाएं हैं। इसके अलावा देश में कुल 15000 थाने हैं जिनमें से सिर्फ 499 महिला थाने हैं। राज्यों में उत्तर प्रदेश में 173341 पुलिस कर्मियों में मात्र 2586 महिलाएं हैं। असम में इनकी संख्या सिर्फ 620 है जबकि कुल 55692 पुलिसकर्मी हैं। महिला पुलिस कर्मियों के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र में महिला पुलिस का प्रतिशत 14.89 है। चंडीगढ़ में यह 13.48, अंडमान और निकोबार में 10.64, तमिलनाडु में 10.57, हिमाचल प्रदेश में 9.68 और दिल्ली में 7.13 है। दिल्ली में 75169 पुलिसकर्मियों में 5356 महिलाएं हैं।

सरकार ने महिलाओं के ख़िलाफ हिंसा से जुड़े सभी कानूनों को सख्ती से लागू किया है। सरकार ने रेप की हर शिकायत में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के मुताबिक पता चलता है कि अब रेप के ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने महिलाओं की मौजूदा फोन हेल्पलाइन के साथ 'हिम्मत' एप्लिकेशन भी शुरू कर दिया है। इस एप्लिकेशन में एक पावर बटन है जिसे फिक्स टाइमिंग तक दबाए रखने के बाद इलाके की पुलिस फौरन सक्रिय हो जाएगी। दिल्ली पुलिस के अनुसार हिम्मत एप्लिकेशन की खासियत इसकी तेजी है। इसके जरिए शिकायतकर्ता और पुलिस कंट्रोल रूम चंद सेकेंड में एक-दूसरे से जुड़ जाएंगे। इसके बाद पुलिस लोकेशन ट्रैक करके घटना स्थल तक पहुंच जाएगी। यह एप राजधानी में सबसे पहले लॉन्च किया गया।

सरकार महिलाओं की सुरक्षा और विकास के लिए कई सहायक कदम उठा रही है। इसके तहत शहर में अकेली रहने वाली महिलाओं को सस्ते दर पर किराए का घर उपलब्ध कराना, महिला प्रधान घरों के रजिस्ट्रेशन पर 10 प्रतिशत की छूट देना, महिलाओं के नाम पर घर की खरीद होने पर रजिस्ट्रेशन पर छूट देना आदि सरकार की प्राथमिकता सूची में है। यह कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि महिलाओं को जायदाद में समान अधिकार मिले। इन केंद्रों की स्थापना के लिए कई शहरों में जरूरतमंद महिलाओं की पहचान के लिए सर्वे कराया जा रहा है।

देश में बढ़ते रेप के मामलों के देखते हुए महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने रेप पीड़ितों के लिए 660 रेप क्राइसिस सेंटर बनाने का ऐलान किया था। इस सेंटर की खास बात यह है कि इसमें दूर-दराज के इलाकों से आने वाली महिलाओं के लिए कुछ समय तक रुकने की भी व्यवस्था होगी। यहां पर पीड़ित महिला को मनोचिकित्सक, डॉक्टर, वकील और पुलिस की सुविधाएं एक साथ और एक ही जगह पर मिलेंगी। इन केंद्रों पर पीड़ित महिलाएं सभी तरह की शिकायत दर्ज करा सकेंगी। अभी पीड़ित महिला को पहले पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने जाना होता है, फिर मेडिकल चेकअप के लिए कहीं और जाना होता है जिसमें समय भी लगता है और परेशानी भी उठानी पड़ती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार रेप क्राइसिस सेंटर खोलने की योजना बनाई।

हालांकि इस योजना को वित्त मंत्रालय से मंजूरी सिर्फ 36 सेंटर्स खोलने के लिए मिली। पैसे की कमी के चलते अब सिर्फ 36 ऐसे सेंटर खोले जाएंगे।

रेप क्राइसिस सेंटर को खोलने के लिए 'निर्भया फंड' से पैसे खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने दिसंबर 2012 के निर्भया गैंगरेप की घटना के बाद 1,000 करोड़ रुपये की राशि का ये फंड बनाया था। मौजूदा सरकार ने इस बजट (2015-2016) में इस फंड में इतने ही और पैसे डाले हैं। अब तक इस फंड में कुल तीन हज़ार करोड़ रुपये हैं।

देश के 2 करोड़ 70 लाख बच्चों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम भारत में चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सात घातक बीमारियों से बचाव के लिए निशुल्क जीवनरक्षक टीके लगाए जा रहे हैं। इस टीकाकरण को मिशन इंद्रधनुष नाम दिया गया है।

बाल विकास

देश के 2 करोड़ 70 लाख बच्चों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम भारत में चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सात घातक बीमारियों से बचाव के लिए निशुल्क जीवनरक्षक टीके लगाए जा रहे हैं। इस टीकाकरण को मिशन इंद्रधनुष नाम दिया गया है। इस मिशन का उद्देश्य उन बच्चों का 2020 तक टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं या डिप्थेरिया, बलगम, टिटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपिटाइटिस-बी रोकने जैसे सात टीके आंशिक रूप से लगे हैं। यह कार्यक्रम हर साल 5 प्रतिशत या उससे अधिक बच्चों के पूर्ण टीकाकरण में

तेजी से वृद्धि के लिए विशेष अभियानों के जरिए चलाया जाएगा। 300 से अधिक जीवन रक्षक दवाओं को दवा मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाया गया।

अलग-अलग टीकों की पर्याप्त कवरेज होने के बावजूद, भारत की पूर्ण प्रतिरक्षण (Immunisation) कवरेज मात्र 65.2 प्रतिशत बनी हुई है। भारत में लगभग 35 प्रतिशत बच्चों को या तो सारे टीके नहीं लग पाते या एक भी टीका नहीं लग पाता। वर्ष 2009 और 2013 के बीच, लगभग दस लाख और बच्चों को सारे टीके लगाए गए, कवरेज दर में वृद्धि मात्र सालाना एक प्रतिशत रही। आपको बता दें कि प्रतिरक्षा के दायरे से बाहर रहने वाले प्रत्येक बच्चों में मृत्यु का खतरा पूर्णतया प्रतिरक्षित बच्चों की तुलना में लगभग छह गुना अधिक होता है।

बच्चों के लिए साफ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। सरकार ने जवाहर लाल नेहरू की 125वीं जयंती पर 'बाल स्वच्छता मिशन की शुरुआत' की। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ भोजन, खुद को साफ करने, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छ शौचालय को प्रोत्साहन देकर स्कूलों में स्वच्छता सुनिश्चित करना है। यह मिशन महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर को जयंती पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए 'स्वच्छ भारत अभियान' का हिस्सा है। स्वच्छ भारत मिशन सरकार का एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जो कि शहरों और गांवों की सफाई के लिए आरंभ की गई है। इस अभियान में शौचालयों का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, गलियों व सड़कों की सफाई, देश के बुनियादी ढांचे को बदलना आदि शामिल है।

लापता हो रहे बच्चों की बढ़ती संख्या भी चिंताजनक विषय है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, हर साल लगभग 70 हज़ार बच्चे खो जाते हैं। जनवरी, 2012 से लेकर अप्रैल, 2015 तक की अवधि के दौरान पाए गए बच्चों की संख्या 73,597 रहीं। सरकार ने इस दिशा में पहल करते हुए लापता बच्चों की खोज के लिए अब तकनीक का सहारा ले रही है। गुमशुदा बच्चों की खोज के लिए सरकार ने फोटो 'खोया-पाया' वेबसाइट शुरू की है। अब हजारों लोग मिलकर लापता बच्चा ढूंढेंगे और कोई ऐसा भी हो सकता है जो बच्चे का पता बता दे। इसके लिए बस आपको गुमशुदा बच्चे का ब्योरा और फोटो 'खोया-पाया' वेबसाइट पर डालना होगा। इस पोर्टल पर कोई भी नागरिक गुमशुदा या कहीं मिले बच्चे अथवा वयस्क की सूचना अपलोड कर सकता है। इस वेबसाइट को शुरू करने का विचार प्रधानमंत्री का था। पीएम चाहते थे कि डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल गरीबों की मदद के लिए हो और यह पोर्टल विशेष तौर पर गरीबों के गुमशुदा बच्चों को ढूंढ़ने का जरिया बने। सरकार का कहना है कि अमीरों के बच्चे गायब नहीं होते और अगर गुम भी हो जाते हैं तो मिल जाते हैं लेकिन गरीब का बच्चा अगर गुम हो जाता है, तो जल्दी नहीं मिलता। गरीब व्यक्ति कुछ दिन तक अपना बच्चा ढूंढ़ता है और फिर संसाधनों की कमी के चलते चुपचाप बैठ जाता है। यह पोर्टल ऐसे ही लोगों की मदद करेगा। इसका मोबाइल एप्लिकेशन भी डाउनलोड किया जा सकता है।

खोए हुए बच्चों के लिए सरकार की एक और वेबसाइट 'ट्रैक चाइल्ड' भी है जिसमें केवल पुलिस बलों के बीच संवाद होता है। इसमें सिर्फ उन्हीं लापता बच्चों का ब्योरा होता है जिसकी पुलिस में सूचना दी जाती है। 'ट्रैक चाइल्ड' एक सीमित पोर्टल है, जबकि 'खोया पाया' पोर्टल में हर कोई भाग ले सकता है।

खोए हुए बच्चों के लिए सरकार की एक और वेबसाइट 'ट्रैक चाइल्ड' भी है जिसमें केवल पुलिस बलों के बीच संवाद होता है। इसमें सिर्फ उन्हीं लापता बच्चों का ब्योरा होता है जिसकी पुलिस में सूचना दी जाती है। 'ट्रैक चाइल्ड' एक सीमित पोर्टल है, जबकि 'खोया पाया' पोर्टल में हर कोई भाग ले सकता है।

निष्कर्ष

कोई भी सरकार एक साल में सभी मुद्दों को नहीं सुलझा सकती है लेकिन इतने दिन सरकार की मंशा और उसकी तत्परता को आंकने लिए बहुत होते हैं। सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए कदम तो उठाए है लेकिन अभी इन समस्याओं से और सख्ती से निपटने की ज़रूरत है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जुड़े कानून को सख्ती से लागू करने के बाद भी रेप और छेड़खानी पर लगाम नहीं लग पाई है लेकिन लड़कियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं इनका सकारात्मक प्रभाव दिखने लगा है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के बाद हरियाणा में लोगों के बीच जागरूकता इसकी एक मिसाल है। ❑

योजना
आगामी अंक

अगस्त 2015
समेकित विकास और सामाजिक परिवर्तन

जम्मू-कश्मीर दर्पण

दक्षिणी कश्मीर में खुलेंगे विश्वविद्यालय

केंद्र सकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत श्रीनगर और जम्मू के महाविद्यालयों को एक साथ लाकर राज्य उच्च शिक्षा योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में दो विश्वविद्यालय बनाने को मंजूरी दे दी है। इस योजना का लक्ष्य मौजूदा संस्थाओं की क्षमता बढ़ाकर सांस्थानिक आधार बढ़ाना तथा क्षेत्रगत असमानताओं का समाधान करने के लिए नई संस्थाओं की स्थापना के साथ-साथ वंचित क्षेत्रों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।

इस योजना के तहत कठुआ तथा गंदरबल में दो प्रोफेशनल कॉलेजों की स्थापना और शोपियां, गंदरबल और सांबा के मौजूदा कॉलेजों का समुन्नयन किया जाना है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ने जम्मू विश्वविद्यालय तथा कश्मीर विश्वविद्यालय समय 22 संस्थानों को अवसंरचना अनुदान स्वीकृत कर दिया है तथा 20 संस्थानों में उच्चतर शिक्षा को पेशेवर बनाने के लिए सहयोग को भी स्वीकृति दे दी है।

पूर्वोत्तर की झांकी

मणिपुर में खुलेगा खेल विश्वविद्यालय

मणिपुर के थोऊबल में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर के पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केंद्र द्वारा मान्यता प्राप्त होगा।

यह विश्वविद्यालय बीपीएड, एमपीएड के साथ-साथ कोचिंग, फीजियोथेरेपी, फिटनेस, खेल प्रबंधन, खेल पत्रकारिता आदि में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संचालित करेगा। मणिपुर सरकार ने इसके लिए 163 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर ली है। फिलहाल 47 से 49 एकड़ भूमि की और जरूरत होगी। सत्र 2015-16 में यह विश्वविद्यालय इम्फाल के खुमन लंपक स्थित समेकित खेल परिसर से शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

असम में खुलेगा मेगा फूड पार्क

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने असम के नालबाड़ी में पूर्वोत्तर मेघा फूड पार्क स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। इसके जरिए छह हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार तथा 25-30 हजार किसानों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। इससे नालबाड़ी के साथ-साथ आसपास के जिलों में भी किसानों, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमियों और उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचने की उम्मीद है।

मेगा फूड पार्क के लिए 30-35 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश होने की उम्मीद है जिससे 450-500 करोड़ रुपये का वार्षिक टर्न-ओवर लक्षित है।

परियोजना के तहत लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए पूर्णतः सक्रिय औद्योगिक इकाइयों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को औद्योगिक भूखंडों का पट्टा, 10000 मीट्रिक टन क्षमता का शुष्क भंडारगृह, 3000 मीट्रिक टन क्षमता वाला कोल्ड स्टोरेज, साझा उपचार संयंत्र तथा गुणवत्ता नियंत्रक प्रयोगशालाएं आदि सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की योजना है।

सांस्कृतिक राजनय: दिलो-दिमाग को जोड़ने का मंत्र

नई परिस्थितियों में सांस्कृतिक राजनय और आम नागरिकों के बीच आपसी संपर्क ही आने वाले वर्षों में भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों की दिशा तय करेंगे। हाल में प्रधानमंत्री के चीन दौरे ने लोगों के आपसी संपर्क के माध्यम से रिश्तों को मजबूत करने और साझेदारी को आगे ले जाने की दिशा में पहल की है। चीन में योग और ताई ची के संयुक्त अभ्यास ने एक बार फिर यह साबित किया है कि यदि दोनों देश अपनी सांस्कृतिक विरासत के जरिए एक-दूसरे से जुड़ते हैं, तो राजनीतिक संबंधों को तय करने के लिए बेहतर माहौल तैयार हो सकेगा।

15 मई को उस वक्त बेहद ऊर्जावान माहौल था, जब बीजिंग के टेंपल ऑफ हेवन यानी स्वर्ग मंदिर में दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में चीनी बच्चों ने योग किया और भारतीय बच्चे ताई ची का प्रदर्शन करते दिखे। इस मौके पर खासे उत्साहित चीनी प्रधानमंत्री ली कचियांग ने कहा, 'मैं प्रधानमंत्री मोदी की ओर से इस तरह के कार्यक्रम की कल्पना की सराहना करता हूं। यह स्वर्ग का मंदिर है और स्वर्ग में पहुंचने के लिए शरीर और दिमाग के संतुलन की आवश्यकता होती है। योग एक ऐसी कला है, जो शरीर और दिमाग के बीच संतुलन स्थापित करता है। आज के दौर में निराशा और गुस्से का माहौल दुनिया के बड़े हिस्से में है और योग इस समस्या से निपटने का बेहतरीन तरीका है। वहीं, भारतीय प्रधानमंत्री ने योग को दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्तों की संभावित कड़ी करार देते हुए कहा, 'यह अद्भुत संयोग है कि चीनी बच्चों ने जहां योग का प्रदर्शन किया, वहीं, भारत के बच्चे ताई ची कर रहे हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने के लिए यह बेहतरीन माध्यम हो सकते हैं। हमें इसे आगे ले जाना होगा।

इस दौरे में सांस्कृतिक माध्यमों से भारत और चीन के रिश्तों को नई ऊर्जा मिलती दिखी। दोनों देशों के बीच हुए समझौतों में शंघाई की फुडान यूनिवर्सिटी में गांधी एवं भारतीय अध्ययन केंद्र की स्थापना पर भी सहमति बनी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच एक थिंक टैंक फोरम, उच्च स्तरीय मीडिया फोरम, कुनमिंग में योग कॉलेज की स्थापना और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद एवं युन्नान नेशनल यूनिवर्सिटी के बीच योग कॉलेज की स्थापना के लिए सहयोग पर सहमति बनी।

इसके अलावा भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के नए रूट को लेकर सहमति बनना खुशी की बात रही। दोनों देशों ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से इस यात्रा के मार्ग को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले तीर्थयात्री उत्तराखंड से गुजरने वाले लिपुलेख दर्रे वाले मार्ग से यात्रा करते रहे हैं। लेकिन नाथुला दर्रे से गुजरने वाला रास्ता काफी आसान है, जहां बुजुर्ग भी आसानी से यात्रा कर सकते हैं। इस मार्ग से कैलाश मानसरोवर जाने पर समय की भी बचत होगी।

इसके अलावा प्रधानमंत्री ने दोनो देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चीनी पर्यटकों को ई-वीजा की सुविधा दिए जाने का भी ऐलान किया। इस फैसले का बीजिंग की शिंघुआ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जोरदार स्वागत किया। यहां तक कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भी इसे उपहार की संज्ञा दी। यही नहीं दोनों देशों ने 2015 को भारत के चीन जाने और 2016 को चीन के भारत आने का वर्ष घोषित किया। इसके अलावा फिल्म निर्माण के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहमति भी एक महत्वपूर्ण कदम है। चीन में थ्री इडियट्स और पीके जैसी भारतीय फिल्मों की अपार लोकप्रियता ने इस क्षेत्र में असीम संभावनाओं को साबित भी किया है। दोनों देशों की समृद्ध संस्कृति निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में एशिया की दो उभरती शक्तियों के बीच बेहतर रिश्ते स्थापित होने की अहम वजह होगी। ❑

एलईडी से जगमगाएगा वाराणसी

ऊर्जा की बचत को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी में डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम और एलईडी आधारित स्मार्ट स्ट्रीट लाइट प्रोग्राम को शुरु किया गया है। इन दोनों योजनाओं के तहत सरकार का लक्ष्य पीक आवर्स में ऊर्जा की खपत में 10,000 मेगावाट तक की कमी करना है। इसी योजना के तहत केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेस लिमिटेड (ईईएसएल) के साथ मिलकर वाराणसी में 2,28,496 उपभोक्ताओं को 13 लाख एलईडी बल्बों का वितरण करेंगी और सड़कों की 36,077 पारंपरिक लाइटों को एलईडी लाइटों में बदला जाएगा।

कम बिजली की खपत करने वाली एलईडी लाइटें लगाए जाने से वाराणसी में बिजली की मांग में 45 मेगावाट तक की कमी आएगी, जिससे 68 करोड़ रूपये तक की बचत होगी। पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को एलईडी लाइटों में तब्दील करने से बड़े पैमाने पर बचत होगी, लेकिन इस दिशा में स्थानीय निकायों की ओर से भी निवेश किए जाने की आवश्यकता है। इन लाइटों से पीक ऑवर्स में बिजली की खपत तो कम की ही जा सकेगी, बल्कि रोशनी की गुणवत्ता में भी खासा सुधार हो सकेगा।

ईईएसएल जो बिजली मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक कंपनी है, यह अपने खर्च पर पूरे शहर में सड़कों पर लगी लाइटों को स्मार्ट एलईडी लाइटों से बदलेगी। पांच से सात साल के भीतर अगर एलईडी में कोई समस्या आती है तो कंपनी की जिम्मेदारी होगी। आने वाले पांच से सात सालों में निकाय एएलईडी लाइटें लगाए जाने से होने वाली बिजली की बचत की राशि को परिचालन लागत और ईईएसएल की रकम लौटाने में खर्च कर सकेंगी। निकायों को यह लाइटें फ्री रख-रखाव एवं बदलाव की सुविधा के साथ दी जाएंगी। जिससे निकायों को इस मद में बहुत अधिक पूंजी खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे निकायों को यह सुविधा मिल सकेगी कि वह पूरे शहर में एएलईडी लाइटें बिना किसी खर्च के लगा सकेंगे और भविष्य में भी किसी तरह के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता नहीं होगी।

ईईएसएल पूरे वाराणसी में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के साथ मिलकर डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम का संचालन करेगा। इस प्रोग्राम के तहत पूरे शहर में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 13 लाख बल्ब वितरित किए जाएंगे। इस योजना के तहत दो किलोवॉट और उससे कम वॉट मीटर वाले उपभोक्ताओं को सिर्फ 10 रुपये की शुरुआती कीमत पर सात वॉट के पांच बल्ब दिए जाएंगे। जबकि 11 महीने के बाद प्रति बल्ब 110 रूपये बिजली बिल के साथ ही लिए जाएंगे। इसके अलावा घरेलू उपभोक्ता तीन साल की रिप्लेसमेंट वॉरंटी के साथ सिर्फ 120 रुपये की कीमत पर बल्ब खरीद सकेंगे। आसान किस्तों में एलईडी लेना हो तो 10 रुपये भुगतान कर शेष रकम 11 किस्तों में देनी होगी। जिनकी बाजार में कीमत 350 से 600 रुपये तक के बीच है। अनुमान के मुताबिक हर उपभोक्ता प्रति बल्ब एक साल में 162 रुपये की बिजली की बचत कर सकेंगे। ऐसे में आने वाले समय में सड़कों की लाइटों एवं घरों में लाइटों पर बिजली की खपत में उल्लेखनीय कमी आएगी। इससे प्रत्येक परिवार को चौबीसों घंटे व सातों दिन बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलने की संभावना है।

खसरा से बचाव में मदद करेगा नीदरलैंड

खसरा (मीजल्स) और रूबेला जैसी बच्चों की घातक बीमारी से बचाव के लिए टीका तैयार करने के मकसद से भारत और नीदरलैंड ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भारत सरकार के *मेक इन इंडिया* अभियान के तहत किए गए हैं। इस समझौते के बाद जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आने वाली केंद्रीय कंपनी भारत इम्युनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के चोला स्थित अपनी इकाई में खसरा (मीजल्स) और रूबेला से निपटने के लिए वैक्सीन तैयार करने का काम शुरू करने वाली है। इस काम में नीदरलैंड का सरकारी संस्थान यूपी ट्रांसलेशनल वैक्सीनोलाजी (एनटीआरएवीएसीसी) इसके लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा। इस समझौते के तहत अन्य वैक्सीनों को तैयार करने की दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे। एनटीआरएवीएसीसी नीदरलैंड के स्वास्थ्य, वेलफेयर एवं खेल मंत्रालय के अधीन काम करता है। इस संस्थान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीका तैयार करने को लेकर पहचान है और तकनीक के विनिमय का इसका लंबा इतिहास रहा है। जबकि बुलंदशहर की भारत इम्युनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत काम करती है। यह विभाग केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है।

केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया अभियान के तहत कंपनी ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से इस करार में सफलता पाई है। अब संस्थान को वैक्सीन तैयार करने के लिए पर्याप्त तकनीक हासिल हो सकेगी। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री श्री मार्के रूटे की भारत यात्रा के दौरान इस करार पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मामलों के मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने इस सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि इससे खसरा तथा रूबेला और अन्य जरूरतमंद वैक्सीनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव होगा तथा हजारों बच्चों की जान बचाई जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि देश में पोलियो उन्मूलन के बाद अब सरकार का ध्यान खसरा तथा रूबेला जैसी बीमारियों के नियंत्रण/उन्मूलन पर होगा, जिन्हें टीकों के जरिए रोका जा सकता है। ❑

प्रकाशक व मुद्रक: डॉ. साधना राउत, अपर महानिदेशक द्वारा प्रकाशन विभाग के लिए ब्रजबासी आर्ट प्रेस लिमिटेड, ई-46/11, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-2, नयी दिल्ली-110020 से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक: ऋतेश पाठक

रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2015-17
Reg.No. D.L.-05/3231/2015-17 at RMS, Delhi
23 जून, 2015 को प्रकाशित • 29-30 जून, 2015 को डाक द्वारा जारी

Licenced under U (DN)-55/2015-17
आर.एन.आई. 951/57
R.N.I. 951/57

बाजार में उपलब्ध

नवीन संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण 2015

संघ एवं राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन हेतु अत्यन्त लाभदायक सामग्री.
विभिन्न विश्वविद्यालयों के भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न-पत्र एवं अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी.

Code No. 791
₹ 315/-

Code No. 790
₹ 350/-

टॉपर्स की राय में...

- .....प्रतियोगिता दर्पण के अर्थशास्त्र व राजव्यवस्था अतिरिक्तांक काफी अच्छे लगे. —संतोष कुमार राय
  सिविल सेवा परीक्षा, 2013 में हिन्दी माध्यम से प्रथम स्थान पर चयनित
- .....मैंने प्रतियोगिता दर्पण का उपयोग किया और विशेषतः इसके अर्थव्यवस्था वाले भाग से तैयारी में मुझे बहुत मदद मिली. —मेधा रूपम
  सिविल सेवा परीक्षा, 2013 में 10वें स्थान पर चयनित
- मैंने अर्थव्यवस्था के अतिरिक्तांक का उपयोग समय के सदुपयोग के लिए किया. —प्रियंका निरंजन
  सिविल सेवा परीक्षा, 2012 में हिन्दी माध्यम से द्वितीय स्थान
- प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक प्रतियोगियों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं. विशेषतः अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक अत्यंत लाभकारी है. —नागेन्द्र नाथ यादव
  उ.प्र. पी.सी.एस. परीक्षा, 2013 में द्वितीय स्थान
- मैंने प्रतियोगिता दर्पण के अर्थव्यवस्था एवं सामान्य विज्ञान के अतिरिक्तांकों का अध्ययन किया है, जो तैयारी के दौरान काफी उपयोगी रहे. —दिनेश मिश्रा
  उ.प्र. पी.सी.एस. परीक्षा, 2012 में हिन्दी माध्यम से प्रथम स्थान

मुख्य आकर्षण

✸ भारतीय अर्थव्यवस्था–प्रमुख विशेषताएँ ✸ राष्ट्रीय आय के नवीन आँकड़े (आधार वर्ष 2011-12) ✸ जनांकिकी परिदृश्य एवं जनगणना 2011 ✸ कृषि, उद्योग, बैंकिंग, विदेशी व्यापार एवं यातायात ✸ नई विदेश व्यापार नीति : 2015-20 ✸ गरीबी पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट (2014) ✸ भारत पर विदेशी ऋण (दिसम्बर 2014) ✸ मौद्रिक नीति (7 अप्रैल, 2015) ✸ प्रमुख रोजगारपरक एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ✸ नीति आयोग एवं पंचवर्षीय योजनाएं ✸ आर्थिक समीक्षा 2014-15 ✸ केन्द्रीय एवं रेलवे बजट 2015-16 ✸ प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ✸ आर्थिक शब्दावली ✸ नवीनतम आर्थिक तथ्यों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

अपने निकटतम पुस्तक विक्रेता से अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें

प्रतियोगिता दर्पण
2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा-282 002 फोन : (0562) 4053333, 2530966; फैक्स : (0562) 4053330
• E-mail : care@pdgroup.in • Website : www.pdgroup.in
• नई दिल्ली 23251844/66 • हैदराबाद 66753330 • पटना 2673340 • कोलकाता 25551510 • लखनऊ 4109080

YH-75/2015